हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 सितम्बर, 1982

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 21 सितम्बर, 1982

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों को लिखित उत्तर	(2)24
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)30
वैयक्तिक स्पश्टीकरण	
श्री प्यारा सिंह द्वारा	(2)31
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(2)31
ध्यानाकर्शण सूचनाः–	
पानीपत बाईपास बनाने तथा बढ रहे यातायात को विनियमित करने सम्बन्धी	(2)36
वक्तव्यः–	
लोक निर्माण राज्य मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना सम्बन्धी	(2)36

ध्यानाकर्शण सूचनाः–	
चण्डीगढ पंजाब को हस्तांतरित करने सम्बन्धी	(2)38
वक्तव्यः–	
मुख्यमंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना सम्बन्धी	(2)39
स्पश्टीकरणः–	
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस कर्मचारियों को निकाले जाने सम्बन्धी	(2)45
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(2)47
संविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक 1982 के अनुसमर्थन सम्बन्धी संकल्प	(2)47
वर्श 1982–83 के सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेटस (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान–	
1. राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय में अनुमानों पर चर्चा	(2)57
2. अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)57
दि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982	(2)65

बैठक का समय बढाना	(2)70
दि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982 (पुनरराम्भ)	(2)70
वैयक्तिक स्पश्टीकरणः–	
आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा	(2)81
दि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982 (पुनरराम्भ)	(2)81
बैठक का समय बढाना	(2)86
दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट) सैंकिड अमैंडमैंट बिल 1982	(2)86

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। उपाध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब कन्वै चन्ज होंगे।

Construction of S.Y.L. Canal

***5 Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the latest figures of the total amount deposited by the Haryana Government with the Punjab Government for the construction of S.Y.L. Canal;

(b) whether the Punjab Government propose to get the digging work done departmentally; if not, whether any tenders have been invited by Punjab Government for the purpose; and

(c) the time by which the digging work on the said canal is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Total amount deposited is Rs. 15.30 crores.

(b) Presently the tenders are being invited for digging work from time to time. Available machinery with Punjab and Haryana is also being deployed to work departmentally as an additional measure.

(c) As per inter-state agreement signed on 31-12-1981; the work is scheduled to be completed within 2 years from the date of the agreement.

डा0 मंगल सैनः क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह 15.50 करोड रूपया कब कब दिया गया और किस किस मद के लिए दिया गया तथा उन्होंने इस रूपये का इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, एक करोड रूपया तो भाुरू में दिया गया था जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। 7 करोड के करीब रूपया अभी दो तीन हफते पहले दिया गया है। इससे दो तीन महीने पहले बाकी का रूपया दिया गया था। यह रूपया लैंड ऐक्विजि ान स्टाफ जो इन्होंने रखा हुआ है तथा इस काम से सम्बन्धित दूसरे जो काम है उनके लिए दिया गया है।

श्री बीरेंद्र सिंहः क्या मंत्री जी बताएंगे कि कितने किलोमीटर लैंग्थ की जमीन जब तक ऐक्वायर की जा चुकी हैं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अभी तक 3500 एकड जमीन की ऐक्विजि ान के लिए सैक ान 4.17 और सैक ान 6 की नोटिफिके ान हो चुकी है और अवार्ड अनांउस होना बाकी है।

डा0 मंगल सैनः क्या मंत्री जी बताएंगे कि श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने जब इस नहर की खुदाई का उदघाटन किया था तब से लेकर अब तक कितनी लम्बाई की जमीन की खुदाई हुई है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने जहां डिगिंग के काम का इनआगुररे ान किया था वह कोई 5 किलोमीटर की रीच है। बाकी जो जमीन है उसकी ऐक्विजि ान की प्रोसीडिंगज बाद में भाुरू की गई है। जैसा मैंने पहले कहा लगभग 3500 एकड जमीन को ऐक्वायर करने की प्रोसीडिंगज फाईनल स्टेज पर है। उसका अवार्ड किसी मोमैंट भी अनांउस हो सकता है।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो लैंड एक्वायर करने का प्रोसैस है वह पूरी तरह खत्म हो चुका है या अभी तक केवल दफा 4 और 6 के नोटिस ही जारी हुए है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, लैंड ऐक्विजि ान के सारे नोटिफीके ान्ज हो चुके हैं। अब तो सिर्फ अवार्ड अनांउस होना रहता है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस स्पीड पर काम चल रहा है वह काफी निरा ाजनक मालूम होता है। क्या मंत्री जी को आ ाा है कि यदि इसी स्पीड पर काम चलता रहे तो वह निर्धारित समय पर खत्म हो जाएगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, निरा ाा तो इनके अपने मन की देन है क्योंकि इन्होंने अपने समय मे सिवाए निरा ाा प्राप्त करने के और कुछ नहीं किया। इस सरकार को तो पूरी आ ाा है कि निर्धारित समय के अन्दर यह काम जरूर पूरा होगा।

चौधरी देवी लालः अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते है कि चौधरी भजनलाल जी स्टोन्ज रखने में काफी ऐक्सपर्ट हैं। हरियाणा के हिस्से का पानी कई सालों से हमें नहीं मिल रहा है। इस वक्त हरियाणा में कहत पडा हुआ है। क्या ये बताएंगे कि उस पानी को लेने के लिए यह डिमांड रखेंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके और उनका भला हो सके?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवाल को अच्छी तरह समझ नहीं सका लेकिन बात यह है कि जब यह लहर बनेंगी तभी पानी आएगा। इसके लिए इस समय डिमांड रखने की कोई बात नहीं है। हमें नहर के निर्धारित समय में पूरा होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि ऐमरजेन्सी क्लाज के अन्दर लैंड ऐक्वायर की जा रही है। (विघ्न)

चौधरी देवी लालः अध्यक्ष महोदय, यह पानी तो बहुत सालों से पडा है। अपने हिस्से की नहर भी तैयार पडी है। पंजाब एरिया में नहर कुछेक कारणों से जिनका जिक्र अभी मंत्री जी ने किया तैयार नहीं हो सकी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज जबकि हरियाणा मे कहत पडा हुआ है उससे लोगों को बचाने के लिए क्या ये अपने हिस्से के पानी को पंजाब से लेने की डिंमाड करेंगे?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐग्जिस्टिंग चैनल्ज की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी उनमें आ रहा है। (विघ्न)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इन्हें यही बात बताने वाला था कि नरवाना ब्रांच और भाखडा मेन लाईन आदि की जितनी कैपेसिटी है उतना पूरा पानी अपने भोयर का हम ले रहे है और वह पानी उनमें आ रहा है।

चौधरी देवी लालः अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात है तो इस नहर पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? (विघ्न)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को थोडा क्लीयर कर देता हूं क्योंकि चौधरी साहब इसको कंफयूज कर रहे हैं। हमारा भोयर 3.5 एमएएफ है। इस भोयर में से अब भी जो हमारी मौजूदा चैनल्ज है जैसे नरवाना ब्रांच और भाखडा मेन लाईन उसके द्वारा जितना पानी उनकी नौर्मल कैपेसिटी से फालतू हम ला सकते हैं ला रहे है। बाकी

पानी को लाने के लिए यह चैनल बनाने जा रहे है और इसके लिए यह सारी कार्यवाही की जा रही है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, सोनीपत और रोहतक में 40 फीसदी पानी की कट है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि एस0वाई0एल0 बनने से सोनीपत और रोहतक को कोई फायदा पहुंचेगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस नहर के बनने से प्राईमैरिली तो जवाहरलाल नेहरू कैनाल और दूसरी कैनाल के द्वारा रूरल एरियाज को पानी मिलेगा लेकिन दूसरे एरियाज में भी चाहे वे जमुना के हैं या भाखडज्ञ के हैं उनमें भी वाटर अलांउस बढने से पूरा पूरा फायदा होगा।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस नहर की खुदाई को जल्दी करवाने के लिए हमारे इरीगे ान डिपार्टमैंट के स्टाफ को भी ऐसा ि ाएट किया जाएगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो ऐग्रीमैंट हुआ है उसके तहत गवर्नमैंट आफ इंडिया के लैवल पर एक मौनिटरिंग कमेटी बनी हुई है वाटर कमी ान के चेयरमैन उसके चेयरमैन है। हरियाणा और पंजाब के औफिसर्ज भी उस कमेटी की मीटिंग में भाग लेते है। इसके अलावा एक और कमेटी सैन्ट्रल गवर्नमैंट के इरीगे ान मुहकमें के सैकेटरी की अध्यक्षता में

बनी हुई है जो बाकी प्रोगैस और पालिसी मैटर्ज को रिव्यू कर सकती है।

श्रीमति चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वै चन के पार्ट (सी) का जवाब इन्होंने ठीक तरह से नहीं दिया है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि अन्तर राज्य ऐग्रीमैंट के अनुसार समझौते की तिथि से दो साल में यह कैनाल बनकर पूरी होनी है। (विघ्न) इसमें मार्जिनल ओवरलैपिंग हो सकती है परन्तु हमारी पूरी कोि ा ा है कि ि ाडयूड टाईम पर ही यह नहर बनकर तैयार हो जाए।

डा0 मंगल सैनः क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस नहर को खोदने के खिलाफ अकालियों ने जो मोर्चा लगा रखा है उसकी वजह से इस नहर को खोदने में काफी बाधा पडी है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा सरकार को पता है वह मोर्चा फिजल आउट हो चुका है और वहां अब इस वक्त कोई बाधा नहीं है।

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितनी लैंग्थ की जमीन की ऐक्विजि ान हो चुकी है और उसमें से कितनी जमीन की खुदाई हो चुकी है?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब पहले आ चुका है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लैंग्थ नहीं बताई है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जब कभी कोई जमीन ऐक्वायर होती है चाहे वह नहर के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, वह किलोमीटर में ऐक्वायर नहीं होती बल्कि एकड के हिसाब से ऐक्वायर होती है। फिर भी यह जरूरी नहीं कि जो जमीन ऐक्वायर हुई है उसकी कंटिगियूटी हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 3500 एकड जीमन की ऐक्विजि ान की प्रोसीडिंगज लगभग कम्पलीट हो चुकी है और 2200 एकड जमीन की ऐक्विजि ान अन्डर प्रोसैस है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह कैनाल 108 किलोमीटर लम्बी बनेगी। टोटल रकबा 8000 एकड ऐक्वायर होगा। इसमें से 3500 एकड रकबा ऐक्वायर हो चुका है। पांच किलोमीटर का रकबा जो पहले ही ऐक्वायर किया हुआ था उस पर पिछले चार महीने से काम चालू है। लगभग चार लाख फुट मिटटी वहां से खोद कर निकाल दी गई है। अगर माननीय सदस्य मौके पर जाना चाहें तो जा सकते है और इस सारे काम को देख सकते है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, हाउस के आल पार्टीज मैम्बरान को वहां परप भिजवाने का कश्ट करें जहां पर नहर की खुदाई हो रही है।

श्री अध्यक्षः यह बात जरूर कंसीडर करेंगे।

श्री हरि चन्द हुडडाः स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पानी भाई चारे से नहीं आ सकता? (हंसी) पहले आप कोर्ट में गये और फिर इंदिरा गांधी जी ने समझौता करवा दिया। आप बि ानोई जाट है और उधर अकाली जाट हैं इसलिये आप इसका फैसला भाई चारे से कर लें ताकि हरियाणा के एरिया में जल्दी से पानी मिल सकें। (विघ्न)

चौधरी देवी लालः सुरजेवाला साहब के कहने के मुताबिक तो मैंने ही जून में एक करोड रूपया दिया था। उसके नक ो कदम पर चल कर ही तो आपने फाउन्डे ान स्टौन रखवाया है लेकिन आप अभी तक यह नहीं बता रहे हो कि कितनी खुदाई हो चुकी है।

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

***61. Chaudhri Sahab Siingh Saini:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of murder cases registered in Pehowa constituency of district Kurukshetra during the period from 25-05-82 to 15-8-82 together with the number of such cases registered during the corresponding period in the years 1977 to 1981, separately.

(b) whether any of the murder cases, as referred to in part (a) above were politically motivated; if so the details of such cases; and

(c) whether any complaints in regard to the cases, as referred to in part (b) above, have also been received by the Government, if so, the action taken thereon?

मुख्यमंत्रीः (क) मांगी गई सूचना नीचे दी जाती हैः–

पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के हत्या के दर्ज किये गये मुकदमों की संख्या।

25–5–82 से 15–8–82	25–5–81 से 15–8–81	25–5–80 से 15–8–80	25–5–79 से 15–8–79	25–5–78 से 15–8–78	25–5–77 से 15–8–77
5	2	3	1	–	–

(क) नहीं।

(क) प्र न ही नहीं उठता।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, 25–5–79 से 15–8–79 तक एक कत्ल का केस दर्ज हुआ, 25–5–80 से 15–8–80 तक तीन हुए, 25–5–81 से 15–8–81 तक दो हुए और 25–5–82 से 15–8–82 तक 5 कत्ल हुए क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कत्लों में यह बढौतरी क्यों हुई? क्या इसके पीछे राजनैतिक कारण तो नही है जिसकी वजह से कत्लों की तादाद बढती जा रही है?

चौधरी भजन लालः इसमें राजनैतिक कारण नहीं है। आप जानते है कि ज्यादातर झगडे जमीन की वजह से होते है। किसानों का ज्यादा ताल्लुक जमीन से है इसलिए इसी बात को लेकर वहां ज्यादा झगडे होते हैं। अगर एक बट पर भी झगडा हो जाये तो कत्ल हो जाता है जो भी पांच कत्ल हुए है उन सभी के मुलजिम पकडे गये है। तीन केसिज का अदालत में चालान हो चुका है बाकि केसिज के मुसजमान तो पकडे गये हैं लेकिन उनके चालान अदालत में पे ा नहीं किये गये। वे भी बहुत जल्दी अदालत में भेज दिये जायेंगे।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या यह फैक्ट है कि उस एरिया में चौदह कत्ल हुए है और उन कत्लों में एक पोलिटि ायन और एक एसएचओ का हाथ है।

चौधरी भजन लालः केवल पांच कत्ल के केसिज हुए है और सभी के मुलजमान को पकड लिया गया है।

श्रीमति चन्द्रावतीः हमें तो वहां के लोकल लोगों ने बताया है कि 14 कत्ल हुए है। अगर नहीं हुए है तो चीफ मिनिस्टर साहब पोजी ान कलियर कर दें।

चौधरी भजन लालः बहिन जी, आप तो बहुत पुरानी मैम्बर है। आपको पता हे कि जब भी कोई कत्ल होता है तो मुकदमा दर्ज होता है। यहां पर सवाल पेहवा हल्के के बारे में पूछा गया है। सारी स्टेट और जिले की बात नहीं है। पेहवा असैम्बली

हलके में पांच मुकदमें दर्ज हुए है। पांचों कत्ल के मुसजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 34 मुसजमान है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन केसिज के चालान पे ा हो चुके है। दो केसिज के चालान बहुत जल्दी अदालत में जाने वाले है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में बताया है कि पांच केसिज कत्ल के हुए और सभी के मुकदमें दर्ज हुए है। उन्होंने सही और असल फिगर्ज नहीं दी है। 14 कत्ल हुए है। पांच को केवल कत्ल दिखाया है और बाकी को सुसाइड दिखाया गया है। उनके परचे ही दर्ज नहीं किए इसलिए असल बात को छुपाया जा रहा है। चुनाव के बाद एक पोलिटि ियन और एसएचओ की वजह से कत्ल हुए लेकिन उनके पर्चे खुर्द बुर्द कर दिये गये। दरअसल कत्ल 14 हुए है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल निराधार और गलत है। जिस बात के कोई सिर पैर न हो उसे हाउस में कहने का कोई लाभ नहीं। आज तक किसी भी महानुभाव ने सरकार के नोटिस में यह बात नहीं लायी कि फलां जगह परप इतने कत्ल हुए है या इतने आदमी मारे गये है। इन्होंने यह बात कभी भी लिखकर नहीं दी कि वहां पर इतने कत्ल हुए है। मैं सदन के यह आ वासन देना चाहता हूं कि चाहे छोटा सा भी केस हो वहां पर केस दर्ज करके जांच कराते है। जांच करने के बाद जो भी व्यक्ति दोशी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं और बेगुनाह के खिलाफ कार्यवाही करने का

सवाल नही पैदा नहीं होता। किसी भी सियासी आदमी की वजह से कोई भी कत्ल नहीं हुआ है। जब आप (वीरेंद्र सिंह) होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय भी जमीन के काफी झगडे थे। आप सरकार के नोटिस में लाये। अगर हम एक ान न लें तो आप कहें।

चौधरी देवी लालः सिरसा में कत्ल हुआ लेकिन आपने उसे खुदक ाी साबित किया है। यह सब आपकी मेहरबानी से हुआ है?

राव निहाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं जब आप उस कांस्टिचुऐंसी से एमएलए थे तब वहां कोई कत्ल नहीं हुआ। क्या आप बताएंगे कि आपने उस समय कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से कत्ल नहीं हुए?

Mr. Speaker: You can put the question to the Government.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से कैटेगरीकली जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गुमथला में अप्रैल 1982 में कत्ल हुआ, फिर इसी गांव में बीस दिन के बाद कत्ल हुआ। बाखली गांव में भी अप्रैल 1982 में दो कत्ल हुए। करासाहब में जून के महीने में दो व्यक्ति कत्ल हुए और तीसरे व्यक्ति को कत्ल करने का प्रयास किया। नोच गांव में एक व्यक्ति कत्ल हुआ लेकिन पुलिस अभी तक उसकी पूरी इन्क्वायरी

नहीं कर पायी लेकिन मैडिकल रिपोर्ट में कत्ल किया हुआ साबित हुआ। पेहवा में मई में एक सुनार का कत्ल हुआ, अगस्त में लुहार माजरे में कत्ल हुआ। कया मुख्यमंत्री जी इन कत्ल हुए व्यक्तियों के परिवारों से मिले हैं? क्या यह बात सच है कि वहां उस एरिया का एक पुलिस अधिकारी एक पोलिटि ियन से मिल कर यह साजि ा करवाता रहा और कोई ऐक ान नहीं हो सका?

चौधरी भजन लालः यह बात बिल्कुल निराधार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी सियासी आदमी ने सरकार पर दबाव नहीं डाला है कि मुलजमान को न पकडा जाये। जिन मुलजमान के नाम एफआईआर में दर्ज है। वे सारे के सारे गिरफ्तार हो चुके हैं।

चौधरी साहब सिंह सैनीः क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस इन्सपैक्टर ने यह कार्य किया है उसे बाद में प्रोमोट किया गया और उसी जिले में डीएसपी लगाया है।

चौधरी भजन लालः इन्सपैक्टर से अगर डीएसपी लगाया है तो उसकी प्रोमो ान डयू होगी। अगर कोई कत्ल होता है और उसमें एसएचओ कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उसके खिलाफ ऐक ान लिया जायेगा लेकिन अगर एसएचओ की कोई बदनीयती नहीं है और वह मुलजमान को गिरफ्तार करता है तो उसकी प्रोमो ान रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, उस एसएचओ को इसलिये प्रोमोट किया गया है ताकि मामले को ह ा अप किया जा सके और दबाया जा सके। क्या इस बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे? (व्यवधान व ाोर)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो डाटा इस सवाल के जवाब में दिया है इससे पता चलता है कि 1977–78 में और 1978–79 में कोई कत्ल का केस रजिस्टर नहीं हुआ है। उसके बाद हर साल इस बारे में प्रगति हुई है यानि कत्ल के मुकदमें बढते चले गये है। क्या मुख्यमंत्री जी यह बतायेंगे कि वह मुकदमें क्यों बढते चले गये हैं और इनके कारणों की क्या कोई जांच की गयी है कि ऐसा क्यों हुआ है अगर नहीं की गयी है तो भविश्य में क्या इस बात की जांच करने की कोि ा ा की जायेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहले तो डाक्टर साहब ने यह कहा हे कि उस एसएचओ को स्पै ली प्रोमोट करके इन्सपैक्टर बना दिया गया है। यह बिल्कुल गलत बात है किसी को भी स्पे ाली इन्सपैक्टर नहीं बनाया गया है। जो जिसका हक बनाता था उसी हिसाब से सिनियोरिटी के हिसाब से उसको प्रोमोट किया गया है। यह सरकार प्रोमो ान के मामले में किसी के साथ ज्यादती नहीं करती और न ही किसी को जान–बुझकर अन्याय से डिमोट किया गया है। इस बारे में जो इन्होंने कहा है कि उसको स्पे ाली इन्सपैक्टर प्रोमोट किया गया है। मैं इस बारे

में पता करूंगा लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रोमो ान के मामले में किसी के साथ किसी किस्म की रियायत बरतने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसका हक बनता है उसके उसका हक दिया जाता है। जहां तक कत्ल के मुकदमें कयों बढ रहे है इसका सवाल है अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है कुरूक्षेत्र जिले में जमीनों के बारे में बडा भारी झगडा है। वहां पर कुछ बंजर जमीनें 1952 में सरदार प्रताप सिंह कैरों जब मुख्यमंत्री होते थे उस समय 20–20 साल के पटटे पर दी गयी थी। उनके 20 साल 1972 में पूरे हो गये है। इसके बाद जो मालिक है वे अपनी जमीनों का कब्जा लेने की कोि ा ा कर रहे है। जिन लोगों के पास उनका कब्जा है वे सुप्रीम कोर्ट में चले गये। सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी इस बारे में है। इसलिये हम इस बारे में कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद हमने एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है। ताकि इस बारे में कोई न कोई रास्ता निकाला जाये जिससे वहां पर भाान्ति रह सके। हम यह चाहते है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाये जिससे मालिकों और मुजारों का फैसला हो जाये तथा वहां पर हालत ठीक हो जायें। वह सब–कमेटी जल्दी ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच कर कोई न कोई सुझाव देगी जिनको अगर दोनों पार्टीज मान लेंगी तो हालात वहां पर ठीक हो जायेंगे।

श्री प्यारा सिंहः मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैं आपको पर्सनल एक्सलेने ान देने के लिए क्वै चन आवर के बाद कुछ समय दूंगा।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 कत्ल हुए है लेकिन डा0 मंगल सैन ने 9 गांवों के और 9 आदमियों के नाम गिनाये है। जिनके कत्ल हुए है। इन्होंने इस के बावजूद उस एसएचओ की प्रोमोअ कर दिया है। सवाल यह है कि अगर उसको प्रोमोअ किया है तो क्यों किया गया है? जिस राज में ऐसी हालत हो वहां आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं क्या होगा? (विघ्न) जहां पर ये 5 कत्ल बता रहे हैं वहां पर ही डाक्टर मंगल सैन जी ने 9 आदमियों के कत्ल गिनायें है। फिर उस एसएचओ को प्रोमोट भी कर दिया गया है। उसको जो स्प ैली प्रोमोट किया गया है इसका कारण बतायेंगे?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, किसी को कोई स्पै ाल प्रोमो ान नहीं दी गयी है। जैसे मैंने कहा है कि अगर उसको प्रोमोट किया गया होगा तो उसको उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से और उसके हम के हिसाब से प्रोमोट किया गया होगा। मैं तो आन ओथ यह बात कहने के लिये तैयार हूं कि मैं उसका नाम तक भी नहीं जानता। (व्यवधान व ाोर)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 25–5–1982 से 15–8–1982 तक 5 कत्ल के केसिज पेहोवा में हुए है। स्पीकर साहब, जब से

इनके पास यह महकमा आया है तब से इस हलके में एक ही गांव गुमथला में 20 तारीख को 2 कत्ल हुए हैं । क्या यह उस एसएचओ की इन–एफीि ायैन्सी नहीं है और इस सब के बावजूद उसे क्यों प्रोमोट किया गया है क्या सरकार इस बात का जवाब देगी?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है।

Sewerage System in Safidon

***12. Shri Kundan Lal:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage system in the Grain Market of Safidon; and

(b) if so, the time by which the sewerage system is likely to be provided?

राज्य जन स्वास्थ्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह):

(क) हां जी।

(ख) कार्य को समाप्त करने की कोई निि चत तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह धन रािा की प्राप्ति व सामग्री पर निर्भर है।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपना जो जवाब दिया है मेरे ख्याल से यह कोई जवाब नहीं है। अगर कोई सरकार यह कहे कि उसको यह पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोजैक्ट कब पूरा होगा और यह भी कहे कि उसे यह भी पता नहीं कि फण्डज हैं या नहीं है और मेटीरियल है या नहीं है तो पता नहीं यह सरकार कैसे चल रही है जिसको यह पता ही नहीं है कि कोई काम कब पूरा होगा? (व्यवधान व ाोर)

चौधरी लाल सिंह: मैम्बर साहब को सवाल पूछने का पता ही नहीं है। इन्होंने कौन सा सही सवाल पूछा है। यह सरकार तो बडी तेजी से काम कर रही है। (व्यवधान व ाोर)

डा0 भीम सिंह दहिया: आप वक्त बताइये कि कितने वक्त में यह काम पूरा होगा। (व्यवधान व ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जान को अभी खतरा बना हुआ है या नहीं। (व्यवधान व ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: इनकी जान को खतरा अभी भी बना हुआ है या नही। अगर बना हुआ है तो कब तक यह खतरा बना रहेगा? (व्यवधान व ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप लोग तो उनके मजाक कर रहे है। आप उनको सुनना नहीं चाहते।

चौधरी लाल सिंहः मेरे पास इस समय सारे हरियाणा की हरेक स्कीम के बारे में इन्फर्मे ान है। मैं सारी फाइलें पढकर आया हूं और साथ लाया हूं। आप जो भी पूछना चाहते है पूछिये।

10.00 बजे

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, श्री कुन्दन लाल का सवाल मल निकास प्रणाली के बारे में था लेकिन मंत्री महोदय ने जल वितरण प्रणाली के बारे में जवाब दिया है। अगर मंत्री महोदय इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री महोदय को इसका जववा देना चाहिये। (व्यवधान व ाोर)

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय ने पार्ट ए का जबाव हां में दिया है और पार्ट बी का जवाब जो दिया है उसमें कहा कि कोई डेफिनिट डेट नहीं बताई जा सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जल वितरण योजना के बारे में जवाब दिया है जबकि सवाल मल निकास प्रणाली के बारे में है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मल के बारे में विभाग किसी और मंत्री के जिम्मे हैं?

चौधरी लाल सिंहः मैनें मल विकास योजना सफीदों के बारे में प्र न का जवाब दिया है।

श्री देवी दासः मंत्री महोदय ने कहा है कि काम समाप्त करने की अवधि नहीं बताई जा सकती क्योकि धनरा ि। और

सामग्री की कमी है। स्पीकर साहब, मैं सोनीपत के बारे में बताना चाहता हूं कि नगरपालिका पूरा पैसा ले लेती है लेकिन तीन तीन साल गडढे खुदे पडे रहते है पानी की नालियां खुली पडी रहती है लेकिन सरकार का पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट कहता है कि धन नहीं है इसलिये यह काम पूरा नहीं हो सकता। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस परप कुछ प्रका ा डालैंगे?

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डा0 दहिया और श्री देवी दास ने समय निर्धारित करने के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि वाटर सप्लाई की स्कीम हो या सीवरेज की स्कीम हो इनके लिये समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें पैसा और सामग्री दोनों की बात होती है। कई बार सरकार पैसा दे देती है लेकिन मैटिरियल नहीं मिलता जैसे कि बिजली के ट्रांसफारमर्ज की स्थिति है पैसा भी है लेकिन ट्रांसफारमर्ज नहीं मिलते। इसलिये समय निर्धारित करना मु कल होता है स्पीकर साहब, यह भी नही हो सकता कि एक ही सर्कल में काम हो। बजट में जो पैसा होता है वह सभी सर्कलज के लिये होता है और वह पैसा सारी स्टेट में बांटकर देना पडता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पूरी कोि ा ा है कि जहां भी काम चल रहा है वहां काम पूरा हो लेकिन जब मैटिरियल की दिक्कत हो तो समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

श्री हरि चन्द हुडडाः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सिवरेज जिसमें एमएलएज बह जाते है वह तो एक

दिन में तैयार हो जाता है लेकिन वह सिवरेज जिससे दे ा की गन्दगी निकलती है उसको तैयार होने में काफी समय लगता है इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्षः यह प्र न डिसअलाड किया जाता है।

Vacant Posts in Statistical Department

***31. Chaudhri Om Parkash:** Will the Finance Minister be pleased to state whether any posts of Deputy Directors are lying vacant in the Statistical Department Haryana; if so, the reasons for not filling up the said posts?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): There are no posts of Deputy Directors in the Statistical Department. However, posts of Deputy Economic and Statistical Advisors are lying vacant. The matter for filling these posts is under consideration.

चौधरी ओम प्रका ः अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले डिप्टी इकोनोमिक एण्ड स्टेटिसटिक्ल ऐडवाइजर्ज की पोस्ट के लिए किसी औफिसर को प्रोमोट न करने के लिए हैड आफ दी डिपार्टमैंट को चार्ज ीट किया गया था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिस हैड आफ दि डिपार्टमैंट को चार्ज ीट किया गया था उसने आज तक जवाब नहीं दिया और न ही उस औफिसर को प्रोमोट किया गया है जिसको जानबुझकर प्रोमोट नहीं किया गया था?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, इस केस में कमि नर एण्ड सैक्रेटरी ने इन्कवायरी की थी और he was absolved of the charges स्पीकर साहब, आप यह भी जानते है कि यह डिपार्टमैंट का प्रिरोगेटिव है कि किस औफिसर को किस वक्त प्रोमोट करना है और किस वक्त किस पोस्ट को फिलअप करना है।

डा0 मंगल सैनः मंत्री महोदय ने बताया है कि डिप्टी इकोनोमिक एण्ड स्टेटिसटिक्ल ऐडवाइजर्ज की जगह खाली है और उनको भरने के लिये अभी मामला विचाराधीन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह पोस्ट कब से वेकैन्ट है और कितने सालों से विचार किया जा रहा है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः यह पोस्ट अप्रैल 1979 में वेकैन्ट हुई थी और वेकैन्ट होने के कारण यह था कि हमारा औफिसर पंजाब लैन्ड डिवैलपमैंट बैंक के पास डैपुटे ान पर गया था। यह पोस्ट सैन्ट्रल असिसटैन्स विदड्रा कर ली और वह भरी नहीं गई। अब गवर्नमैंट इसको भरना चाहती है।

चौधरी ओम प्रका ाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ऐलिजिबल परसन को जानबूझ कर प्रोमोट नहीं किया जा रहा है?

श्री अध्यक्षः इस का जवाब आ गया है।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वेकैन्ट पोस्ट जनरल कोटे की है या रिजर्व कोटे की है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: ये सारी जनरल कोटे की पोस्ट है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी डैपुटे ान पर है इस पोस्ट को उसकी अधिकारी से भरेंगे या नए आदमी से भरेंगे?

चौधरी कटार सिंह छोकर: इस वक्त हमारे जो डिप्टी इकोनोमिक एण्ड स्टेटिसटिक्ल ऐडवाइजर्ज हैं उनमें से चार डैपुटे ान पर है और इन खाली पोस्टस को हम नैक्सट सीनीयर आदमियों से जल्दी ही भर देंगे।

Expenditure incurred on Bedding, Blankets in Hospitals

***6. Shrimati Chandrawati:** Will the Minister for Health be pleased to state the average yearly expenditure, based on the figures of the last three years, incurred on the purchase of beddings, blankets and bedcovers of hospitals at district headquarters and sub-division headquarters in the State together with the average yearly expenditure incurred on washing thereo?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

खरीद पर खर्च	**603787.93**
धुलाई पर खर्चा	**159787.11**

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में अलग अलग जिले की फिगर्ज पूछी थी लेकिन जो जवाब दिया गया है उससे पता नहीं चलता कि किस जिले में कितना खर्च किया गया है। क्या मंत्री महोदया अलग अलग फिगर्ज बताने की कृपा करेंगी।

श्रीमति प्रसन्नी देवीः जिला वार बजट व्यवस्था और खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:–

बजट व्यवस्था

जिला का नाम	1979–80	1980–81	1981–82
	रूपए	रूपए	रूपए
हिसार	57600	45000	68720
रोहतक	23200	40000	59560
गुडगांव	40640	40000	36650
करनाल	40000	40000	59560
अम्बाला	66560	45000	64140

नारनौल	28000	40000	45820
जीन्द	40000	38000	41240
कुरूक्षेत्र	25920	40000	50400
भिवानी	53280	45000	41240
सोनीपत	12000	30000	36650
सिरसा	25280	30000	32070
फरीदाबाद	—	40000	45520

खर्च

Name of the District		Bedding	Blankets	Bedcovers
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Karnal	15655.66	6666.66	20583.00
2	Bhiwani	22322.00	3333.00	-
3	Ambala	4060.00	21090.00	36715.00
4	Faridabad	8400.00	700.00	18000.00
5	Narnual	22574.00	37463.00	24665.00

6	Jind	38392.17	2666.65	5195.75
7	Kurukshetra	17267.00	3366.00	41467.10
8	Hissar	20399.59	-	3533.33
9	Gurgaon	1844.00	1953.00	9827.00
10	Rohtak	37997.00	7000.00	9951.66
11	Sonepat	133.33	4000.00	12166.66
12	Sirsa	3166.00	-	16666.00

डा0 भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो रकम इन्होंने अभी जिलावार हस्पतालों के लिये सामान खरीदने के लिए बतायी है आया इस रकम से वही साामन खरीदा जाएगा जिसके लिये यह पैसा सरकार दे रही है क्योंकि आम जनता में यह अफवाहें आ रही है कि हस्पतालों के अन्दर बिस्तर नहीं हैं, पटिटयां नहीं मिलती है और जो सामान हस्पतालों में आता है वह बेचा जाता है। क्या इस ओर सरकार ध्यान देगी और इन बातों की रोकथाम के लिये सरकार आगे क्या कदम उठाने का विचार रखती है। क्या यह सैन्क ान किया गया पैसा हस्पतालों के इस्तेमाल की चीजों पर ही खर्च किया जाएगा?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस में सामान बगैरह बेचने की बात नहीं है। जितने बिस्तर , चादरें और कम्बल हस्पतालों में रखने की आव यकता होती है उससे ज्यादा

की सामान वहां पर मुहैया किया जाता है क्योंकि कई बार ऐमरजैन्सी पडने पर सामान की आव यकता पड सकती है। अलबता यह बात तो जरूर हो सकती है जोकि आम देखने में आई है कि हस्पतालों में कई बार सफाई बगैरह का ध्यान नहीं रखा जाता है क्योंकि मरीजों के साथ कुछ लोग आ जाते है जोकि वहां कमरों में रहते है और सफाई वगैरह का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। इसलिये अब इस तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है कि सफाई वगैरह का भी ध्यान रखा जाए। सरकार अपनी ओर से यह कोि ा ा करती है कि हस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा सामान भेजा जाए लेकिन इसके बावजूद फिर भी वहां पर सामान की कमी रह सकती है। सरकार का यह यत्न है कि ऐसी कमी को भी पूरा किया जाए।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, 603787 रूपये के बिस्तरे कम्बल और बिस्तरों की चादरें खरीदी गयी है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि हरके सीएमओ ने हर साल अलग अलग सामान खरीदा है या यह सारा माल सारे प्रांत के लिए इकटठा ही खरीदा गया है। दूसरा प्र न यह है कि आया यह माल किसी कारपोरे ान से खरीदा गया या किसी प्राईवेट फर्म से खरीदा गया है।

श्रीमति प्रसन्नी देवीः यह माल हरके जिला के सीएमओ द्वारा खरीदा जाता है और इसे हरियाणा रैड कास सोसायटी लघु

उद्योग तथा निर्यात निगम और हरियाणा मैडिकल डिपो करनाल आदि से खरीदा जाता है।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से यह हिदायतें है कि कम्बल और खादी ग्रामोउद्योग से ही खरीदे जाएं। क्या सरकार ने वहीं से यह माल खरीदा है या किन्ही और फर्मों से इसे खरीदा जाता है।

श्रीमति प्रसन्नी देवीः आनरेबल मेम्बर अगर इसके लिए अलग से नोटिस दे ंतो बता दिया जाएगा। वैसे जहां जहां से सामान अवेलेबल होता है और जो निर्धारित कारपोरे ान्ज हैं वहीं से माल खरीद लिया जाता है।

श्रीमति चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी के अनुसार हस्पतालों में कोई कम्बल, बिस्तर वगैरह अवेलेबल नहीं है और जो हैं भी वे भी फटे पुराने है। न वहां पर मरीजों के लिये कोई दवाई है न पटिटयां ही अवेलेबल है सफाई को तो इतना बुरा हाल है कि कहना ही क्या तो मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि कभी इन्होंने हस्पतालों में स्वयं जाकर वहां की ऐसी गन्दी हालत को देखने का कश्ट किया है? अगर नहीं तो क्या वहां जाकर हस्पतालों को देखने का कश्ट करेंगी?

श्रीमति प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, हम ने इतलाह देकर और बिना इतलाह के हस्पतालों को चैक किया है। हमें तो कोई ऐसी बात जैसा कि बहन चन्द्रावती जी बता रही है वहां

दिखाई नहीं दी। हां सफाई की कमी जरूर मिलती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मरीजों के साथ उनके कुछ रि तेदार आ जाते है जोंकि कमरों में उनके साथ रहते है और सफाई वगैरह का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते।

श्री हरि चन्द हुडडाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इस बात में क्या राज है कि जो सवाल पूछने वाले हैं वे तो कमजोर हैं और जो मिनिस्टर महोदया है वे तगडी है? कहीं ऐसा तो नही हैं कि ये सरकारी माल पर डाका डाल रही हो?

श्री अध्यक्षः हुडडा साहब, आप बैठिये यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी देवीलालः अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदया ने जिलावार रकम का ब्यौरा दिया कि हस्पतालों की बहबूदी के लिये इतनी रकम खर्च की गयी है। बडी अजीब बात है कि सन 1978 में वनचारी, फरीदाबाद, बारू जींद, कलानौर, रोहतक, चुटाला और हिसार में 25–25 बिस्तरों का हस्पताल बनाने की योजना थी लेकिन हमारे सीएम साहब ने * * * * * * * (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐसी बात कहना आपको भाोभा नहीं देता ये भाब्द रिकार्ड न किए जाएं।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो मर्जी कहें, इनको पूरी छुटटी है लेकिन जब मैं बोलूं तो मेरी बात भी जरा सुन लें। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी देवीलालः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुटाला में ये श्री बलराज जाखड, लोकसभा के स्पीकर के साथ गये थे और वहां पर यह अनांउसमैंट करके आये थे कि इसको हम चण्डीगढ बना देंगे लेकिन चण्डीगढ तो क्या बनाना था, वहां पर न कोई स्टाफ ही है न कोई बिस्तर है और न कोई दूसरा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान है। अगर किसी जगह पर सरकार की तरफ से इस तरह ही अनांउसमैंट हो जाती है तो वहां लोगों की सहूलियत के लिए सब प्रकार का सामान जैसे कि बिस्तर, कम्बल और दवाइयां आदि मुहैया करना सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चुटाला जो हैं वह राजस्थान बार्डर पर लगता है और हरियाणा का आखिरी गांव है और वहां पर हास्पीटल के लिये पत्थर चौधरी देवीलाल जी ने जब वे स्वयं मुख्यमंत्री थे रखा था। उसके बाद वे चले गये और बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि चुटाला में हस्पताल की क्या जरूरत है वहां पर एक छोटी सी डिस्पैन्सरी ही बन जाये तो उचित रहेगा। मैंने कहा कि नहीं हमारे पहले मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने इसका पत्थर रखा है यहां पर पूरा हस्पताल की बनेगा और

इसको पूरा करके चालू कर दिया गया है। स्टाफ की बात इनहोंने आज बताई है हम जल्दी ही वहां पर स्टाफ बगैरह भी भिजवाएंगे।

* * * * * * *

चौधरी देवीलालः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान।

श्री अध्यक्षः मैंने कल भी अर्ज की थी कि जब ऐसी बात एक तरफ से भाुरू होगी तो सारे हाउस में बदमजग पैदा होगी। देवीलाल जी पहले आपने बात भाुरू की और उसके बाद आपने भी कुछ सुना और फिर कहा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी का तो लफज तेज कहने से किसी की इज्जत नहीं बढती और न ही उससे डिबेअ का स्टैडर्ड बढता है। आप दोनों मुख्यमंत्री रह चुके है और भजनलाल जी अब भी मुख्यमंत्री है इसलिये मैं आप दोनों से रिकवैस्ट करूंगा कि ऐसी बात न करें। देवीलाल जी को ऐसी बात भाुरू ही नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में जो भी लफज कहे गये है वे रिकार्ड पर न लाए जाएं।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदया ने ध्यान में यह बात है कि जो पैसा कपडों की धुलाई के लिये दिया जाता है उसमें से ज्यादातर पैसा सीएमओज खा लेते है? पहले इस मामले में एक सैकेटरी भी मिला हुआ था अब तो भाायद वह नहीं है। मैं यह चाहती हूं कि क्या सरकार इस बात की इन्क्वायरी करवाएगी। दूसरी बात यह हे कि आज कल हस्पताल स्टिंक कर रहे है और मरीजों की देखभाल नहीं हो रही है। इस बारे में भी मैं चाहती हूं

कि मुख्यमंत्री और हैल्थ मिनिस्टर हाउस में अ योरैंस दें कि हस्पतालों को ठीक ढंग से चलाया जाएगा और मरीजों को दवाईयां दी जाएगी।

श्रीमति प्रसन्नी देवीः ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सी जगह जाकर मरीजों से खुद पूछा है उनको बाकायदा दवाइयां मिल रही है। जहां तक धुलाई के पैसे खाने की बात है ऐसी कोई बात नहीं है।

डा0 भीम सिंह दहियाः अभी मंत्री महोदया ने कहा कि हस्पतालों में सफाई न रख पाने का कारण भाायद यह है कि हर मरीज के साथ दो तीन आदमी उसकी देखभाल के लिये आ जाते है। यह बात भाायद सच हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मरीजों के साथ जो आदमी उनकी देखभाल के लिए आते हैं क्या उनकी रिहाय ा के लिए सरकार कोई इन्तजाम करने का ख्याल कर रही है? हम पिछले दस सालों से सुन रहे है कि मैडिकल कालेज रोहतक में एक धर्म ाला बनाने जा रहे है। वह धर्म ाला बनेगी या नहीं, अगर बन रही है तो वह किस स्टेज पर है? रोहतक के अलावा जो बाकी पडे भाहरों में हस्पताल है क्या वहां भी कोई ऐसा इन्तजाम किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः इसके लिये तो आप अलग से नोटिस दे क्योंकि धर्म ाला के बारे में भाायद इनके पास इनफर्मे ान न हो।

श्री अमीर चन्द मक्कड: हस्पतालों में जो बिस्तर वगैरह दिये जाते है ये जिला और तहसील लैवल के हस्पतालों में दिये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हांसी के हस्पताल को बने हुए एक साल हो चुका है लेकिन उसका अब तक उदघाटन नहीं किया गया वह कब तक होगा?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: वैसे तो यह सवाल अलग है कि लेकिन फिर भी मैम्बर साहब की सूचना के लिये बता देती हूं कि उस हस्पताल की बाकी बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है सिर्फ रैम्प बनना रहता है। रैम्प तैयार होते ही उसका उदघाटन कर देंगे और हस्पताल चालू कर देंगे। जैसे ही एक मंजिल कम्पलीट हो जाएगी हम उस बिल्डिंग में काम भुरू करवा देंगे।

Water Supply Scheme in Safidon and Jind Tehsils

***13. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Public Health be pleased to state:-

(a) whether any schemes for the supply of drinking water in Safidon and Jind Tehsils are still incomplete; if so, details thereof, together with the dates by which these were scheduled to be completed separately; and

(b) the time by which the schemes, referred to in part(a) above, are likely to be completed?

जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): क. जी हां, योजनाओं का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा है।

ख. योजनाओं का पूर्ण होने का कोई निि चत समय नहीं बताया जा सकता है क्योंकि वह धनराि ा तथा इन्जीनिरिंग मैटिरियल उपलब्ध होने पर निर्भर होगा।

अनुबन्ध (क)

ग्रामीण जल वितरण योजनायें

राि ा लाखों में

कंमाक	योजना का नाम	गांवों की संख्या	अनुमानित राि ा	1982–83 तक प्रदान की गई धनराि ा	योजना को पूर्ण करने के लिए धन की आव यकता	पूर्ण करने के लिए अनुसूची
1	2	3	4	5	6	6
तहसील सफीदों						
1	धरोली समूह योजन	2	21.35	8.20	13.15	निर्धारित नहीं किया

	ा					गया
2	बागरू कलां समूह योजन ा	4	14.79	5.00	9.79	‘‘
3	बुटानी समूह योजन ा	3	17.36	2.50	14.86	‘‘
4	बाग खेडा समूह योजन ा	3	30.20	2.40	27.62	‘‘
5	मोरखी समूह योजन ा	2	15.15	2.40	12.75	‘‘
6	रत्त	3	18.00	0.80	17.20	‘‘

	खेडा समूह योजना					
	जोड	17	116.67	21.30	95.37	

1	2	3	4	5	6	6
तहसील जीन्द						
1	मालवी समूह योजना	3	30.35	4.00	16.35	निर्धारित नहीं किया गया
2	खारान्ती समूह योजना	5	28.47	7.00	21.47	‘‘
3	किनाना समूह योजना	7	22.95	3.50	19.45	‘‘
4	अकालगढ समूह योजना	4	30.53	2.50	28.03	‘‘

5	बरसौला समूह योजना	5	28.00	8.50	19.50	''
6	तलोदा समूह योजना	4	19.50	3.30	16.20	''
7	कारखेडी समूह योजना	6	28.88	0.80	28.08	''
8	जलालपुरकलां समूह योजना	6	20.00	1.00	19.00	''
9	दलामवाला समूह योजना	2	10.40	0.50	9.90	''
10	थुआ समूह योजना	1	15.50	3.50	12.00	''
11	रोहेडा माजरा समूह योजना	3	20.27	1.00	19.27	''
	जोड	46	244.85	35.60	209.25	

नागरिक जल वितरण योजनायें

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित राि ा	1982–83 तक प्रदान की गई धनराि ा	योजनाओं को पूर्ण करने के लिए धन की आव यकता
1	2	3	4	5
तहसील सफीदों				
1	सफीदों भाहर की जल वितरण योजना	15.69	14.44	1.25
तहसील जीन्द				
1	जींद जल वितरण योजना की बढौतरी	21.60	18.87	2.73
2	जींद की हरिजन बस्ती में जल वितरण योजना	3.16	1.00	2.16
3	रेलवे कालोनी जींद वार्ड नं0 9 की जल वितरण योजना	5.03	3.00	2.03

4	प्रेम नगर तथा जैन नगर की जल वितरण योजना	5.54	2.50	3.04
5	जींद के टिम्बर मार्केट क्षेत्र की जल वितरण योजना	3.63	2.54	1.09
6	जुलाना/ सं ाोधित जल वितरण योजना	20.16	13.16	7.00
	कुल जोड	74.81	55.51	19.30

राव इन्द्रजीत सिंहः मंत्री महोदय ने इस बार भी पिछले सवाल के जवाब की तरह कहा कि सबजैक्ट टू दि अवेलेबिल्टी आफ फंडज। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल सैन्टर की तरफ से कितने फंडज हरियाणा सरकार को मिले और इस साल कितने मिलने की उम्मीद है। दूसरा सवाल यह है कि जो फंडज हमें इस साल सैंटर से मिले थे उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है और उसका क्या काइटेरिया है? अगर मेरे इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी दे दे ंतो बेहतर होगा।

चौधरी लाल सिंहः माननीय सदस्य ने किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में नहीं पुछा। मेरे पास जवाब तैयार है। अगर ये कोई जनरल बात पूछना चाहते है तो मैं वह भी बता सकता हूं।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, आपको पता है कि जो महकमा श्री लाल सिंह जी के पास है वह लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करता है। मैं समझता हूं कि हरियाणा का एक महत्वपूर्ण काम एक गैर–महत्वपूर्ण आदमी को दिया गया है।

चौधरी लाल सिंहः आप सवाल पूछें और मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। मैं चार बार इस सदन में चुन कर आया हूं आप तो पहली बार आए हैं।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सवाल बहुत अहम है। हरियाणा प्रान्त में कुल 6731 गांव है जिनमें से हम दो हजार गांवों को पानी दे चुके है और 1177 गांवों में पानी देने की स्कीम पर काम चल रहा है। हमारी कोि ा ा यह भी है जहां कही भी पानी ठीक नहीं है और लोगों को पीने के लिये दूर से पानी लाना पडता है। उन गांवों में हम पहले पानी देंगे। इसी तरह से जहां कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत होगी, वहां हम पहले पानी मुहैया करने की कोि ा ा करेंगे।

डा0 मंगल सैनः अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जिन गांवों में पानी की कठिनाई है पानी दूर से लाना पडता है पानी खारा है या गहरा है यानी जो डिफिकल्ट विलेजिज है उनको हम प्रैफरैंस देंगे। क्या इसके लिये वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लेने की कोई स्कीम है।

चौधरी भजन लालः ऐसी स्कीमों के लिये वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है और सरकार अपने बजट से भी पैसा देती है। बहुत से गांवों की स्कीमों के बारे में हमने वर्ल्ड बैंक को भी लिखा है और जहां सरकार अपने साधन जुटा सकती है, वहां जुटा रही है।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी बडे लोकप्रिय है और बडा अनुभव भी रखते हैं। ये लोगों की सेवा भी करना चाहते है लेकिन एक अडचन है कि सरकार अनाउंसमैंट भी करती है और पत्थर भी बहुत रखती है लेकिन उसके बाद स्कीमें चार पांच साल तक लिंगर आन होती रहती है। क्या सरकार आने वाले समय में उतनी स्कीमों का ही पत्थर रखेगी जो समय पर पूरी हो जाएं। अगर इसी तरह स्कीमें बनाते जाएंगे और पत्थर रखते जाएंगे तो वे लिंगर आन होती जाएंगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी काम भारू करने के लिए हमें पहले पत्थर रखना पडता है। हम जो भी कंस्ट्रक ान का काम भारू करेंगे उसका पहले पत्थर रखेंगे। जिस जिस जगह पर हमने

पत्थर रखे हैं वहां सभी जगहों पर काम चालू है। हो सकता है एकाध जगह ऐसी हो जहां पर काम भाुरू करने में कोई किसी प्रकार की अडचन आ गई हो या किसी आदमी ने अदालत से स्ट `ले लिया हो । बाकी सब जगहों पर काम चालू है। इसके वक्त जो पत्थर रखे गए थे हमने तो वहां पर भी काम चालू किया है। जिन जिन जगहों पर पत्थर रखे हैं वहां पर काम पूरा करने की पूरी पूरी कोि ा ा करेंगे।

चौधरी देवीलालः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि इन्होंने हमारे वक्त में जहां कहीं भी पत्थर रखे गए थे वहां पर भी काम भाुरू कर दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे वक्त में आठ गांवों की 34 लाख रूपए के ऐस्टिमेटस की वाटर वर्कस की स्कीमज थी। उन सारे गांवों को इनहोंने वाटरवर्कस स्कीम्ज से निकाल दिया है। उन गांवों में अभी तक वाटर वर्क्स तैयार नहीं हुए है। सिरसा जिलें के गांव गिलाखेडा के वाटर वर्कस का काम जो अंडर कस्ट्रक ान था वह भी जब आज तक पूरा नहीं हुआ है तो ये बडे प्रोजेक्टस का काम कैसे पूरा करेंगे। इसी तरह से मेरी कांस्टिचुऐंसी मेहम में वाटर वर्कस के लिए पत्थर रखा गया था लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। क्या ये बताएंगे कि उसका काम कब पूरा करेंगे? (ाोर)

श्री अध्यक्षः आनरेबल मेम्बर्ज, अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों को लिखित उत्तर

Telephone Bills of the Council of Ministers

***32. Chaudhari Om Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of expenditure incurred by the Government on account of the bills of the telephones installed at the offices and residences of Chief Ministers Ministers of State and Deputy Ministers during the period from January 1982 to 22nd May 1982 and from 23rd May, 1982 t0 August 1982 separatly?

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः एक विवरणी अनुबंध ए तथा बी जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन के पटल पर रखी जाती है।

अनुबंध 'ए'

दिनांक 1–1–82 से 22–5–82 की अवधि में मंत्रियों के कार्यालयों तथा निवास स्थान पर किये गये टेलिफोन के खर्च का विवरण

क्रमांक	नाम तथा पदनाम		रा ि ा
	मुख्यमंत्री	99305.12	

1	श्री भजन लाल		99305.12
	मंत्री	258712.83	
2	श्री कन्हैया लाल पोसवाल, भूतपूर्व गृह मंत्री		20057.33
3	श्री खु र्शिद अहमद, भूतपूर्व वित्त मंत्री		18686.20
4	श्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला, तत्कालीन कृशि मंत्री		14073.05
5	श्री लछमन सिंह, तत्कालीन खाद्य एवं पूर्ति मंत्री		24567.50
6	श्री मेहर सिंह, भूतपूर्व आबकारी एवं कराधान मंत्री		14090.90
7	श्री बीर सिंह, भूतपूर्व सहकारिता एवं योजना मंत्री		14754.55
8	श्री तारा सिंह, भूतपूर्व सिंचाई एवं विद्युत मंत्री		16491.25
9	श्री राम पाल सिंह, भूतपूर्व		14119.80

	लोक निर्माण मंत्री		
10	श्री गजराज नागर, भूतपूर्व स्वास्थ्य एवं पयर्टन मंत्री		16478.40
11	श्री जगन्नाथ, भूतपूर्व परिवहन मंत्री		31852.65
12	श्री ि ावराम, भूतपूर्व जेल एवं डेरी विकास मंत्री		12158.60
13	श्री भोर सिंह, भूतपूर्व राजस्व मंत्री		23439.75
14	श्री दलीप सिंह, भूतपूर्व विकास मंत्री		12268.15
15	श्री मांगे राम, भूतपूर्व स्थानीय भाासन मंत्री		6371.80
16	श्री देसराज, भूतपूर्व ि ाक्षा मंत्री		19302.90
	राज्य मंत्री	38307.85	
17	श्री देवेन्द्र भार्मा, भूतपूर्व राज्य मंत्री सिचांई एवं		19685.15

	विद्युत		
18	श्रीमति भाान्ति देवी, भूतपूर्व राज्य ि ाक्षा मंत्री		8439.75
19	श्रीमति भाकुन्तला, तत्कालीन राज्य मंत्री लोक निर्माण		10182.95
	उपमंत्री	38413.80	
20	श्री लाल सिंह, तत्कालीन उप श्रम मंत्री		13706.70
21	श्री सरदार खां, भूतपूर्व उप गृह मंत्री		16812.20
22	श्री प्रेम सिंह, भूतपूर्व उप कृशि मंत्री		7894.90

अनुबंध 'बी'

दिनांक 23–5–82 से 31–5–82 की अवधि में मंत्रियों के कार्यालयों तथा निवास स्थान पर किये गये टेलिफोन के खर्च का विवरण

क्रमांक	नाम तथा पदनाम		राि ा
	मुख्यमंत्री	45260.67	
1	श्री भजन लाल		45260.67
	मंत्री	83047.20	
2	श्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला, सिचांई एवं विद्युत मंत्री		7396.00
3	श्री हरपाल सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री		5655.40
4	श्री लछमन सिंह, उद्योग मंत्री		12777.50
5	कर्नल राम सिंह, परिवहन मंत्री		3092.00
6	श्री राजेन्द्र सिंह, खाद्य एवं पूर्ति मंत्री		1425.00
7	श्रीमति भाारदा रानी, विकास मंत्री		7275.70
8	श्रीमति प्रसन्नी देवी,		8368.50

	स्वास्थ्य मंत्री		
9	श्री सुरेन्द्र सिंह, कृशि मंत्री		9909.00
10	श्रीमति भाकुन्तला, समाज कल्याण मंत्री		4263.00
11	श्री बीरेन्द्र सिंह, सहकारिता एवं डेयरी विकास मंत्री		6891.00
12	श्री फुल चन्द, राजस्व मंत्री		2210.00
13	श्री कटार सिंह, वित्त मंत्री		6254.50
14	श्री कल्याण सिंह, आवास एवं जेल मंत्री		2298.00
15	श्री बृज मोहन, आबकारी एवं कराधान मंत्री		5231.60
	राज्य मंत्री	51954.00	
16	श्री गोवर्धन दास चौहान, राज्य मंत्री लोक निर्माण		5510.50
17	श्री लाल सिंह, राज्य मंत्री जन स्वाथ्स्य		5628.50

18	श्री ए0सी0 चौधरी, राज्य मंत्री स्थानीय भाासन		2825.00
19	श्री राजे ा कुमार, राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार		1610.00
20	श्री चन्दा सिंह, राज्य मंत्री परिवहन		6647.00
21	श्री रहीम खां, राज्य मंत्री सिंचाई एवं विद्युत		5751.00
22	श्री जगदी ा नेहरा, राज्य ि ाक्षा मंत्री		15377.00
23	श्री लछमन दास अरोडा, राज्य मंत्री तकनीकी ि ाक्षा		8605.00

Provision of Bed/Beddings in Dadri, Jhojh and Gopi Hospitals.

***7. Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) the number of beds as well as beddings provided in Dadri, Jhojh and Gopi Hospitals separately; and

(b) whether it is a fact that sufficient amount is not being provided to meet washing expenses of the aforesaid hospitals?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(क)	सामान्य हस्पताल, दादरी	50
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झोझू	8
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोपी	8

(ख) नहीं।

Bus Accidents occurred in the State

***17. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the number of fatal accidents involving Haryana Roadways buses occurred during the year 1980-81 and 1981-82 together with the steps, if any, taken or proposed to be taken to minimize chances of such accidents; and

(b) whether the Government proposed to fix any amount of compensation to be paid as a matter of policy depending upon the nature of casuality suffered, to the dependents of the deceased and to the persons injured in the

accidents referred to in part(a) above, if so, the details thereof and the time by which this policy is likely to be implemented?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) अनुबंध 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) इस समय सरकार के पास इस विशय पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध 'क'

(क) हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के कुछ फैटल दुर्घटनाएं:–

1981–82	146
1981–82	184

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गये हैं:–

1. 65 किलोमीटर प्रति घण्टा के हिसाब से गति नियत की गई है।

2. चैंकिग के लिये कई दल बनाये गये है जिनमें ट्रैफिक इनफोरसमैंट स्टाफ सचि प्रादे िाक परिवहन अधिकारी, अनुभवी चालक तथा वरिश्ठ मकैनिक है जिन द्वारा तेज गति से

वाहन चलाने वालों तथा हरियाणा राज्य द्वारा कानून की उल्लंघना करने वालों को पकडा जाता है।

3. दुर्घटनाओं को गाडियों की ब्रेक डाऊन को रोकने के लिए तकनीकी अनियमतों को रोकने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन का स्तर उंचा किया गया है।

4. चालकों को सेवा में लेने से पहले परीक्षण तथा तो पहले से सेवा मैं है को रिफ्रै ार कोर्स करना पडता है।

5. जिन चालकों की आयु 45 वर्श से उपर है उनकी आंखों का निरीक्षण किया जाता है।

Admission to Dental College, Rohtak

***33. Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) the total number of seats sanctioned for the admission to the B.D.S. course in the Government Dental College, Rohtak during the academic year 1981-82;

(b) the number of students admitted to the said course against general quota on merit, reserved quota and by nominations during the above said academic year separately; and

(c) the percentage of marks obtained by the nominated students in the examination held for admission to

the said course together with the names and addresses of the nominated candidates?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):-

(a) 26

(b) (1) General quota on merit 17

(2) Reserve quota:-

(1)	Scheduled castes/ Scheduled Tribes	Nil as on candidate belonging to this category was available
(2)	Backward Classes	2
(3)	Nominations by Haryana Govt.	7

(c) (i) Candidates nominated by Haryana Govt. were not required to appear in admission test and as such the question of percentage of marks in their case does not arise.

(ii) A list of the candidates nominated by Haryana Govt. to B.D.S. Course is laid on the table of the house.

Name and addresses of the candidates nominated by Haryana Government for B.D.S. course:-

1. Miss Ashu Bala, D/o Shri Piara Grover, 62, Old Mandi, Mandi Adampur, Distt. Hisar.

2. Miss Geetika Chawla, D/o Sh. Y.C. Chawla, 11/6J, Medical Campus, Rohtak.

3. Miss Deep Shikha S/o Dr. Brij Mohan Gupta, Chawk Bazar, Jagadhri, Haryana.

4. Ajay Soni S/o Sh. P.K. Soni, 12/13 East Patel Nagar, New Delhi-8

5. Mr. Arvind Kumar S/o Sh. Satgur Dass, Damdam Mohalla, Khajjar, Distt. Rohtak.

6. Harjit Singh S/o Sh. P.J. Singh, No. 20 Air Force Dental Centre, Airforce Adampur, Jullundur.

7. Nitin Jain S/o Sh. Moti Sagar Jain, General Hospital, Sector-16, Chandigarh.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Dismissal of Policemen

12. Shri Roshan Lal Arya: Will the Minister be pleased to **Chaudhri Om Parkash**

state whether it is a fact that some Policemen were dismissed from service in August, 1982 in the State, if so, the number thereof?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): हां जी। राज्य में अगस्त 1982 में 363 पुलिस कर्मचारी बरखास्त/डिस्चार्ज किए गए थे।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं रिकार्ड को जरा स्ट्रेट करना चाहता हूं। सदन में कुछ

समय पहले एक अनप्लैजैन्ट बात चली। चौधरी देवीलाल जी ने कुछ कहा और चौधरी भजनलाल जी ने भी कुछ कहा। (विघ्न) स्पीकर साहब, मुझे याद है कि चौधरी भजन लाल जी ने चौधरी देवीलाल जी के बेटे श्री ओम प्रका ा के बारे में यह कहा था कि उनका कोई कसूर नहीं है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, वे सारी बातें मैने रिकार्ड से निकलवा दी है। (व्यवधान व ाोर)

चौधरी भजन लालः मंगल सैन जी मैं यह बात नहीं कहना चाहता कि आपको चौधरी देवीलाल जी ने मिनिस्टरी से डिसमिस किया था। (ाोर एवं विघ्न)

डा0 मंगल सैनः चौधरी साहब, आप यह बात कह कर खु ा हो लें कि चौधरी देवीलाल ने मुझे मिनिस्टरी से डिसमिस किया था। स्पीकर साहब, रिकार्ड स्ट्रेट रखने के लिये यह कहना बडा जरूरी है कि चौधरी भजन लाल जी समय समय पर रंग बदलते हैं (विघ्न) कोई बात नहीं आपने उस समय तो चौधरी देवीलाल जी के बेटे के बारे में यह बात कही थी कि उनका कोई कसूर नहीं है लेकिन अब बदल गए। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

श्री प्यारा सिंह द्वारा–

श्री प्यारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। पिहोवा में जो पांच आदमियों का कत्ल हुआ है उनके बारे में मेरे पर जो इल्जाम लगाया गया है, वह सरासर निराधार है। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उन मरने वाले पांच आदमियों में चार आदमी मेरे स्पोर्टर थे जिन्होंने चुनावों के दौरान मेरी स्पोर्ट की थी।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी देवीलाल जी ने क्वै चन आवर के दौरान पर्सनल एक्सप्लेने ान दी थी और सरदार प्यारा सिंह जी ने भी पर्सनल एक्सप्लेने ान दी थी। मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई मैम्बर या मिनिस्टर क्वै चन आवर के दौरान पर्सनल एक्सप्लेने ान दे सकता हैं या नहीं? (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी देवीलाल और मुख्यमंत्री जी ने एक दूसरे के विरूद्ध जो बातें कही थी वे रिकार्ड पर नहीं है।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, * * * * * (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये किस विशय में बोल रहे है * * * * * (ाोर एवं विघ्न)

प्रोफैसर सम्पत सिंहः * * * * * (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि बोलते वक्त हमें रूल्ज एण्ड रैगुले ान बरकरार रखने पडेंगे। चौधरी सम्पत सिंह जी आप मेरी परमि ान के बगैर खडे होकर बोल रहे हैं और अखबार दिखा रहे हैं। इसका मतलब तो केवल यही हो सकता है कि आप गैलरी में बैठी हुए पब्लिक को यह चीज दिखा रहे है। यदि मैं आपको बोलने की परमि ान नहीं देता हूं तब तो आपको कुछ कहना चाहिए था। क्वै चन आवर के दौरान मैंने 90 परसैन्ट टाईम अपोजि ान को सप्लीमैटरी पूछने के लिये दिया है। फिर भी यदि आप कायदे कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मुझे कुछ सोचना पडेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी थोडी देर पहले मुख्यमंत्री जी ने यह फरमाया * * * * *। यह बात ऐक्सपन्ज किया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

सिचांई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, श्री सम्पत सिंह जी ने आपके परमि ान के बगैर जो कुछ कहा है वह ऐक्सपन्ज किया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः श्री सम्पत सिंह जी ने मेरी परमि ान के बगैर जो कुछ कहा है वह ऐक्सपन्ज कर दिया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि * * * * * यह डैरोगेटरी है। इसको ऐक्सपन्ज किया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय सदस्य को स्पीकर साहब, का आदर करना चाहिए। जिस समय स्पीकर साहब, खडे हो तो उनको बैठ जाना चाहिए। जो आदमी एमएलए का कर्तव्य नहीं समझता उसको अपना कर्तव्य समझना चाहिए। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः हम स्पीकर साहब का आपसे ज्यादा आदर करते है। आप फैसला देने वाले नहीं है। यदि स्पीकर साहब से हमारी कोई बात होगी तो उस बात के जिम्मेदार हम होंगे। स्पीकर साहब, आपने चौधरी सम्पत सिंह की बात को ऐक्सपंज करने का हुकम फरमा दिया। इन्होंने ऐसी कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कही जिसको ऐक्सपंज किया जाए। इसलिये मेरी आपसे गुजारि ा है कि आप उनकी बात को ऐक्सपंज न करें आप उसको रिव्यू करें।

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी अगर किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा भी यदि कोई अनपार्लियामेंटरी या डैरोगेटरी बात कही गई है तो वह ऐक्सपंज हो जाएगी।

डा0 मंगल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था। मुख्यमंत्री जी

आए दिन कहते है कि अगर ऐसी कोई बात हो तो हमारे नोटिस में लांए। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी श्री आन्नद भार्मा, जिन्होंने सांपला से चुनाव लडा था, न ऐसी हरकत की है जिसे कहते हुए मुझे भार्म आती है। स्पीकर साहब, यह बात इन्डियन ऐक्सप्रैस में भी छपी है। उन्होंने एक अबला की इज्जत लूटने की कोि ा ा की है। यह बडा सीरियस मामला है। मैं यह बात किसी पोलिटिकल प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बाई गाड कह रहा हूं कि यह बडा गम्भीर मामला है और उनके खिलाफ जरूर ऐक ान लिया जाना चाहिए। मेरे पास एक फोटो स्टेट कापी है जिसे में मुख्यमंत्री जी को देने के लिए तैयार हूं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, डा0 साहब मुझे यह कापी दे दें, हम इसकी पूरी इंक्वायरी करवा लेगें। किसी बात के पूरी तरह से तह में जाएं बगैर और इन्क्वायरी किए बगैर किसी आदमी के खिलाफ ऐक ान नहीं लिया जा सकता। यह बात गलत भी हो सकती है। इस बात की हम पूरी इंक्वायरी करेंगे अगर यह बात सही होगी तो उनके खिलाफ ऐक ान लिया जाएगा। (इस समय मुख्यमंत्री जी को डा0 मंगल सैन द्वारा एक लैटर दिया गया)।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अगर मैंने जो ा में कुछ कह दिया हो तो उसके लिये मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और गाइडैंस के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष

महोदय, हम भी पढे लिखे हैं। लोगों ने हमें वोट दिए हैं और हम लोगों के प्रतिनिधि है। मुझे विधान सभा के मतलब का भी पता है। विधानसभा का मतलब यह है कि वह सभा जो विधान बनाती है। कानून बनाने के लिए हमें साल में केवल 5–6 दिन का ही समय मिल पाता है लेकिन जो रोजमर्रा की चीज है जो रोजाना घटती है जिनसें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी भी बदनामी होती है। (विघ्न) उनकी तरफ ध्यान दिलाना हमारा फर्ज है। हाउस में हम सभी एमएलएज बैठै हुए है। लौगों के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है। यदि कोई गलत काम होता है तो उसे बताना हमारा फर्ज बनता है। हरियाणा में रोजाना नई नई चीजें हो रही है। यहां पर हर चीज का व्यापारीकरण हो चुका है। यह अखबार दिल्ली से निकलता है। इस अखबार का नाम फोर्टनाईट है।

श्री अध्यक्षः मैंने आपकी भावना समझ ली है जो अखबार आप दिखा रहे है। इसके बारे में आप मुझे चैम्बर में मिल लें। तब कोई निर्णय ले लेगें।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः यदि अखबार में गलत खबर है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मो ान लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः मैंने आपसे कह दिया है कि आप इस बारे में मुझे चैम्बर में मिल लें।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहती हूं। आज की सरकार ने भिवानी जिले में बिजली के रेट बढा दिए है। जिससे तंग आकर कुछ लोग वहां पर भूख हडताल पर बैठे हैं। भूख हडताल पर बैठे होने के कारण उनकी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने बिजली के जो रेट बढाये हैं वे न बढाये क्योंकि किसान पहले ही सूखे के कारण काफी दब चुका है। बर्बाद हो चुका है। और उस पर इतना अधिक कर्जा हो चुका है कि वह उससे उभर नहीं पा रहा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार को बढे हुए रेट वापस लेने चाहिए। यदि ये बढे हुए रेट वापस ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र होंगे। आज सारे हरियाणा के अन्दर बिजली के ट्रांसफार्मर जले हुए है। बिजली ठीक प्रकार से किसानों को नहीं दी जा रही। फिर भी इन्होंने बिजली के रेट इतने अधिक बढा दिए है जिससे किसानों में अत्याधिक अंसतोश फैला हुआ है। इसलिये मैं अन्त में सरकार से फिर यही प्रार्थना करूंगी कि इस बारे में सरकार पुनर्विचार करें और सरकार को इस इ ु को प्रैसटिज इ ू नहीं बनाना चाहिए। लोगों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन् ान मो ान दिया था। करनाल के अन्दर मजदूरों को परे ान किया जा रहा है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहां के मजदूर भूख

हडताल कर रहे है। मजदूरों को नाजायज तंग किया जा रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मेरे उस काल–अटैन ान मो ान का क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः मैं उसे अभी ऐग्जामिन कर रहा हूं।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अभी बहन चन्द्रावती ने जो बात कही हे वह बिल्कुल ठीक है। इस में कोई दो राय नहीं कि बिजली के रेट बढाये जाने से किसानों में असंतोश है। पिछले दिनों यह बात सुनने में आई थी कि बिजली बोर्ड अपने रेट बढाने जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। आज भिवानी जिले के अन्दर जो रेतीलें इलाके है वहां तक बिजली के रेट 40–42 प्रति ात बढा दिए है। वहां पर पहले 48 घंटों में से 12–14 घंटे बिजली किसानों को मिलती थी लेकिन अब वहां पर सिर्फ 9 घंटे बिजली दी जा रही है। सारी सावनी की फसल खराब हो गई है। लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। किसानों पर कर्जे बढ रहे है। वहां पर लोग भूख हडताल पर बैठे हुए हैं मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः इस का कल डिटेल में जवाब आ गया था।

श्री हीरा नन्द आर्यः भिवानी जिले के कुछ इलाके में बिजली का रेट चार्ज करने के लिए तीन स्लैब बनाये हुए है। एक स्लैब तो वह है जहां 50 फुट से कम गहरा पानी है, दूसरा स्लैब

वह है जहां 50 फुट से 80 फुट तक गहरा पानी है और तीसरा स्लैब वह है जहां 80 फुट से अधिक गहरा पानी है। हर जगह पर बिजली का रेट प्रति यूनिट 4 पैसे बढाया गया है। जहां पर पहले एक यूनिट के 12 पैसे आते थे उसके भी 5 पैसे और जहां पर एक यूनिट के 20 पैसे आते थे वहां पर भी पांच पैसे बढाए गए है। मेरे कहने का मतलब यह हे कि सरकार ने 25 प्रति ात से लेकर 42 प्रति ात तक बढोतरी की है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर टयूबवैल ज्यादा गहराई में है वहां पर ज्यादा पैसेन बढाये जाएं। वहां पर जो लोग भूख हडताल पर बैठे हुए है। वे जन जागरण के लिये बैठे है। सरकार को उनकी समस्या की ओर ध्यान देते हुए जो बिजली के रेट बढाये है। वापस लेने चाहिए। इसलिये मैं चहूंगा कि सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भी इसी तरह का एक काल अटैन ान मो ान दिया हुआ है। मैं उसे इलाके से सम्बन्ध रखता हूं जहां पर पानी मिलता ही नहीं और बिजली भी ठीक प्रकार से सप्लाई नहीं हो पा रही है। सरकार ने बिजली के रेट बहुत बढा दिए है। जिससे किसान बहुत दुखी है।

श्री अध्यक्ष: वह अभी कन्सीडर हो रहा है।

ध्यानाकर्शण सूचना–

पानीपत बाईपास बनाने तथा बढ रहे यातायात को विनियमित करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज मुझे श्री फतेह चन्द विज एमएलए की ओर से ने ानल हाईवे नं0 1 पर पानीपत के पास एक बाई पास बनाने के लिये काल अटैन ान मो ान का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूं। कृपया वे अपना नोटिस पढ ले और मंत्री महोदय अपना जवाब दे दें।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने चण्डीगढ के विशय में एक एडजर्नमैंट मो ान दी हुई है, उसका क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्षः श्री फतेह चन्द विज की काल अटैन ान मो ान भ्ारू हो चुकी है इसके खत्म हो जाने के बाद उसके बारे में आपको बता दिया जायेगा।

श्री फतेह चन्द विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस अत्याव यक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस बढ रहे यातायात को ठीक ढंग से चालू रखने के लिये तुरन्त आव यक पग उठाए। पानीपत एक औद्योगिक नगर है जहां से करोडो रूपये का हैंडलूम माल तैयार होकर दे ा और विदे ा में जाता है जहां पर बहुत बडी भ्ागर मिल, फर्टीलाईजर फैक्ट्रिरी तथा थर्मल प्रोजैक्ट होने के कारण ट्रैफिक बहुत बढ गया है और

सडक दुर्घटनाएं बढती जा रही है और अब एक बहुत बडा प्रोजैक्ट आयल रिफायनरी लगने जा रही है जिसके लिए 1500 एकड भूमि अर्जित की जा रही है जिससे यातायात बहुत बढ जाएगा। अगर बहुत भीघ्र नगरपालिका की सीमा में सिक्स लेन रोड न बनाई गई और पानीपत नगर के बाईपास को जोकि मंजूर हुआ है जल्दी बनाने के लिये केंद्रीय सरकार को कहकर भुरू न कराया गया तो भविश्य में और ज्यादा दुर्घटनाएं बढ जाएगी और यातायात बिल्कुल ठप्प हो जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

वक्तव्य–

लोक निर्माण राज्य मंत्री द्वारा उक्त ध्यानकर्शण सूचना सम्बन्धी

Minister of State for Public Works (Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan): The State Government is fully aware of the urgent requirement for a Byepass on National Highway No.1 at Panipat. Panipat is an important industrial town and is developing fast. The recent addition of the Thermal Power Station and a Fertilizer Plant has generated considerable traffic around the town. The thorough traffic on the National Highway which ifself has increased considerably over the years gets mingled with the local traffic and apart from causing great inconvenience to the residents of the town, also endangers public safety.

2. The State Government have for a very long time been urging the Government of India to construct a Byepass

on the National Highway No.1 at Panipat. The Ministery of Shippiing and Transport of the Government of India did provide for a Byepass at Panipat in the Fourth Five Year Plan. At a later stage, the Govt. of India considered the alternative possibility of improving and widening the National Highway passing through Panipat. This proposal, however, was dropped and agains the Government of India included the proposed Byepass at Panipat in the list of works proposed to be sanctioned for the Sixth Five Year Plan. Soon after the inclusion of this work in the Sixth Five Year Plan, the State Government submitted a rough cost estimate for the Byepass for an amount of Rs. 31495000/- to Government of India in January 1979. The alignment proposed by the State Government was inspected by Additional Director General (Road Development) of the Government of India in June, 1980. Subsequently as desired by the Government of India the State Government also submitted a report on the cost benefit and cost appraisal concerning the Byepass in 1981.

3. The State Government were surprised to note that even after having agreed to this project in principle earlier, the Government of India did not include it in the Sixth Five Year Plan as finally approved. The Finance Minister Haryana and subsequently the Chief Minister addressed demi-official letters to the Minister Haryana also Transport Government of India. The Chief Minister Haryana also discussed the matter regarding the construction of a byepass at Panipat with the Minister of State, Shipping and Transport, New Delhi on December 6, 1981. As a result of all these efforts the Central Government have now agreed to accommodate the estimate for land acquisition only for the Panipat byepass in

the Sixth Plan 1980-85 by substitution for some other works already included in the Plan. In response to this the State Government have sent to Government of India on June 2, 1982 the requisite estimate amounting to Rs. 14016800/- prepared by the PWD (B&R) Department. The matter is being pursued with the Government of India.

4. Earlier, an an alternative to the byepass the State Government had approved a scheme for 6 laning of the 3.80 K.M. on Highway passing through the Municipal limit of Panipat town at a cost of Rs. 48.72 lakhs. However, now that the Govt. of India have agreed to include the bye-pass project in the Sixth Plan, the scheme has been kept in abeyance. But in order to provide immediate relief an estimate for six-laning about a kilometer of the busiest stretch of the road (costing of Rs. 9.93 lakhs) has been sent to Govt. of India afte discussing with the Director General of the Ministry of Shipping and Transport.

श्री फतेह चन्द विजः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिस काम को 9.93 लाख रूपये का ऐस्टिमेट गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेजा गया है वह काम कब भ्रुरू हो जाएगा।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः जितनी जल्दी पैसा आ जाएगा हम काम भ्रुरू करा देंगे।

श्री फतेह चन्द विजः उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से का लगाना है उससे फिलहाल ये काम भ्रुरू करवा दें।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः हमने कोई पैसा नहीं लगाना है। यह पैसा गवर्नमैंट आफ इंडिया ने देना है। हमें उम्मीद है कि यह पैसा जल्दी आ जाएगा।

श्री फतेह चन्द विजः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारा खर्च 48.72 लाख रूपये का बताया है लेकिन भारत सरकार को एस्टिमेट केवल 9.93 लाख रूपये का भेजा है बाकी का 38 लाख रूपया भी तो कहीं से आना है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, 48.72 लाख रूपये वाली स्कीम को छोड दिया गया है। हमने 9.93 लाख रूपये का एस्टिमेट 1 किलोमीटर रोड के बिजीयेस्ट स्ट्रैच का भेजा है। हमारी इच्छा है कि इसे तो कम से कम जल्दी बनवा दिया जाए और उसके बाद बाईपास का काम भाुरू किया जाए।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

ध्यानाकर्शण सूचना–

चण्डीगढ पंजाब को हस्तांरित करने सम्बन्धी

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक बहुत अहम इ ा रेज किया था वह चण्डीगढ के बारे में था। आपने फरमाया था कि आप आज इसके बारे में अपना फैसला देंगे।

Mr. Speaker: Hon. Members I have converted an adjournment motion given notice of by Dr. Mangal Sein into a calling attention motion being a matter of public importance but not of such importance which requires to be admitted as an adjournment motion and has therefore, admitted this calling attention motion accordingly for today. Dr. Mangal Sein may please read his calling attention motion. I would request the Government to make a statement in the matter today, if they ar prepared or tomorrow.

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन का ध्यान मैं एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हैं कल के दैनिक इंडियन एक्सप्रैस जो कि चंडीगढ से छपता है के मुख्यपृश्ठ पर यह समाचार प्रकाि ात है कि चंडीगढ पंजाब को दिया जा रहा है। परन्तु फाजिल्का अबोहर का हरियाणा में भाामिल होने के बारे में बात ज्यादा स्पश्ट नहीं हैं। यह कार्यवाही पहली नवम्बर 1982 को होने जा रही है परन्तु प्रदे ा की सरकार ने अभी तक अपनी राजधानी कहां ले जानी हे इसका भी निर्णय नहीं किया है।

यह सारी कार्यवाही अकाली मोर्च के दबाव में आकर की जा रही है यह घटना अभी की है तथा समस्य प्रदे ा के जन जीवन से इसका सम्बन्ध हैं। केंद्रीय सरकार की दब्बू नीति के परिणामस्वरूप हरियाणा के हितों का बलिदान होने वाला है। अतः यह मामला बडा गम्भीर है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

वक्तव्य–

मुख्यमंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचन सम्बन्धी

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने बडे महत्व पूर्ण मसले की ओर सरकार का और सारे हाउस का ध्यान दिलाया है। अखबार में हमने भी इस बात को पढा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि चंडीगढ पंजाब को ट्रांसफर होने जा रहा है। आप जानते है कि यह फैसला 1970 में हुआ था। इसके लिए कमी ान मुकर्रर हुआ और बहुत गहराई से उस कमी ान ने सारी बातों को देखा। उसने पंजाब को सुना हरियाणा को सुना और हिमाचल को भी सुना तथा उसके बाद यह निर्णय भारत सरकार ने लिया कि चंडीगढ पंजाब को जाएगा और अबोहर फाजिल्का का इलाका हरियाणा को मिलेगा। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 1970 में कमी ान ने यह फैसला किया कि चंडीगढ पंजाब को जाएगा और अबोहर तथा फाजिल्का हरियाणा को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है। यह फैसला तो प्रधानमंत्री के अवार्ड में हुआ था। (विघ्न)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है। मेरा भी कहने का भाव यही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जब तक अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को ट्रांसफर नहीं होता तब तक चंडीगढ छोडने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि अबोहर और फाजिल्का भी हमें मिल जाए तब भी चंडीगढ हो हम तब छोडेगें जब दूसरी जगह अपनी राजधानी बना लेंगे। अभी तक इसके बारे में न तो भारत सरकार ने कोई मीटिंग बुलाई है और न कोई ऐसी बात विचाराधीन है। अगर भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई बात होगी तो हमारी सरकार को वि वास में लिया जाएगा। हमारी सरकार के साथ बात की जाएगी और उसके बाद वे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। (विघ्न) मैं सदन को बताना चाहता हैं। **11.00 बजे** कि जहां तक हमारी सरकार का ताल्लुक है हरियाणा के हितो की पूरी रक्षा की जायेगी। भारत सरकार भी हरियाणा के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेगी। आप सभी साहेबान जानते है कि भारत सरकार के लिए सारा दे ा एक जैसा है। भारत सरकार जब भी कोई फैसला करती है तो सभी बातों को सामने रखते हुए करती है। इस बारे में किसी महानुभाव को चिन्तित होने की आव यकता नहीं है। हम इस बात की पूरी कोि ा ा करेंगे कि अगर चंडीगढ पंजाब को ट्रांसफर किया जाता है तो फाजिल्का और अबोहर के इलाके हरियाणा के साथ ही साथ ट्रांसफर होने चाहिए। चंडीगढ का जो

कुछ भी फैसला हो फाजिल्का और अबोहर का भी साथ ही फैसला होगा। जो हमारे हिन्दी बोलने वाले इलाके है और आजकल पंजाब में है उनके लिए अलग से कमी ान बनाया जाएगा ताकि वे इलाके हरियाणा को मिल सकें। (व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री को अपने स्टैन्ड को कलियर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम कोि ा ा करेंगे।

चौधरी भजन लालः हमारा स्टैण्ड बिल्कुल कलीयर है। जो फैसला हुआ है उसको इम्पलीमैंट करने की बात है जो फैसला हो चुका है उसकी बात मैं कह रहा हूं। किसी भी हालत में जब तक फाजिल्का और अबोहर का इलाका हमें ट्रांसफर नहीं हो जायेगा तब तक चंडीगढ को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि कल एक दो बातें यहां पर कही गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन बातों का उतर दे दूं। यहां पर कल पुलिस के निकाले हुए कर्मचारियों का हवाला दिया गया और इन्होंने उसबात तक कल वाक आउट भी किया। कुछ और भी इल्जाम लगाये इसलिये मैं उनके बारे में कलियर करना चाहता हूं।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने चंडीगढ का मामला उठाया है। यह उस मामले को टालना चाहते है। मैंने एक दो

सवाल भी करने है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने वायदे पर कायम रहेंगे?

चौधरी भजन लालः आप सवाल पूछिए। हमने तो आपका बहुत साथ दिया है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिन मांगों को लेकर अकाली मोर्चा लगा हुआ है। उसमें तीन बातें हरियाणा से संबंधित है एक तो हरियाणा को जो अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिन मांगों को लेकर अकाली मोर्चा लगा हुआ है। उसमें तीन बातें हरियाणा से संबंधित है एक तो हरियाणा को जो एसवाईएल का पानी मिला है उसके बारे में है। हालांकि हमें उतना पानी नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था, उससे कम मिला है। यद्यपि हरियाणा के हितों को बलिदान करके यह फैसला किया गया है लेकिन फिर भी उनकी मांग यह है कि उस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए और उन्हें पानी का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे जो इलाके पंजाब के हरियाणा में रह गए वे उन्हें मिलने चाहिएं। उन्होंने यह भी बात रखी हुए है कि पंजाबी एरिया पंजाब को ट्रांसफर होने चाहिए। तीसरे उनकी मांग यह भी है कि हरियाणा में गुरमुखी दूसरी भाशा बनाई जानी चाहिए। तीन बातों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सरकार की पोजी ान कलियर करें। इन तीन मामलों के बारे में इस सदन को और सारे हरियाणा की जनता को वि वास में ले और जो भी उनका स्टैन्ड हो उसे कलियर करें।

चौधरी भजन लालः जहां तक पंजाब में अकाली ऐजीटे ान का सवाल है उसके बारे में तो पंजाब सरकार ही कुछ कहेगी। जहां तक हमारी सरकार और भारत सरकार की रावि ब्यास के पानी के बारे में स्टैन्ड का ताल्लुक है वह फैसला भारत सरकार ने किया है और उस पर भारत सरकार का स्टैन्ड पक्का है क्योंकि यह फैसला उसी ने किया है। यह बहुत ही भाानदार फैसला भारत सरकार ने लिया है। यह कहना कि हरियाणा के हितों को बलिदान करके फैसला किया गया है बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। 35 लाख एकट फीट पानी न तो आज तक किसी सरकार ने या चौधरी देवीलाल ने कभी मांगा था और न ही इसमें ज्यादा कभी दिया गया था। (व्यवधान व ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप तो 3.5 एमएएफ की बात करते है हमने तो 4.8 एमएएफ पानी मांगा था। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः यह तो हमने ही पहले मांगा था। आपकी सरकार ने नहीं मांगा था। आपने कभी इतना पानी नहीं मांगा। यह रिकार्ड की बात है। (व्यवधान व ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः आप ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखें, उसमें मांगा हुआ है।

चौधरी भजन लालः 3.5 एमएएफ का पानी का फैसला हरियाणा के लिए बहुत की भाानदार फैसला हुआ है। उस नहर पर अब काम भाुरू हो चुका है उस नहर के काम की प्रोग्रैस की

मीटिंग होती है। सैन्ट्रल वाटर कमी ान की चेयरमैन उस कमेटी का चेयरमैन है और उसमें हरियाणा और पंजाब के अफसर भी भाामिल है। हर महीने कमेटी जायजा लेती है कि नहर का काम किस स्टेज पर है और उसमें कितनी प्रेाग्रैस हुई है। इतनी ही बात नहीं है उस कमेटी के उपर भी एक हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है। जिसके चेयरमैन सैक्रटरी इरीगे ान गवर्नमैंट आफ इंडिया है। प्राईम मिनिस्टर भी उस कमेटी से रिपोर्ट लेती है कि कितनी प्रोग्रैस हुई है। उसमें पंजाब और हरियाणा के चीफ इंजीनियर फाईनैन्स सैकटरी आदि मैम्बर्ज है। इस हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग अक्तूबर के महीने में होनी है। वह कमेटी चैक करेगी कि इस संबंध मैं क्या प्रोगैस हुई है। यह नहर दो साल में बन कर तैयार हो जायेगी। सारी बातों का जायजा लेने के लिये ये कमेटियां भारत सरकार ने बनायी हुई है।

डा0 मंगल सैनः क्या यह मामला फिर री–ओपन तो नहीं हो जायेगा।

चौधरी भजन लालः री–ओपन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस नहर पर काम भाुरू हो चुका है। ऐग्रीमेंट तीनों स्टेट का हो चुका है। तीनों मुख्यमंत्रियों के दस्तखत हो गये है। हमारी प्रधानमंत्री खुद इन्ट्रैस्ट ले रही है और यह चाहती है कि टाईम के अन्दर यह नहर बने। जिस काम में प्रधानमंत्री इतनी दिलचस्पी ले फिर उसमें दरे से बनने का और री–ओपन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर तीसरे महीने वे प्रोग्रैस देखती है।

दो साल का टाईम नहर बनने का दिया हुआ है लेकिन उससे पहले ही नहर बनकर तैयार हो जायेगी।

डा0 मंगल सैन जी ने पंजाबी भाशा का भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी भी हमारे भाई है। और दूसरे लोग भी हमारे भाई है। जहां तक पंजाबी भाशा को सैकिन्ड लैंग्वेज बनाने का सवाल है वह तो हम अंग्रेजी को सैंकिड लैंग्वेज मान कर चलते है लेकिन मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि जो पंजाबी पढना चाहे, वह पढ सकता है। अगर किसी स्कूल में दस लडके पंजाबी पढने वाले होंगे तो हम वहां पर पंजाबी टीचर देंगे इसी प्रकार से अगर कोई उर्दू पढना चाहे तो जहां दस लडके उर्दू पढने वाले होगें। वहां भी हम उर्दू टीचर देंगे। तेलगू भाशा का भी हरियाणा में पढाने का प्रबन्ध किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि अगर कोई ने ानल हाईवे अमृतसर तक जाता है और उस रोड के उपर यदि अंग्रेजी और हिन्दी में बोर्ड लगे हुए है उसके नीचे यदि पंजाबी में भी लिख दिया जाये तो कोई एतराज वाली बात नहीं है। क्या पंजाबी हमारे भाई नहीं है। क्या उस रोड पर पजांबी पढे हुए भाई नहीं चलते है। जहां तक ने ान का सवाल है उसमें ब्रोड माइन्डिड होना चाहिए। हमें पंजाबियों को भाई मान कर चलना चाहिए। पंजाबी को सैकिंड लैंग्वेज मामने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक हितों का सवाल है पंजाबियों के हितों की पूरी रक्षा ही जायेगी। जहां तक चंडीगढ आदि के फैसले का सवाल है

उसमें पहले ही लिखा गया है कि ये एरिया ट्रांसफर होने के बाद हिन्दी बोलने वाले इलाके जो पंजाब में रह गये है। या पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा में रह गये हैं उसके लिए भारत सरकार एक कमी ान मुकरर्र करेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनको पता हे कि क्या होने जा रहा है। यह हाउस से कुछ छिपा रहे हैं इन्होंने यह मान लिया है कि कमी ान मुकरर्र होगा और यह सरकार हरियाणा के हितों को बेच जायेगी। (व्यवधान व ाोर) इनकी बातों से अब हमें पता लग गया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो कुछ 1970 के अवार्ड में दिया गया था। उसकी चर्चा कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ उसी का उल्लेख कर रहा हूं जो कुछ उस अवार्ड में दिया गया है। (व्यवधान व ाोर)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये सारी बातें कह कर ये हरियाणा के हितों के खिलाफ बात कर रहे है। (व्यवधान व ाोर)

चौधरी भजन लालः मैं यह कहता हूं कि चंडीगढ अगर पंजाब को जायेगा तो उसके साथ ही एक ही दिन में एक ही मिनट में बिना एक सैकंड की देर किये अबोहर और फाजिल्का भी हरियाणा को आयेंगे और जो पंजाबी या हिन्दी बोलने वाले इलाके तो एक दूसरे के क्षेत्र में रह गये हैं उनके लिये एक अलग से

कमी ान बनेगा। यह तो उस अवार्ड में दिया हुआ है जो 1970 में दिया गया था।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कमी ान बनेगा इसका मतलब स्पश्ट है कि यह इस बारे में हमें बता नहीं रहे है। (व्यवधान व ाोर) आपने यह बात तो मान ली है कि कमी ान बैठेगा। आपने तो ऐसे कह दिया है कि जैसे आपको पहले से ही पता है कि कमी ान बैठेगा। (व्यवधान व ाोर)

चौधरी भजन लालः यह तो अवार्ड में है कि हिन्दी स्पीकिंग इलाके हरियाणा में जायेंगे और पंजाबी स्पीकिंग इलाके पंजाब को जायेगें। (व्यवधान व ाोर)

डा0 मंगल सैनः अकालियों से केंद्रीय सरकार भी डरती है और इनका भी हाजमा खराब हो जाता है। (व्यवधान व ाोर)

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि उस एग्रीमेंट में जो केंद्रीय सरकार ने उस समय अनाउंस किया था उसी में यह प्रोवीजन था। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें यह लिखा हुआ नहीं था कि 5 साल में अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को मिल जायेंगे जोकि अब तक भी नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्षः जो स्टेटमैंट मुख्यमंत्री जी ने देनी थी, वह दे चुके है। अब डाक्टर मंगल सैन जी यदि कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, उस समय 10 करोड रूपया सैन्टर सरकार ने हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिये माना था, अब रूपये की कीमत चूंकि बहुत कम हो गयी है और मंहगाई बढ गयी है इसलिये क्या हरियाणा सरकार केंद्रीय सरकार से 2 अरब रूपये की मांग करेगी।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैं यह समझती हूं कि हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों को ही किसी भी केंद्रीय सरकार के नये कमी ान के लिए एग्री नहीं करना चाहिये। आज अन–एम्पलायमैंट की समस्या है और डैफिसिट फाइनैंसिस की वजह से रूपये की डी–वैल्यूए ान हो रही है। केंद्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा के लोगों को आपस में लडाने के लिये यह कमी ान बनाना चाहती है। जो फैसला हो चुका है उस अवार्ड को तो अभी तक इम्पलीमैंट नहीं किया गया है। अगर उस अवार्ड को इम्पीमैंट करें फिर तो कुछ बात बनती है लेकिन मैं यह साफ कहना चाहती हूं कि उनकी मन् ाा यह है कि हम लोगों को ध्यान वास्तविक समस्याओं की ओर से हटाये। पंजाब और हरियाणा के लोग जो बहादुर है और जो सारे दे ा के लिये अन्त पैदा करते है। उनको दोबारा लडाने के लिए केंद्रीय सरकार की यह एक बहुत बडी साजि ा है। मैं यह बात आन दी फलौर आफ दी हाउस कह रही हूं। मैं यह समझती हूं कि हरियाणा सरकार को इस कमी ान के लिये कभी भी नहीं मानना चाहिये। पहले आपके पता है कि चंडीगढ इ ा पर कितने लोग मरे थे और कितनी

गोलियां चली थी। इसलिये हमको चाहिये कि यह जो केंद्रीय सरकार की साजि ा है उसको कामयाब नहीं होने देना है। आज कितने ही लोग अन–एम्पलायड घूम रहे है। उनको आपस में लडाने की बजाये अगर ज्यादा ही करना है तो हम चंडीगढ को आध आधा कर लें तो अच्छा होगा। मैं यह चाहती हूं कि आज जो जवान लडके और लडकियां बेकर घूम रहे है। उनको नौकरियां दे। जो दे ा में छोटे बच्चे है उनको पूरी खुराक नहीं मिल पाती है उनको आप पूरी खुराक दें। मैं यह चाहती हूं कि इस मामले में कमी ान दोबारा नहीं बैठना चाहि। क्या इस बारे में गवर्नमैंट अपनी स्थिति स्पश्ट करेंगी।

चौधरी भजन लालः जहां तक कमी ान अप्वायंट होने की बात है वह तो अवार्ड के इम्पलीमैंट होने के बाद की बात है। उसमें यह लिखा गया है कि अवार्ड के इम्पलीमैंट होने के बाद एक कमी ान बैठेगा जिसके बैठने से हरियाणा किसी भी हालत में लास में नहीं जायेगा। आपको तो यह वहम हो गया है कि हम लूट करेंगे। वहां पर पंजाब में सैंकडों गांव ऐसे है जो हिन्दी स्पीकिंग है और पंजाब में है। पटियाला के हरियाणा के साथ लगने वाले इलाके ऐसे ही है।

श्रीमति चन्द्रावतीः वह तो उस अवार्ड का अंग है कि पटियाला तहसील के हरियाणा के साथ लगने वाले इलाके हरियाणा को दिये जायेंगे।

चौधरी भजन लालः इसलिये तो में यह कह रहा हूं कि उस अवार्ड की इम्पलीमैंट ान से हम घाटे में नहीं रहेंगे। (व्यवधान व ाोर) वह कमी ान तब बैठेगा जब हमें अबोहर और फाजिल्का मिल जायेंगे और चंडीगढ पंजाब को चला जायेगा। वरना तो उस कमी ान के बैठने का सवाल ही नहीं है। जब तक उस अवार्ड को इम्पलीमैंट नहीं किया जाता कमी ान बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान व ाोर)

स्पश्टीकरण–

मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस–कर्मचारियों को निकाले जाने सम्बन्धी

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के बारे में थोडा सा स्पश्टीकरण देना चाहता हूं। कल खासतौर पर श्री वीरेंद्र सिंह जी ने इल्जाम लगाया कि कास्टिजम के आधार पर पुलिस के सिपाहियों को निकाला गया है। कोई भी दे ा कास्टिजम से नहीं चलता। जाति–पाति की बात किसी भी दे ावासी को नहीं करनी चाहिये। चाहे वह सियासी आदमी हो या गैर सियासी आदमी हो। अगर वह ऐसी बात करता है तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता क्योंकि एक बिरादरी से कभी कोई दे ा नहीं चल सकता। जब तक 36 बिरादरियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक समाज अच्छा नहीं होगा और दे ा की राजनीति अच्छी नहीं होगी। हमें कभी भी जाति–पाति की बात

नहीं करनी चाहिये। हमने कभी भी जाति–पाति के हिसाब से कोई काम नहीं किया है। मैंने पता करवाया है कि पुलिस में कितने आदमी किस बिरादरी के निकाले गये है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जहां फौज एक ऐसी फोर्स है जो दे ा की सीमाओं की रक्षा करती है वहां पुलिस ऐसी फोर्स है जो हरेक नागरिक की सेवा करती है उसकी इज्जत को महफूत रखती है और ला एण्ड आर्डर का मेनटेन करती है। किसी भाई के साथ ज्यादती होती है तो उसको दूर करने की कोि ा ा करती है। अगर उस फोर्स में ही अनु ाासन न हो तो क्या दे ा ठीक तरह से चल सकता है? नहीं। इसलिये इन महानुभावों को यह चाहिये था कि सरकार द्वारा किये गये काम को क्रिटीसाईज न करते। आपको पता है कि हरियाणा पुलिस एक बहुत अच्छी फोर्स है। सारे दे ा में इतने नाम कमाया हुआ है और इसका नाम सारे दे ा में उंचा है। हमारी पुलिस फोर्स दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी और बेहतर है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह तो जबाव दे रहे है यह किस मो ान पर जबाव दे रहे हैं। अगर आप हाफ इन आवर डिस्क ान इस पर अलाउ कर दे ंतो अच्छा रहेगा क्योंकि इस बारे में कल जो हमारा काल अटैन्ा ान मो ान था उसको तो आपने डिस–अलाउ कर दिया था। हमने तो यह मामला जीरो आवर में उठाया था। आपने चूंकि हमारा काल अटैन्ा ान मो ान डिस–अलाउ कर दिया था इसलिये

हमने वह मामला तो जीरो आवर में उठाया था। अब आप अगर चौधरी साहब को जबाव देने का मौका देंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिये आप हाफ इन आवर डिस्क ान अलाउ कर दीजिये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: क्वै चन के जवाब में तो हाफ एन आवर डिस्क ान हो सकती है वरना नही।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आपने रूल्ज पढे तो होंगे लेकिन अब भाायद भूल गये होगें। मैं आपको रूल 84 पढकर सुना देता हूं कि तीन वजूहात से हाफ एन आवर डिस्क ान हो सकती है। (व्यवधान व ाोर)

श्री अध्यक्ष: काल अटैन्ा ान मो ान पर तो हाफ एन आवर डिस्क ान हो नहीं सकती। हाफ एन आवर डिस्क ान केवल क्वै चन पर हो सकती हैं? (व्यवधान व ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपको रूल 84 पढ कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है–

A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discussion such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed...

मेरा सबस्टांटिव मो ान था, डा0 मंगल सैन का सबस्टांटिव मो ान था। चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट दे रहे हैं। मेरी अर्ज यह है कि आप इस पर डिस्क ान अलाउ कर दें और मुझे तथा डा0 मंगल सैन जिनका यह मो ान है को पांच पांच मिनट दे दें। (व्यवधान व ाोर)

श्री अध्यक्षः आज काफी बिजनैस है। इसलिए मैं किसी को भी टाईम नहीं दूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे जल्दी खत्म करें।

डा0 मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस हाउस में जो भी कार्यवाही होती है वह रूल्ज के मुताबिक होती है। मुख्यमंत्री जी मेरे सब–स्टांटिव मो ान के बारे में जवाब दे रहे है जोकि रैलेवेन्ट है। अगर वे कोई बात कहते है तो हमें भी दो–दो मिनट का समय मिलना चाहिए। सबस्टांटिव मो ान तो एडमिट नहीं हुआ लेकिन वे पुलिस के मामले पर बोल रहे हैं और आप उनको बोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा हूं। यह डिस्क ान अब नहीं पर खत्म कर दी जाए। (ाोर व व्यवधान)

श्री हरि चन्द्र हुडडाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने रूल दिखाया और चीफ

मिनिस्टर ने पुलिस के बारे में बात कही। मैं इन रूल्ज से भी उपर की बात कहना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने जो रास्ता अख्तियार किया वह * * ने दिखाया था। चौधरी भजन लाल कहते है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे है। अगर चौधरी भजन लाल उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे है तो फिर पुलिस वालों ने क्या बुरा किया है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, * * का जो रैफरैंस दिया गया है वह ऐक्सपंज होना चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

मेज पर रखे गुए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Transport Minister will lay some papers on the Table of the House.

Transport Minister (Col Rao Ram Singh): Sir, I beg to lay on the Table of the House-

Transport Department, Haryana Notification No. G.S.R. 49/CA.4/39/S.91/Amd (1) 82, dated the 29th March 1982 regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amemdment) Rules 1982 as required under section 133(3) of the Punjab Motor Vehicles Act, 1939.

Transport Department, Haryana Notification No. G.S.R. 74/CA.4/39/S.41/Amd (2) 82, dated the 21th June 1982 regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana Second Amemdment) Rules 1982 as required under section 133(3) of the Punjab Motor Vehicles Act, 1939.

संविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक,उ 1982 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प

Excise and Taxation Minister (Shri Brij Mohan): Sir, I beg to move-

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill, 1982 as passed by the two Houses of Parliament.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill, 1982 as passed by the two Houses of Parliament.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, अच्छा होता यदि मंत्री महोदय संसद के अन्दर पारित इस सं ाोधन विधेयक के बारे में अपनी बात कहते मैम्बर्ज को एनलाइटन करते लेकिन वे तो प्रस्ताव रखकर बैठ गए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। उपाध्यक्ष महोदय, इस दे ा को आजाद हुए 35 वर्श हो गए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसका कुछ भाग 26 नवम्बर, 1949 को भी लागू हो गया था। 1950 के बाद आज 1982 आ गया। बत्तीस साल में 46वीं बार संविधान में

सं ाोधन करने जा रहे है। यह जो आज की अमैंडमेंट है यह लोकसभा और राजसभा द्वारा पारित की जा चुकी है। डिप्टी स्पीकर साहब, जनता पार्टी के भाासन में हमारे वित्तमंत्री बाबू मूल चन्द जी जैन ने इसी प्रकार का विधेयक इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था। जिन उद्योगपतियों ने हरियाणा की धरती पर उद्योग लगाए हुए है जो हरियाणा की धरती पर पोल्यू ान कर रहे हैं। सडकों का इस्तेमाल कर रहे है और हरियाणा की बिजली का इस्तेमाल कर रहे है। उनकी सारी लायबिलिटी तो हरियाणा प्रदे ा पर है। लेकिन उन्होंने अपने दफतर दिल्ली में बनाए हुए है और वे सारे माल को हरियाणा में न बेचकर दिल्ली के ब्रांच आफिस में बेचने के लिए ले जाते है। इसका नतीजा यह होता है हमारा प्रदे ा सेल्ज टैक्स से वंचित रह जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम जानते है कि स्टेट का रैवेन्यू ज्यादातर सेल्ज टैक्स पर और एक्साइज पर ही निर्भर हो गया है। लैंड बहुत ही अनइकोनिमिक होती जा रही है। उसका रैवेन्यू बहुत कम है और अब सारा बर्डन इस टैक्स स्ट्रक्चर पर आकर पडा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, प्रोडक्टिंग स्टेट पहले इस बात से वंचित रह जाती थी कि उसे उसके माल पर सेल्ज टैक्स नहीं मिलता था क्योंकि माल यहां बनता था आरै सेल्ज टैक्स जहां जाकर माल बिकता था वहां आदा किया जाता था लेकिन अब इन्होंने यह कर दिया है कि जब यहां से माल जाएगा उसी पर यहां से ही टैक्स लग जाएगा, यह अच्छी बात है। इससे अपनी

स्टेट को आमदनी होगी। अब हमारी सरकार ने टैक्स लगाने का तो तरीका अपना रखा है वह उचित नहीं है। अभी आज के ही एजेण्डे पर इन्होंने पैट्रोलियम प्रोडक्टस पर सेल्ज टैक्स बढाया है। बसों के भाडे में वृद्धि की है बिजली की दरों में भी वृद्धि की गयी है। वैसे तो पहले ही हरियाणा का गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, साधारण मजदूर, अनुसूचित जाति के लोग, कमजोर लोग, आम नागरिक टैक्सों के बोझों के नीचे दबे हुए है। मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं है वह कह रहे थे कि नाथपा झाकडी की जो परियोजना है उसके लिए पैसा चाहिये। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से कितनी आय से कर लेंगे? फिर भी इन्हें केंद्र का मुंहदेखना ही पडेगा और वहां से बात न बनी तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पडेगा जब कही जाकर ये परियोजनाएं पूरी होगी। मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं है चले गये, विश्राम कर रहे होंगे, उनको मिलने वाले भी बहुत आते है थके हुए रहते हैं अगर वे बैठे होते तो उनसे हम पूछते। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का अपनी मन्त्रि परिशद का भी खर्चा है काफी भर्ती की हुई है और कईयों को तो लारे भी दे रखे हैं। लालच भी दे रखा है। (विघ्न) कारपोरे ानज और बोर्ड के चेयरमैन बनाने के लिए कईयों को झांसा भी दे रखा है। (विघ्न) सुरजेवाला साहब आपको क्या है आप तो ठीक जंच रहे हो। सरदार लछमन सिंह जी आपकी क्या बात है आपके दोनों हाथों में गुलाब जामुन और लडडू है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ टैक्स लगाने की बचाये इस मन्त्रि

परिशद का खर्चा अगर ये कम कर ले तो इनकी काफी बचत हो सकती है। कांग्रेस (आई) के दोस्तों ने चुनाव के दिनों में लोगों से यह वायदा किया था कि अगर हमें सत्ता में लाओगे तो हम आपको सेल्ज टैक्स की लानत से छुटकारा दिला देंगे। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म नहीं कर सकी। इन्हीं में से पहले हमारे कुछ साथी थे। कुछ अब लोकदल में है कुछ इनकी तरफ चले गये है। (विघ्न) कांग्रेस पार्टी के जो 35–36 मैम्बर्ज जीत कर आये हैं ये पता नहीं किस तरह से रिटनिंग अफसर से मिल–मिलाकर हेराफेरी करवा कर जीत गये है। (विघ्न) खैर, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन अदालती मामलों में नहीं पडना चाहता। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर पहले ही यह वायदा पूरा कर दिया होगा तो लोगों को इस सेल्ज टैक्स की लानत से अव य ही पहले ही छुटकारा मिल गया होता और छोटे व्यापारी का इससे पीछा छूट गया होता। सिंगला साहब का विभाग डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत अच्छा है इसमे कोई भाक नहीं है। इनके विभाग ने राज्य में काफी नाम रो ान किया है। सेल्ज टैक्स के नाम पर जब इनके इस्पैक्टर जाते हैं तो बेचारे दुकानदार अपनी दुकानों के भाटर गिरा देते हैं वैसे तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके विभाग का कोई ही ऐसा बिरला अफसर होगा जोकि लेन–देन का काम न करता हो। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको भी इस बात का तजुर्बा होगा। आप वकील है। आप के पास भी ऐसे कई केसिज आते होंगे कि किस तरह से छोटे–छोटे व्यापारियों का खून चुसा जा

रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई तरीका क्यों ने अडोप्ट किया जाए जिससे सारे दे ा के लोगों का इस सेल्ज टैक्स की लानत से पीछा छूट जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सं ाोधन का तो मैं समर्थन करते हुए स्वागत करता हूं और इतनी ही बात कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो रेजोल्यू ान रेटीफिके ान के लिये हमारे सामने आया हैं मैं उसका स्वागत करता हूं परन्तु यह बहुत लेट हो गया। अभी डा0 मंगल सैन जी ने कहा कि वह विधेयक पहले जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस वक्त आया था परन्तु पार्लियामैंट डिजौल्व हो गयी और यह लैप्स हो गया। खैर अब कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को दोबारा लेकर आयी है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसिज ने इस को पास किया है और अब रेटिफिके ान के लिये हमारी हरियाणा असेम्बली के सामने रखा गया है। मेरा दल इस को पास करने के लिये इस सरकार का पूरा सहयोग करेगा। मैं एक दो बातें कह कर अपना स्थान लूंगा। इस रेटिफिके ान के बाद जो ऐक्ट है ज बवह कानून का रूप लेगा उस समय हरियाणा प्रान्त को इससे लगभग 100 करोड रूपये सालाना की आदमनी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त बाबू मूल चन्द जैन वित्तमंत्री थे। उन्होंने जब इस बात को अपने बजट में पे ा किया था तो उस वक्त इस किस्म का टैक्स लगाया गया था लेकिन जब दूसरी सरकार चौधरी भजन लाल जी

की आई तो इन्होंने इसको खत्म कर दिया लेकिन भाुक है अब ये लोग राहेरास्त पर आये है और अब इसी टैक्स के द्वारा हरियाणा प्रान्त का रैवेन्यू बढाना चाहते है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके साथ साथ में डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने साथ ही साथ बसों के किराये में बढोतरी कर दी है बिजली की दरों को बढा दिया है। सिंचाई तथा बिजली मंत्री यहां बैठे है। मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि डा0 मंगल सैन जी ने कहा कि नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट के लिये कई करोड रूपये की आव यकता है। इसके लिये हमें या तो केंद्र पर निर्भर रहना पडेगा या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पडेगा। स्लैब सिस्टम में जो दर बढा दिया गया है। उससे पांच सालों में लगभग 17 करोड रूपये को इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड को लाभ होगा। मैं याद दिलाना चाहता हैं कि जो इलैक्ट्रिसीटी डयूटी लगती थी वह इनहोंने बडे बडे इंडस्ट्रियलिस्टस को खु ा करने के लिए ऐबोलि ा कर दी। लेकिन अगर उस डयूटी को दोबारा रिवाईव किया जाए तो उससे हरियाणा प्रदे ा को कम से कम 21 करोड का लाभ होगा। मेरा कहना यह है कि बगैर किसानों को मारे, उनके उपर टैक्सों का बोझा लगाये बिना, बडे बडे इंडस्ट्रियलिटस पर से जो डयूटी ऐबोलि ा कर दी गई थी उसको दोबारा रिवाईव कर दिया जाए। क्योंकि आज किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है। किसान को आज पूरा पानी नहीं मिल रहा है उसकी

जरूरत के अनुसार बिजली भी नहीं मिल रही है और दूसरा उपर से परमात्मा का कोप भी है। अगर एक आध बारि ा नही हुई और इसीलिये हरियाणा के किसान को काफी लाभ होगा। प्रान्त में बारि ा नहीं हुई और इसी लिये हरियाणा के दो तिहाई हिस्से में कहत पड चुका है। इस मार को हरियाणा का किसान बर्दा त नहीं कर सकेगा और क्योंकि आई0पी0एम0 साहब इन संस्कारों में पले हुए है। इसलिये मैं समझता हूँ कि वे इसकी रिव्यू करेंगे और इलैक्ट्रिसीटी डियूटी को रिवाइव करेंगे। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों में यह डियूटी पे करने की कैपेसिटी है उनको यह लगे। दूसरी बात यह है कि पैट्रोल पर भी ये टैक्स की वृद्धि कर रहे है। आज पता लगा है कि उसे 5 प्रति ात की बजाए 7 प्रति ात किया जा रहा है। जब आपको इस रैटिफिके ान से सौ करोड रूपये सालाना की आमदनी होने जा रही है तो आप और टैक्स क्यों लगा रहे हो। आज के हालात ऐसे नहीं है कि टैक्स के रेट और बढाए जाएं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इन सारे फैसलों को दोबारा सोचना चाहिए ताकि हरियाणा के आम कंज्यूमर को राहत मिल सके चाहे वह कंज्यूमर बिजली का है या रोड पैसेंजर है।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह पहली बार सुन कर खु ाी हुई है कि जो अमैंडमैंट बिल भारत सरकार ने पास किया है उसमें अपोजि ान भी सहयोग दे रही है। मैं अपनी ओर से इस बिल का समर्थन करता

हूं। इसमें बात यह है कि जो सामान हमारी स्टेट में बनता था और बन कर दूसरी स्टेटों में चला जाता था उसका फायदा तो दूसरी स्टेट उठाती थी और कारखानेदार को सुविधा हमारी स्टेट देती थी। अब इस अमैंडमैंट से वह फायदा हमें मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल लाकर बहुत अच्छी बात की गई है। पहले यह होता था कि माल तो हमारी स्टेट में तैयार होता था और कारखानेदार दूसरी स्टेटों में अपने चार चार दफतर खोल देते थे और सेल्ज टैक्स का सारा पैसा उन स्टेटों को जाता था। मैं समझता हूं कि कुछ साल पहले अगर यह बात बन जाती तो बहुत अच्छा रहता। इस बिल के आने से सरकार की आमदनी बढेगी और क्र ाइन घटेगी। दूसरी बात यह है कि थ्री स्टार, फाइव स्टार होटलों पर जो सेल्ज टैक्स नहीं है लेकिन ढाबे वालों पर सेल्ज टैक्स है यानि जो आदमी सौ रूपये की आमदनी करता है उस पर तो टैक्स है और जिनकी हजारों रूपये की रोज सेल होती है उन पर सेल्ज टैक्स नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि बडे होटल भी सेल्ज टैक्स दें। तीसरी बात हायर परचेज के बारे में है। मिसाल के दौर पर एक किसान ट्रैक्टर लेता है या आदमी ट्रक लेता है उस बारे में कहा जाता है कि इसका पैसा कि तों में होगा इसलिये इस पर सेल्ज टैक्स नहीं होगा। उन्होंने भी ऐसा हिसाब–किताब बना रखा है जिससे हजारों रूपये सरकार को सेल्ज टैक्स का नहीं आता था अ बवह भी ठीक हो जायेगा। आखिरी बात यह है कि हर आदमी यह चाहता हैं। ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब सरकार के पास पैसा हो पैसा टैक्स से

आता है। जैसे हमारी नाथपा झाकडी 800 करोड रूपये की स्कीम है और एस0वाई0एल0 दो सौ करोड रूपये की स्कीम है इन पर अगर पैसा लगेगा ये तभी चलेंगी। इसलिये टैक्स भी लगाना पडता है। ऐसी सुविधाएं देने के लिये मुनासिब टैक्स लगाने का कोई हर्ज नहीं है। खामखाह की मुखालफत जायज नहीं है। अगर नाथपा झाकडी स्कीम बन जाएगी तो हमें बिजली दस पैसे यूनिट के हिसाब से पडेगी। एक तजवीज मैं और देना चाहता हूं कि यह जो सेल्ज टैक्स है अगर इसको हटा दिया जाए तो दे ा का बहुत भला हो सकता हैं कोई ऐसी स्कीम सरकार ले आए कि या तो सेल्ज टैक्स पहली स्टेज पर ही मर्ज हो जाए या इसे एक्साइज डयूटी की भाकल में लगाया जाए। ऐसा करने से सेल्ज टैक्स की चोरी बन्द हो जाएगी और सरकार की आमदनी भी बढ जाएगी तथा दुकानदारों की सरदर्दी भी कम हो जाएगी। इतना कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री हरिचन्द हुडडा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट आई है यह सेल्ज टैक्स के बारे में है जिसको हम लैवी कहते हैं। पीछे हमने जो देखा यह लैवी गरीब लोगों पर लगती थी जोकि बडे बडे कारखानेदारों को देते थे। अब यह जो अमैंडमैंट आई है इससे हरियाणा को सौ करोड रूपये सालाना की आमदनी होगी। नाथपा झाकडी की जो हमारी स्कीम है यह 1974 में स्टार्ट हुई और इस पर हमारा एक करोड रूपया खर्च हो चुका है। उस स्कीम पर तो कभी काम चालू नहीं हुआ, यह पैसा सिर्फ

स्टाफ के कवार्टरों पर खर्च हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस अमैंडमैंट की वजह से जो हमारी सौ करोड रूपये सालाना की आमदनी होगी वह सारा पैसा नाथपा झाकडी स्कीम पर लगा दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो हरियाणा की इकनोमिक पोजी ान अच्छी हो सकती है और इससे किसानों और मजदूरों का भी भला होगा। बिजली आने से छोटी इंडस्ट्रिज डिवैल्प हो जाएगी। आज जो हरियाणा के किसान मजदूर मर रहे हैं उनको नया जीवन देने के लिये यह जरूरी है और वहां के कार्यकर्ताओं को भी देखा है। वे बडी ईमानदारी से दिन रात काम कर रहे है। मैनें उनसे पूछा कि यहां कोई डिस–औनेस्टी का तो काम ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस डैम का काम केवल चार आने ही बाकी रहता है लेकिन दूसरी तरफ जो हरियाणा का डैम बन रहा है उस पर 1974 से लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि इरीगे ान डिपार्टमैंट जितने यह डैम बनाता है और उसने दूसरे डैम भी बनाए है वह वहां उन मजदूरों को काम पर लगाए जो पहले काम कर चुके है। वहां पर अफसर भी अच्छे और ईमानदार भेजे जाएं। जितना जल्दी हो सके उस डैम को बनाया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर ऐक्साइज एंड टैक्से ान मिनिस्टिर साहब देगें लेकिन मैं

भी संक्षिप्त तौर पर कुछ बाते कहना चाहूंगा। मेरे दोस्त हुडडा साहब ने नाथपा झाकडी के बारे में एक बात बीच में इन्ट्रोडयूस कर दी। मैं इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने से पहले हुडडा साहब ने जो बात नाथपा झाकडी के बारे में कही है उसका संक्षिप्त रूप में जवाब देना चाहता हूं। हुडडा साहब ने कहा कि 1974 में नाथपा झाकडी डैम बनना भाुरू हुआ था जोकि हरियाणा को बहुत जल्दी बना देना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हैं कि नाथपा झाकडी डैम 1974 में बनना भाुरू नहीं हुआ था बल्कि इस डैम को बनाने के लिए हरियाणा और हिमाचल सरकारों का पिछले साल ही ऐग्रीमेंट हुआ है। उस डैम पर हिमाचल प्रदे ा ने इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम भाुरू किया था हमने तो उसमें कंट्रीब्यू ान दी है। इस डैम की फाईनैंस क्लीरेंस फाईनैंि ायल स्कीम के तहत गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास पैंडिग है जिसके बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद उस डैम का काम 1974 में भाुरू होने की बात कैसे कह दी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों की तरफ से बिजली के बारे में बात कही गई है कि किसानों पर बिजली की दर बढाई गई है। इस बारे में मैं संक्षिप्त में यह पूछना चाहता हूं कि बिजली की दर बढाने के बारे में बिजली बोर्ड ने अभी फैसला किया है। मैं बताना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ और भिवानी जैसे ऐरिया में जहां पर पानी बहुत गहराई में है वहां बिजली का रेट 10 रूपये पर हार्सपावर है। इसके बाद बिजली का फलैट रेट 14 और 16 रूपए है। इस तरह से बिजली

बोर्ड ने बिजली के फलैट रेट पर 4–4 रूपए इनक्रीज करने का फैसला लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त तौर में यह बात कहना चाहूंगा कि जिस इलाके में 10 रूपए पर हार्सपावर के हिसाब से बिजली का फलैट रेट था अगर आप उसका हिसाब लगाकर देखे तो किसानों को उस इलाके में 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से खर्चा देना पडता था जबकि बिजली के प्रोडक ान का खर्चा 50–60 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आता है। बिजली बोर्ड 40–50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से इतनी हायर सबसिडी दे रहा था। यह तो बिजली का फलैट रेट बढाया गया है यह तो स्लाइट इनक्रीज है जैसे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि अगले 5 सलों में तीनों स्लैब से केवल 15–16 करोड रूपए इकटठे होंगे जो बहुत मार्जिनल है। इसलिए यह कहना कि किसानों को बोझ के नीचे दबा दिया है किसान मरते जा रहे है ये सारी बाते निराधार है। इसमें कोई भाक नहीं है कि बात को बढा चढाकर कहना केवल मात्र प्रोपेगन्डा है। जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कांस्टीच्यू ानल ओबलीगे ान है उसको पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव असैम्बली में पे ा किया गया है। मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी कहा है कि इस प्रस्ताव के द्वारा कन्साइनमैंट टैक्स लगाने का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त तौर से मैम्बर साहेबान को बताना चाहूंगा कि सेल्ज आफ गुडज के अन्तर्गत जो सेल की डैफिनि ान थी उस डैफिनि ान के इनग्रेडिएटस के बारे बैटरले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल की डैफिनि ान में यह

होना जरूरी है कि transfer of property or goods one party to another. इसलिए जिन लोगों ने फरीदाबाद में अपने आफिस बनाए हुए है और वे अपनी चीजों को अपने हैड आफिस दिल्ली में अगर ट्रांसफर करें तो यह जो सेल्ज आफ गुडज का इनग्रेडिएंटस है वह पूरा नहीं होता था इसलिए वे टैक्स को अवाइड कर सकते थे और टैक्स नहीं देते थे। इस को बिज्र करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए पार्लियामेंट में भी कानून आया है। उसके बारे में यहां यह बात नहीं कही गई कि चूंकि इस कानून के बनने के बाद 100 करोड रूपये सेल्ज टैक्स के इक्टठे होंगे इसलिए नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट के लिए टैक्स के जरिए कोई पैसा इक्टठे करने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोडा स्पश्टीकरण देना चाहता हूं कि पार्लियामैंट में कानून पास होने के बाद यह अनुमान है ि एक साल में लगभग 40–50 करोड रूपया टैक्स का मिल सकेगा लेकिन यह जो 100 करोड रूपए का अनुमान है यह ठीक नहीं है। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट एसवाईएल नहर, जमुना नगर थर्मल प्लांट, हाईडल प्रोजैक्ट जमुनानगर हथनीकुंड बैराज और नहरों बगरैह के लिए अगले 5–6 सालों में हरियाणा को एक हजार करोड रूपए की धनरा ि ा की आव यकता है। वह आव यकता केवल 50 करोड रूपए साल की आमदन से पूरी नहीं हो सकती। हमें अपने लिए और अपनी आने वाली जनरे ाल के लिए बिजली और पानी की आव यकता को पूरा करने के लिए हर तबके को थोडी कमर कसनी पडेगी। इन भाब्दों के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस

प्रस्ताव के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है इसलिये इसको पास किया जाए।

श्रीमति चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सामने यह जो संविधान की 46वीं अमैंडमैंट को रैटिफाई करने के लिए प्रस्ताव आया है मैं उसकी ताईद करने के लिए खडी हुई और मैं समझता हूं कि यह चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार जितने टैक्स लगाती है जितनी ऐक्साइज डयूटी लगाती है और सेल्ज टैक्स लगाती है मैं हमे ाा इन इनडायरेक्ट टैक्सिज के खिलाफ रही हूं क्योंकि जो इनडायरैकट टैक्स है इनमें बहुत पिलफरेज होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो छोटे दुकानदार होते है उनको इन्सपैक्टर्ज तंग करते है और जो बडे दुकानदार हैं या कारखानेदार है उनसे रूलिंग पार्टी के लोग चन्दा लेते हैं। यह सरकार कहती है कि टैक्सिज के पैसे से हम स्टेट में डिवैल्पमैंट के काम करेंगे लेकिन वह पैसा डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्च नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इतने सालों के बावजूद भी आज यह उम्मीद दिखाई नहीं देती कि दे ा में डिवैल्पमैंट के कामों पर पैसा खर्च हो रहा है और दे ा में डिवैल्पमैंट के काम हो रहे है मैं तो यह कहना चाहती हूं कि इम्पीरियल टोबैको कम्पनी बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी कर रही है क्योंकि वह कम्पनी कांग्रेस पार्टी को खर्चा देती थी। (ाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मैडम यह उस समय की बात होगी जब आप कांग्रेस पार्टी में थी।

श्रीमति चन्द्रावतीः यह तब से है जब से आप कांग्रेस पार्टी में आए है। मैं उस समय की बात नहीं कह रही हूं। मैं जो भी बात कहती हूं वह जिम्मेदारी के साथ कहती हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझती हूं कि हरियाणा की आमदन में इस तरसीम के बाद टैक्स का बहुत अच्छा प्रभाव पडेगा। इसके अलावा में एक और बात यह भी कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फरीदाबाद में बडे बडे कारखानेदारों को किसानों से जमीन लेकर दी है सोनीपत में भी दो है और गुडगांवा में तो इस सरकार ने कारखानेदारों को अभी खैरात बख्शी है। जितना जितना उन्होंने चंदा दिया है उस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जमीन लेकर उनको दी है। कारखानेदार सेल्ज टैक्स का सारे का सारा पैसा या तो खुद हजम कर जाते है या दिल्ली ले जाते है। हरियाणा सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। हो सकता हैं मुझे डाउट हो पता नहीं इस अमैंडमैंट के बाद हरियाणा सरकार उन पर सेल्ज टैक्स लगा सकेगी या नहीं। कुछ पैसा तो प्राईवेट कौफर में जाता ही है और हो सकता है कुछ पैसा हमारे हरियाणा को भी मिल जाए। उसमें से डिवैल्पमैंट के कामों पर कितना पैसा खर्च करेंगे, वह बाद में देखने की बात है। इसके अलावा मैं किसानों को जब ट्रैक्टर खरीदना पडता है उसके बारे में कहना चाहती हूं। किसान लोग जब ट्रैक्टर लेते है तो उनको उस समय कोई रियायत नहीं होती है। लेकिन दुकानदार सारे **12.00 बजे** के सारे सेल्ज टैक्स को हजम कर जाते है। किसान लोग गवर्नमैंट से कर्जा लेते है लेकिन उस कर्जे में जो रियायत मिलनी चाहिए वह

नहीं मिल पाती। एजेंट बीच में की खा जाते है। किसानों तक वह रियायत नहीं पहंच पाती। कर्जे पर किसानों को जो सबसिडी मिलती है। वह भी किसान को नहीं मिलती। इसी तरह से किसानों को पूरे इम्पलीमैंटस नहीं मिल पाते। जो सेल्ज टैक्स गवर्नमैंट को जाना चाहिए वह भी पूरा नहीं जाता। इसलिए मैं ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर और को–ओपरे ान मिनिस्टर से दरखास्त करना चाहती हूं कि वे इस और अपना निजी ध्यान दे ताकि किसानों को पूरे इम्पलीमैंटस मिल सके उन्हें सबसिडी पूरी मिल सके या जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वह मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से हमारे यहां पर होटलज का महत्व दिन ब दिन बढता जा रहा है। कहीं पर फाईव स्टार होटल बनाये जा रहे है तो कहीं पर कुछ बनाये जा रहे है। रूस वालों को फाईव स्टार होटल पंसद थे तो उनकी नकल कर के हमारे यहां पर भी फाईव स्टार होटल बनाये जा रहे है। अग्रेंजों को या अमरिका वालों को और नाम पंसद थे तो उनके नाम पर कुछ और बनाये जा रहे है। मेरे कहने का मतलब यह हे कि हमारी अपनी ओरिजनैल्टी बिल्कुल ही नहीं रही है। हम हर चीज में दूसरे दे ाों की नकल कर रहे है। जापान से म ीने मंगवाई जा रही है। सरकार ने 46वां जो अमैंडमैंट किया है हो सकता है कि इसमें ये सारी चीजें कवर हो सके। इसलिए मैं इस अमैंडमैंट को तहेदिल से ताईद करती हूं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर सेल्ज

टैक्स की बहुत चोरी होती है जिसे रोका जाना बहुत ही जरूरी है। जो पैसा गवर्नमैंट के पास जाना चाहिए वह पैसा गवर्नमैंट तक नहीं पहुंच पाता। सारा पैसा बीच में ही रह जाता है। हमारे गांव में कहानी चलती है । चलती है क्या, सच्ची बात है। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव के अन्दर एक जमींदार रहता था। उसके चार बेटे थे और उनकी चार बहुंए भी थी। सारी की सारी बहुएं चोरी छिपे अनाज बेच दिया करती थी और अपनी अलग गांठ बना लेती थी। इसी प्रकार से उस किसान के जो चार बेटे थे वे भी खेत में से ही चोरी छिपे पुलियों के बेच देते थे और अपनी अलग गांठ बना लेते थे। इस प्रकार वे सभी के सभी अपनी अपनी अलग अलग गांठी करने लग गये। पहले तो वह घर कुछ दिन ठीक चला लेकिन जब सभी के सभी चोरी करने लग जाए तो उस घर का दिवाला निकल गया और इस परिवार पर कर्जा ही कर्जा हो गया। हमारे यहां पर गवर्नमैंट में जो आदमी बैठे हुए है उनमें वजीर भी हो सकते हैं और दूसरे कुछेक आफिसर्ज भी हो सकते है। वे सभी के सभी अपनी अपनी गांठी करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर ये गांठी करते रहे तो एक दिन इस सरकार का वही हाल होगा जो इस परिवार का हुआ है। यदि हमारे यहां पर सेल्ज टैक्स पूरी तरह से वसूल कर लिया जाये तो नए टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिवैल्पमैंट के काम तो सरकार को करने चाहिए। लेकिन गरीब तबके के उपर अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए। आप टैक्स बढा दें। लेकिन टैक्स बढाने से पहले आप प्रत्येक परिवार के कम से कम एक एक आदमी को रोजगार

अव य दें ताकि वे अपने परिवार का पालन पोशण कर सकें। उसके बाद आप बे ाक टैक्स बढा दे। हमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जमीन रबड तो है नहीं कि इसे बढा कर काम किया जा सके। जमीन हो या ट्रेजरी बैंचिज के जो आदमी है उनके पास ज्यादा जमीन हो। यदि उनके पास ज्यादा जमीन है भी तो वे ज्यादा से ज्यादा एक पीढी तक उस जमीन पर आसानी से खा सकेंगे। यदि आप सभी को रोजगार देकर टैक्स बढा देते हैं तो हम भी आपकी बात का स्वागत करेंगे। सरकार ने फरीदाबाद के अन्दर, सोनीपत के अन्दर और गुडगांवा के अन्दर किसानों की जमीन सस्ते भाव पर लेकर बडे बडे कारखानेदारों को दी है। यह कैसा इंसाफ है। गुडगांवा जिले के अन्दर तो जमीन लेने में हद ही कर दी है। मैं फिर यही कहना चाहती हूं कि किसानों सेल्ज टैक्स का पूरा फायदा देना चाहिए और सरकार को भी अपना पूरा पैसा वसूल करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स न लगाने पडे। अन्त में मैं फिर 46वीं अमैंडमैंट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, संविधान (46वां अमैंडमैंट) बिल रैटिफिके ान के लिए आया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। यह बात ठीक है कि हर चीज हरियाणा की लगती थी और उसका लाभ दूसरे सूबों को मिलता था। इंडस्ट्रीयलिस्टस तो यहां तक करते है कि वे इंडस्ट्री हरियाणा में लगाते है और लेबर बाहर से लाते है। दूसरी स्टेट से

लेबर लाने में हमें कोई एतराज नहीं है। वे भी हमारे ही भाई है। कोई विदे ाी नहीं है। लेकिन जब हमारे अपने ही हरियाणा के अन्दर बेरोजगारी हो, तो बाहर से लेबर लाने की क्या आव यकता है। सरकार की इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ठीक ढंग से कदम उठाये तो सेल्ज टैक्स से जो नुक्सान हो रहा है वह नहीं होगा और स्टेट को काफी फायदा होगा। मैं अपनी स्टेट के बारे में खासकर एक्साईज एण्ड टैक्से ान मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Please confine to the ratification of the Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill, 1982 now. You can have time again for this.

प्रोफैसर सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स की जो चोरी हो रही है यदि उसे रोक दिया जाये तो उससे स्टेट को काफी आमदनी हो सकती है। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि पीछे एक खबर आई थी कि एक्साईज एण्ड टैक्से ान मिनिस्टर के एक सिनेमा घर पर सोनीपत में छापा मारा गया। उस छापे के दौरान 700 टिकटों में से 500 टिकटें बिना टैक्स के पाई गई। (ाोर)

श्री बृज मोहन सिंगलाः डिप्टी स्पीकर साहब, वह छापा मैनें खुद मरवाया था। यदि मैं उस को रोकना चाहता तो पहले ही वहां सूचना दी जा सकती थी लेकिन हमने यहां पर स्कीम बनाईथी कि सिनेमा घरों पर छापे मारने हैं। (ाोर)

प्रोफैसर सम्पत सिंहः मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस बात को कबूल किया है लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि इसी प्रकार से सेल्ज टैक्स की या दूसरे टैक्सों की चोरी को न रोका जाये तो इससे स्टेट गवर्नमैंट को ही घाटा होता है। यदि हम खुद ही चोरी करने लगेंगे तो इससे सभी की बदनामी होगी। (ाोर एवं व्यवधान)

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh): On a point of order Sir. We are discussing the Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill 1982 and not holding any general discussion on Excise and Taxation.

मैं यह दरखास्त करना चाहूंगा कि इनको इस बात के लिए मिनिस्टर साहब को ऐप्रि ाएट करना चाहिए कि इन्होंने खुद अपने सिनेमा घर पर छापा मार कर टैक्स की चोरी को पकडा है। ये उनको कन्डैम कर रहे है। अपोजी ान को सारी चीजों की कन्डैम नहीं करना चाहिए जो ठीक बाते हो उसको ऐप्रि ायट करना चाहिए।

प्रोफैसर सम्पत सिंहः इस बात के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह छापा डलवाया। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जब 1 एकड 2 एकड 4 एकड 8 एकड या 10 एकड जमीन की जरूरत पडती है तो उतनी जमीन उसे दे दी

जाती है लेकिन देखने की बात यह है कि उस जमीन का वे करते क्या है? वे केवल चार दिवारी खींच लेते है और तार लगा लेते है। उनके सिर्फ इतने से काम के लिए किसानों को उजडना पडता हैं।

Mr. Deputy Speaker: This is not the matter under discussion. Let us confine ourseleves to the subject matter under discussion.

प्रोफैसर सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ में इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill, 1982 as passed by the two Houses of Parliament.

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: This has been carried unanimously.

वर्श 1982–83 के सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेटस (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान–

1. राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय में अनुमानों पर चर्चा

2. अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker: According to the previous practice and to save the time of the House, the demand on the order paper will be deemed to have been read and moved together and a general discussion on the supplementary demands is permited. The hon. members, however, are requested to indicate the demand No. on which they wish after the conclusion of the discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs.150000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 4 Revenue.

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डिमांड नं0 4 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। यह डिमांड 15 करोड रूपये की पे ा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मांग प्राकृतिक आपदाओं के कारण सरकार को पे ा करनी पडी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज सारे हरियाणा के दो तिहाई भाग में कहत है। कहीं ज्यादा पानी के कारण और कहीं सूखे के कारण किसानों की फसल तबाह हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुआवजे का जहां तक सम्बन्ध है आज भी करोडों रूपये का मुआवजा

लोगों को नहीं मिला है। सरकार को इसे जल्दी से जल्दी दिलाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं किसान दो तरीकों से अपनी खेती की सिंचाई करता है। एक तरीका नहरों से सिंचाई करने का है और दूसरा तरीका ट्यबवैल्ज से सिंचार्ठ का है। ट्यबवैल्ज से सिंचाई करने में किसान को नहरों से सिंचाई करने की अपेक्षा 10 गुणा और 15 गुणा ज्यादा खर्च करना पडता हैं लेकिन पिछली दफा जब सरकार ने कहत की वजह से किसानों को राहत दी तो किसानों का आबियाना तो माफ कर दिया लेकिन ट्यबवैल्ज से सिंचाई करने के लिए उन्हें जो खर्च करना पडता है। वह माफ नहीं किया। चाहे यह किसी की भूल से हुआ या जानबूझ कर हुआ लेकिन यह उनके साथ भेदभाव की बात है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरह के भेदभाव को दूर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि यह जो मुआवजा देने की बात है इस पर ठीक तरह से अमल नहीं हुआ है। आज भी करोडों रूपये का मुआवजा नहीं दिया गया है। भिवानी जिले में सिवानी आदि जगहों पर बंजर जमीन का भी मुकाबला दे दिया गया और कई जगहों पर जहां किसानों की ऐक्चुअली फसल नश्ट हुई थी वहां मुआवजा नहीं दिया गया। इस बात की सरकार जांच करवाए और जो अधिकारी इसमें दोशी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि जिस प्रकार ओलावृश्टि के कारण फसलों के बरबाद होने का मुआवजा दिया जाता है उसी प्रकार किसी भी प्राकृतिक विपति से नश्ट होने वाली फसलों का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पिछली बार ओलावृश्टि से होने वाली फसलों का तो मुआवजा दिया गया लेकिन किसी बीमारी के कारण जो फसलें नश्ट हुई थीं उनका मुआवजा नही दिया गया। (विघ्न)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): लोगों को चाहिए कि वे फसलों का बीमा कराएं।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, बीमा योजना तो ठीक है लेकिन उसमें किसान की पैदावार की पर एकड ईल्ड बहुत कम आंकी जाती है। इस योजना में कुछ इम्प्रूवमैंट करनी चाहिए। ऐवरेज ईल्ड के हिसाब से अगर बीमा दिया जाए तब तो कुछ फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे हरियाणा में सूखा पडा हुआ है। भिवानी जिला में तो 75 प्रति ात फसल बरबाद हो चुकी है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पिछले साल फसल में कीडा लगने की वजह से आज लोगों को बीज की भी दिक्कत है। अगर कीडा लगा हुआ बीज बोया जायेगा तो फसल में भी बीमारी लग जाती है। सावनी की फसल खराब हो गयी। बाजरा, मूंग, मोठ और गवार आदि को कीडा लग रहा है। उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से उसको दूर किया जा

सकता है। दूसरे जो कीडा लगने से उनकी फसल खराब हुई है उसका सरकार को मुआवजा भी देना चाहिए।

बिल्डिंग एण्ड रोडज की डिमांड 8 के विशय में भी थोडा सा अर्ज करना चाहता हूं। श्री जगजीत सिह, ड्राईवर रोड रोलर, को इस विभाग ने पहले तो सेवानिवृत कर दिया लेकिन बाद में उसे पैमेन्ट करनी पडी। उस गरीब ड्राईवर को अपनी तनखाह लेने के लिए मुकदमा करना पडा और मुकदमें में सरकार हारी और उसे 7425 रूपये देने पडे। वह गरीब आदमी मुकदमे में जीत चुका है परन्तु उसे आज तक पेमैन्ट नहीं की गई है। अगर सरकार उसके साथ पहले ही जस्टिस करती तो उसे अदालतों के चक्कर न काटने पडते। इसी प्रकार से सरकार ने जिला भिवानी के किसानों की जमीन एक्वायर की। यह भूमि जिला जेल के निर्माण हेतू ऐक्वायर की गई थी। किसानों को पूरा मुआवजा न देने से वे अदालत में चले गये। अदालत ने उसका मुआवजा बढा दिया। मुआवजा कम देने से किसान अदालतों में जाते है। और सरकार को बाद में दुगुनी तिगुनी पैमेंट करनी पडती है। अगर उन्हें पहले ही ठीक मुआवजा दे दिया जाये तो न किसान को कोर्ट में जाना पडे और न ही सरकार को जाना पडे। दूसरी बात इसमे यह है कि अदालतों में वही लोग जा सकते है जो साधन सम्पन्न होते है। गरीब व्यक्ति अदालतों में नहीं जा सकते और इसी कारण से वे बेचारे पूरा मुआवजा लेने से वंचित रह जाते है। मेरे नोटिस में यह भी आया है कि जो लोग हाई कोर्ट या

अदालतों में जाते है वही मुआवजा ले सकते है। आप हैरान होंगे कि सात–सात बार अदालतों में मुआवजा बढा है और उन लोगों के केसिज हाई कोर्ट में अब भी चल रहे है। इसका मतलब यह है कि जब कम्पनसे ान दिया जाता है तो वह ठीक प्रकास से जांच पडताल करके नहीं दिया जाता।

Mr. Deputy Speaker: Arya Sahib, please wind up so that the other Members may also get a chance to speak. This point was discusse at length yesterday also.

श्री हीरा नन्द आर्यः यह तो आपकी बात ठीक है कि कल भी इस पर डिस्क ान हो चुकी है लेकिन जो मिसाल मैंने दी है उससे साफ जाहिर है कि जमीन ऐक्वायर करते समय बहुत कम पैसे दिये जाते है। बाद में अदालतों से जीत कर लोग पैसा बढवाते है। अगर पहले ही ठीक पैसे दे दिए जाएं तो उन बेचारों को अदालतों के चक्कर न काटन पडें। जरूरतमंद लोगों को हैरासमैंट नहीं होनी चाहिए। बडे लोग तो अपील करके या मिल मिला कर पैसा बढवा लेते है लेकिन जिस आदमी की थोडी जमीन ऐकवायर होती है उसके पास साधन नहीं होते कि वह अदालत में पैसा खर्च कर सके और ठीक मुआवजा ले सके। इसी प्रकार से मोती लाल नेहरू के लिए जमीन ऐक्वायर की गई थी। उस केस में भी सरकार को चार गुना कम्पनसे ान देना पडा है। इसलिये मैंने सरकार के सामने ये सुझाव रखे है। सरकार इन सुझावों पर गौर करे तो बडी जल्दी से और सही मुआवजा दे सकती है।

श्री नर सिंह (पाई): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को राहत प्रदाने करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को 15 करोड रूपये की आनुग्रहिक राहत प्रदान की है। बडी अच्छी बात है। सरकार को करनी चाहिए। किसान सहायता के पात्र है। लेकिन किसानों को सहायता देते वक्त भी बडा पक्षपात बरता जाता है। कई इलाकों में तो उसकी वक्त सहायता दे दी जाती है यानि पैसा बांट दिया जाता है परन्तु कई इलाकों में आज तक भी पैसा नहीं बांटा गया। सन 1982–83 में 15 करोड रूपये की सहायता देने का प्रोविजन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी मेरी कांस्टीच्यूसी के काकोत, नरड सेगा आदि गांवों में सन 1981 में जो ओले पडे थे उनका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया। जब लोगों ने इस बारे में ि ाकायत की तो सरकार ने उस मुलाजिम को सस्पैंड तो कर दिया जिसने इस मुआवजा को नहीं बांटा था परन्तु उसको सस्पैंड करने का कोई लाभ नहीं। किसानों को आज तक एक पैसा भी मुआवजे का नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारि ा है कि इन गांवों को सन 1981 का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाये। मैंने आपके जरिए यह भी निवेदन किया है कि कुछ इलाकों में मुआवजा तकसीम करते समय पक्षपात बरता जाता है। जब सरकार ने हमारे इलाके में सन 1981 का मुआवजा नहीं दिया तो सन 1982 का मुआवजा कहां से देंगे। इस पन्द्रह करोड की रा ि ा को तकसीम करने में भी पक्षपात बरता जायेगा। जैसे आदमपुर कांस्टीच्यूसी में 15–20 दिन के अन्दर ही ओलावृश्टि से हुए नुक्सान का मुआवजा

दे दिय गया परन्तु पाई हल्के में सन 1981 तक का मुआवजा नही दिया गया। चार पांच गांव ऐसे हैं जहां पर ओलावृश्टि का मुआवजा सन 1981 का भी नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि चने का मुआवजा नहीं दिया जाता। आंधे हरियाणा में चने की बुआयी की जाती है लेकिन किसानों को पांच परसैन्ट भी मुआवजा नहीं दिया जाता। चने के बारे में लैन्ड का हवाला दिया गया। चने पर लैंड टैक्स और रैवेन्यू देते है लेकिन बहुत थोडा देते है। इस कारण से ही ओलावृश्टि का चने का कोई मुआवजा नही दिया जाता। किसान चने का मंहगे भाव का बीज डालता है खेत की बहायी करता है और उसका नुकसान होने का मुआवजा न दिया जाये तो गलत बात है। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि जिस तरह से दूसरी फसल नश्ट होने पर मुआवजा दिया जाता है इसी प्रकार से चने की फसल के लिये भी दिया जाना चाहिये।

इन भाब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 15 करोड रूपया बांटा जाये इसमें किसी के साथ पक्षपात न किया जाये ताकि हर एरिया के किसानों को समय पर राहत मिल सके।

श्री भागमल (सढौरा–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर 4, 8 और 10 पर बोलना चाहता हूं। सब से पहले मैं डिमांड नम्बर 4 पर बोलूंगा। डिमांड नम्बर 4 प्राकृतिक

आपदाओं के कारण राहत देने के बारे में है। जिस मतलब के लिये यह डिमान्ड रखी गई है बडी अच्छी है लेकिन मुझे थोडा सा अफसोस के साथ कहना पडता है कि यह नुकसान तो फरवरी और मार्च के महीने में हुआ लेकिन पेमैंट पूरी आज तक नहीं हो पायी। पेमेंट बहुत जल्दी होनी चाहिए। आप जानते है कि जब किसान की फसल नश्ट हो जाती है तो उसकी क्या हालत होती है। आप भी किसान है और आप किसान की हालत से वाकिफ है। मैं भी किसान हूं वह एक एक पैसे के लिए फसल नश्ट होने पर तरसता है। अगर उसे वक्त पर पैसा मिल जाये तो वह अगली फसल समय पर बो सकता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आगे के लिए प्रावधान किया जाये जब कि सर्वे हो जाये उसके साथ ही साथ पैसा बांट दिया जाना चाहिये।

मैं थोडा सा अपनी कांस्टीच्यूऐंसी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सढौरा और नारायणगढ में बिलकुल पानी का प्रबन्ध नहीं है। वहां पर न ट्यबवैल्ज है और न ही नहरों का पानी है। बारि ा पर ही डिपैन्ड करना पडता है। वहां इस साल बिल्कुल बारि ा नहीं हुई जिसके कारण इस साल के लिये प ाुओं के चारे का भी प्रबन्ध जमींदार न कर सकेंगे। मवे ि ायों के लिये बिल्कुल चरी नहीं है। वहां चारे का प्रबन्ध किया जाये। वह इलाका सूखागस्त है। इसलिये जिन लोगों की फसल सूख गई है। उन्हें मुआवजा दिया जाये ताकि वे लोग अगली फसल बोने का प्रबन्ध कर सके।

डिमांड नम्बर 8 जो भवन तथा सडकों के विशय में है, का भी समर्थन करता हूं क्योंकि यह पैसा भी नेक काम के लिये सरकार मांग रही है लेकिन सरकार उन गरीब किसानों को सीधे हाथों पैसा नहीं देती है। उन गरीब किसानों को यह पैसा कोर्ट में मंजूर करवाना पडता है तब जाकर सरकार देती है। सरकार को वह पैसा भी देना पडता है और साथ में इन्ट्रैस्ट भी देना पडता है कल भी यह बात आयी थी। इसीलिये मैं अपनी कल वाली बात पर एम्फेसाईज करूंगा और चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे मुताल्लिक अफसर साहेबान से भी यह कहूंगा कि वह जब किसी भी किसान की जमीन ऐक्वायर करें उस की जमीन की ठीक कीमत लगाये। अगर वे ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि भाायद किसी को कोई ग्रिवेन्स नहीं होगा और किसी को भी कोर्ट में न जाना पडेगा। आपने देखा है कि हमें काफी इन्ट्रैस्ट देना पड रहा है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो उसमें भी बच जायेगें। आमतौर पर जिसकी जमीन ऐक्वायर की जाती है वह गरीब किसान होता है अगर आप उसे पहले ही पूरा कम्पनसै ान दे दैंगें तो वह भी कोर्ट की दर दर की ठोकरे खाने से बच जायेगा।

आप के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां पर सडकों की बात है पिछली बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में यह आ वासन दिया था कि 31 मार्च 1982 तक सभी डायरैक्टरी विलेजिज को सडकों से जोड दिया जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हलके में अभी भी

कम से कम 30 गांव ऐसे होगें जो डायरेक्टरी विलेजिज है और वहां पर अभी तक भी सडक नहीं बनी है। ढानिया और माजरे तो अलग है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर सडकें जल्दी से जल्दी बनायी जाये।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः उनकी आबादी कितनी है।

श्री भागमलः वहां पर आबादी तो पूरी है वहां पर कुछ गांवों की आबादी तो डेढ सौ है और कुछ ऐसे भी गांव है जिनकी आबादी अढाई सौ है लेकिन अभी तक भी वहां पर सडक नहीं पहुंची है। चौधरी लाल सिंह जी को पता है कि मेरे इलाके में बहुत से ऐसे गांव है जहां अभी तक भी सडके नहीं बनायी गयी है। मेरे सरकार से यह प्रार्थना है कि वहां पर सडके बननी चाहिये। पिछली बार सरकार ने मेरे हल्के में कुछ पुल मजूंर किये थे वहां पर एक पुल बनाने के लिए दो लाख रूपये खर्च होना था उससे कम से कम 50 गांवों के लोगों को असुविधा होती है। वहां पर कोई बस सर्विस भी नहीं है। कृपया आप उस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाइये। इसके अलावा नारायणगढ, छछरोली, कालका और दूसरे इलाकों में भी जो पुल मजूंर हुए पडे है। उनको भी बनाया जाना चाहिये।

अब मैं डिमांड न0 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस डिमांड के अधीन 16500 रूपये हाउस से मांगे गये है।

इस को पढने से यह पता लगा है कि यह इसलिये मांगे गये है क्योंकि एक हमारे ड्राइवर की गलती की वजह से एक बूढा आदमी मर गया था। उसके परिवार वालों को उसका मुआवजा दिया गया है। यह बडी अच्छी बात है लेकिन इस बारे में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि हम रोज देखते हैं कि रोज ही इस तरह से एक्सीडेंट हमारे ट्रांसपोर्ट महकमें की कोताही या गलती के कारण होते रहते है। अफसोस की बात यह है कि कहीं पर 2000 रूपये तो कहीं पर 500 रूपये देकर उन बेचारों को टाल दिया जाता है। मैं सरकार को यह कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान देकर ड्राइवरों पर कुछ न कुछ कन्ट्रोल करे ताकि इतने जो एक्सीडेंट हो रहे है। वे न हो और अगर वाकई उनकी गलती की वजह से हो जाये तो उनको पूरा मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। मैं आपको अपनी कांस्चिुऐंसी के बारे में बताना चाहता हूं। बिलासपुर में चौक में ट्रांसपोर्ट की बस की वजह से एक स्कूल टीचर की डैथ हो गयी। उसको आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। डेढ दो साल हो गये है लेकिन आज तक भी उसे एक पैसा भी नहीं दिया गया है हालांकि उस केस की एफआईआर भी बिलासपुर में दर्ज है। इसलिये मेरा कहना यह है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैंट को उसके घर वालों को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिये जो बेवा है और पांच बच्चों की मां है। उसके लिए स्कूल टीचर्ज यूनियन ने भी रिप्रेजेन्ट किया हुआ है और मैंने भी इस मामले को टेक अप किया था। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस चीज को जल्दी से

जल्दी निपटाया जाये ।इन भाब्दो के साथ में इन डिमांडज का अनुमोदन करता हूं।

श्री निहाल सिंह (अटैली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कल भी इस बारे में थोडा सा अर्ज किया था कि जो कम्पनसे ान देने का तरीका है उसमें कोई न कोई सुधार होना चाहिये। अब तक जो तरीका है वह यह है कि लैंड ऐक्विजि ान अफसर लोगों को टाईम बता देता है कि मैं फलां दिन आउंगा। उस दिन सब लोग इक्टठे हो जाते है। अफसर टाईम पर पहुंचता नहीं है। क्लेमैंटस जो होते हैं वे वहां पर बैठे रहते है। पहली बात तो यह होनी चाहिये कि जो डेट उन अफसरो को देनी चाहिये उस दिन उनको हर हालत में टाईम पर पहुंचना चाहिये एक दूसरी जो इसमें सबसे ज्यादा गडबड होती है वह कै ा लैन्ड ऐक्विजि ान अफसर के हाथ में होने की वजह से होती है। वह उसके हथ में नहीं होना चाहिये। लैन्ड ऐक्विजि ान अफसर को यह पता होता है कि कौन कौन क्लेमैंटस है कितना कितना किसका कलैम है और कितना कितना किसका क्लेम बनता है या देना है। मेरा कहना यह है कि उनको कै ा देने की बजाये गर उनके घरों पर ही उस पैसे का ड्राफट या चैक बनाकर भेज दिया जाये तो उसके कई फायदें होंगे। एक फायदा तो यह होगा कि वहां पर लैन्ड ऐक्विजि ान अफसर जो कै ा अपने साथ लाता है उस झझंट से बच जायेगा। दूसरे क्लेमैंट को जितना पैसा मिलता है उसका पैसा बच जायेगा क्योंकिं वह पूरा पैसा घर नही ले जा पाता। आपके स्टाफ के जो

लोग है वे उससे कुछ न कुछ लेते है। तीसरे जो अफसरों का और क्लेमैंटस का समय बरबाद होता है वह भी बच जायेगा। इसके लिये किसी ला में अमैंडमैंट करने की जरूरत नहीं है ऐज्जैक्टिव इंस्ट्रक ान्ज से ही काम चल जायेगा। इसी तरह से जब लैंड ऐक्वायर की जाती है तो पहले दफा 4 का नोटिफिके ान इ ा होता है। गांव में बहुत से ऐसे अनपढ किसान होते है जिनको यह पता ही नही कि उनकी जमीन ऐक्वायर होने लग रही है। मैं यह कहता हूं कि सरकार को यह इंस्ट्रक ान जारी करनी चाहिए कि जो भी जमीन ऐक्वायर की जायेगी उसके बारे में पटवारी जाकर हरके किसान को घर में बतायेगा कि उसकी जमीन ऐक्वायर होने जा रही है ताकि उसे पता हो। उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अमीर चंद मक्कड (हांसी): डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 4 में जो 15 करोड रूपया मांगा गया है यह किसानों को कम्पनसे ान देने के लिये मंागा गया है इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इस बारे में इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ओलावृश्टि का मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। मेरे हल्के में बहुत से ऐसे गांव है। जहां पर यह मुआवजा अभी दिया नहीं गया है। मेरा कहना यह है कि यदि सरकार देना ही चाहती है तो उसे पूरा मुआवजा देना चाहिये। इसके अलावा जो सूखा पड रहा है उसके बारे में कोई कम्पनसे ान देने की बात नहीं की जा रही है। मैं यह चाहता हूं कि सूखे के लिये भी सरकार को

कम्पनसे ान देना चाहिये। अन्त में मैं गुजारि ा करूंगा कि यह जो मुआवजा दिया जा रहा है मेरे हल्के में जिन लोगों को अभी दिया जाना है उनको जल्दी से जल्दी तकसीम करवाया जाना चाहिये। धन्यवाद ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल (मुढांल खुर्द): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो 15 करोड रूपया दिया जा रहा है यह बहुत अच्छी बात हो रही है। मेरा कहना यह है कि ओलो की वजह से ही फसलें बरबाद नहीं होती दूसरी वजूहात से भी फसलें बरबाद होती है। चने की 99 फीसदी फसल भीत लहर की वजह से बरबाद हुई है। उसके कम्पनसे ान के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। कत्ल चाहे उसके कम्पनसे ान के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। कत्ल चाहे बन्दूक की गोली से हो या छूरे से कत्ल तो कत्ल ही होता है। किसान की फसल तो बरबाद हो गयी। जिस एकड में 2000 रूपये का अनाज पैदा होना था आज वहां पर 2000 पैसे का भी नहीं है। इसके बारे में हमारे आनरेबल मिनिस्टर महोदय यह कहते है कि क्रौप इन्सोरेंस का लाभ उठाये। इस कम्पनसे ान को देने का सिलसिला जनता सरकार ने आज से 5 साल पहले भाुरू किया था जो कि ओलों की वजह से था कि जिसका नुक्सान हो जाये उसको 400 रूपये प्रति एकड दिया जाये। इसके अलावा यह प्रोविजन भी किया जा सकता है कि यदि भीत लहर की वजह से चने की फसल बरबाद होती है तो उसको भी मुआवजा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री महोदय

यहां पर कहते है कि मैं किसान का बेटा हूं और अपने आपको किसानों का बडा हमदर्द कहते है। मैं यह चाहता हूं कि इसके लिये भी उनको कुछ न कुछ प्रोविजन करना चाहिये। जिला सिरसा में, हिसार में और महेन्द्रगढ में चना खूब बोया जाता है। 1981 में जो चने की फसल भीत लहर से बरबाद हुई है उसका एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया और कहा जाता है कि भीत लहर की वजह से मुआवजा देने का प्रोविजन नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, उस भीत लहर से किसान तो मारा गया किसान ने अपनी लडकी की भाादी करनी है। अगर उसको कोई कम्पनसे ान नहीं दिया जाता तो वह बरबाद हो जाता है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से ओलों का कम्पनसे ान देने का प्रोविजन है उसी तरह से भीत लहर का भी प्रोविजन कर दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी गिरदावरी हुई है वह गल्त हुई है। ऐग्रीकलचर मिनिस्टर ने कहा कि गिरदावरी नहीं बदली जा सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार बदल सकती है लेकिन गिरदावरी नहीं बदली जा सकती। यह कितने अफसोस की बात है। मेरा कहना यह है कि दुबारा से स्पै ाल गिरदावरी करवाई जाए और जिन लोगों को कम्पनसे ान नहीं मिला है उनको दुबारा से कम्पनसे ान दिलाया जाए। किसान के लिये आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। चने के नुक्सान का किसान को एक पैसे का कम्पनसे ान नहीं मिला और यह सिर्फ गलत गिरदावरी की वजह से नहीं मिला है। आपके दिल में किसान के

प्रति सिम्पथी होनी चाहिए। मेरी अन्त में यही प्रार्थना है कि सरकार किसान को मुआवजा देने की कृपा करें।

Mr. Speaker: Now I will put the demand to the vote of the House.

Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs.150000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 4 Revenue.

The motion was carried.

(At this stage the Mr. Speaker occupied the chair)

दि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982

Excise and Taxation Minister (Shri Brij Mohan): Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill, 1982.

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज मुझे डा0 मंगल सैन की ओर से पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982 की डिसएप्रुवल के लिये नोटिस मिला है। यदि हाउस सहमत हो तो हाउस का समय बचाने के लिए इस

प्रस्ताव पर तथा बिल की कंसीड्रे ान मो ान पर इक्टठा विचार कर लिया जाए। ये दोनों मो ान्ज वोट के लिए अलग अलग पुट की जायेगी।

Voices: All right, Sir.

श्री अध्यक्षः डा0 साहब आप अपना मो ान मूव करें।

Dr. Mangal Sein: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 3 of 1982).

Mr. Speaker: Motion moved-

Excise and Taxation Minister (Shri Brij Mohan): Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 3 of 1982

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Now the House will hold discussion on both these motions together. Dr. Mangal Sein may please be now speak.

डा0 मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज सदन में पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट

बिल 1982 जिसके बारे में गवर्नर साहब ने आर्डिनेन्स जारी किया था वह बिल की भाक्ल में हाउस के सामने पे ा है। मैं आपके द्वारा चौधरी भजन लाल से कहना चाहता है कि कुछ अच्छी रिवायतें डालनी चहियें। * * * * स्पीकर साहब, उन्होंने पहले फरमाया था कि आप 20 तारीख को आ जाना .....

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन जो बात कहते है उसके पीछे और भी भाव होता है। इन्होंने कहा है * ** * ** है उसके पीछे कुछ और भी भाव होता है। इन्होंने कहा है * ** * ** गवर्नर के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि गवर्नर के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है वह कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, डा0 साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। कोई डेरोगेटरी भाब्द गवर्नर के बारे में नहीं कहे है। ऐक्सपंज करने की इसमें कोई बात नहीं है।

डा0 मंगल सैनः मैनें कोई ऐसे भाब्द इस्तेमाल नहीं किए है .....

श्री अध्यक्षः जो कुछ आपने कहा है वे उसका सैन्स यह निकलता है कि जो भी कागज गवर्नर साहब के पास जाता है बगैर पढे उस पर दस्तखत कर देते हैं। (ाोर एवं विघ्न)

डा0 मंगल सैनः मेरा मतलब यह है कि जो भी कागज ये भेजते है उस पर वे दस्तखत कर देते हैं।

श्री अध्यक्षः आपके कहने से सैन्स तो यही जाहिर होती है कि गवर्नर साहब बगैर किसी कागज को पढे दस्तखत कर देते है। गवर्नर साहब के बारे में जो कुछ कहा गया है वह ऐक्सपंज कर दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ऐक्सपंक ान के भी कुछ रूल्ज है। यह नहीं होना चाहिये कि जो मुख्यमंत्री चाहें कि यह बात ऐक्सपंज कर दी जाए उसको ऐक्सपंज कर दिया जाए। ऐक्सपंज करने के बाकायदा रूल्ज है और उनके हिसाब से ऐक्सपंक ान होनी चाहिये जब तक कोई वर्ड अनपार्लियामैंटरी इस्तेमाल न किया जाए तब तक ऐक्सपंज करने को कोई सवाल नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः फर्ज कीजिए कि आप यह कहें कि चीफ मिनिस्टर जो कुछ स्पीकर साहब, को कहते हैं स्पीकर उनको हां कर देते है। इसका मतलब क्या यह नहीं निकलता कि स्पीकर बगैर सोचे समझें हां कर देता है और क्या वह स्पीकर के उपर ऐसप ान नहीं है।?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यहां यह कहा गया कि जो कुछ मैं कहता हूं उसका कम्पाउन्ड मीनिंग निकलता है कुछ और अर्थ निकलता है। मैं बडी सिम्पल बात कहता हूं। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं कि उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि जब विधान सभा बैठने वाली है and the people's representatives have been summoned he must take care that

he should not promulgate any such ordinance in the State at such a point of time. जब सदन की बैठक होने जा रही है तो वह बात सदन में भी आ सकती है। वह सब से बडी अथोरिटी है। मैंने जो कुछ कहा है वह भोले भाव से कहा है। मैं उनकी नियम पर कोई भाक नहीं करता। मैं उनसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कहना चाहता हूं कि यह रौंग ट्रैडि ान है रौंग प्रैसिडैंटस डाल रहे है। उनको पता है कि सै ान आ रहा है अखबारों में चौधरी भजन लाल बयान दे चुके है कि दो दिन का से ान होगा या तीन दिन का सै ान होगा। (ाोर व व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह एक गलत प्रैसिडेंट है। गवर्नर साहब को असैम्बली के उपर टैक्स बढाने के आर्डर भी इ ा कर दिये और चौधरी भजन लाल जी ने बहाना यह लगाया कि चूंकि दूसरी पडौसी स्टेटस से भाव बढे है इसलिये हमने अपने पडौसी राज्यों की तरह भाव बढा दिये है। भजन लाल जी क्या हमारे काम भी पडोसी राज्यों की तरह कर लोगें?

चौधरी भजन लालः उस से भी आगे।

डा0 मंगल सैनः हां आपकी बात ठीक है दूर दूर तक आप की चर्चा है। सारे अखबारों में, वीकलीज में, मन्थली अखबारों में आपके नाम के बडे चर्चा है। वे अखबार आपकी बडी ही तारीफ करते है। और अगर कहीं बाहर जाएं कोई हमसे गल्ती से पूछ बैठे कि भाई कहां के रहने वाले हो तो हम कहते है बडे फक्र के साथ कि हरियाणा के रहने वाले है तो वे आगे हंस कर कहते है कि

अच्छा उस हरियाणा राज्य के जहां के लोग होलसेल पर बिकते है। (हंसी एवं भाोर) तो मैं कह रहा था कि स्पीकर साहब, कि ये कहते हुए भार्म आ रही है। (ाोर व व्यवधान) तो मैं कह रहा था स्पीकर साहब, कि ये कहते है कि चूंकि पडोसी राज्यों में भाव बढे हैं इसलिये हमने भी बढा दिये है। ये अपने पडोसी राज्य दिल्ली की नकल करते है। भजन लाल जी दिल्ली की क्या नकल करोगे दिल्ली में जो हो रहा है क्या वह आप पर पाओगे। वहां पर तो लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हनी है। 24 घंटे लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है और यहां पर किसानों को बिजली नहीं मिलती उपर से टैक्स लगाये जाते है खून चूसा जाता है फैक्ट्रियों में इसी कारण से गरीब मजदूरों की छटनी की जाती है। पांच पांच घंटे यहां पर किसानों को बिजली से वंचित रहना पडता है। लोगों के खेत प्यासे पडे हुए है लोग इसी कारण से दुखी है और सरकार को कोस रहे है। महेन्द्रगढ के इलाके में आप जाकर के देखिये कि वहां पर किसानों का कितना बुरा हाल है बिजली नहीं मिल रही और दूसरा वहां पर कहत पडा हुआ है। लोगों को सुविधाओं से तो वंचित रख रहे है सुविधाएं तो दे नहीं सकते और दूसरी तरफ लोगों के उपर टैक्सों का बोझा लाद रहे है।

स्पीकर साहब, एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो हातम ताई की कब्र पर भी लात मार दी। बसों का किराया बढा दिया और बसों की हालत तो आपको स्पीकर साहब,

पता ही है आप की कांस्टिचुऐंसी पेहवा है। आपको पता है कि उस रूट पर चलने वाली बसों की हालत क्या है। स्टेयरिंग पर दो दो आदमी बैठते है। एक स्टेयरिंग पर बैठता है और दूसरा इंजन पर हाथ रख लेता है क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि कहीं गेयर बाक्स वगैरह नीचे न गिर जाएं। खिडकियां जो है वे गमियों में खुलती नहीं और सर्दियों में बन्द नहीं होती। बुरी तरह से बसें टूटी फुटी है। कील बाहर को निकले पडे है और गरीब लोगों के कपडे फाडे जा रहे है। सीटस टूटी फुटी पडी है। मेरा कहने का मतलब यह था कि बसों की मेन्टेनैस तो कुछ है नहीं और उधर से किराये भाडे में वृद्धि की गयी है। कितने अफसोस की बात है कितनी भार्म की बात है हमारी सरकार के लिये। दूसरी तरफ आर्डिनैंस भी जारी कर दिया। (विघ्न) यह बात, भाई भजन लाल जी आपने तो खुद ही फरमाया है कि हमारी पार्टी तो एक समुद्र है इसमें जितने भी मैम्बर्ज चाहें वे समा सकते है। आपको आन्ध्रप्रदे ा का पता है वहां पर क्या हुआ? 6 महीने के बाद चुपके से इन्दिरा जी ने चीफ मिनिस्टर की छुटटी करके दूसरा चीफ मिनिस्टर बना दिया। भजन लाल जी आप भी सब सो के उठोगे तो अखबारों में पढोगे कि Bhajan Lal is replaced (हंसी व भाोर)।

चौधरी भजन लालः डा0 साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर भजन लाल चला गा तो आप भी नहीं बन सकते। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः भजन लाल जी, हमने तो कभी इस बात की ख्वाहि ा भी नहीं रखी। हमने तो कभी आपकी तरह दोस्तों से धोखा भी नहीं किया और न ही हमने पार्टी बदली है। हम तो जहां पहले खडे थे वहीं पर खडे है। जनता पार्टी के आगे हमने तो भारतीय जोड दिया है। स्पीकर साहब, पहले तो ये इंदिरा जी को कहा करते थे कि पहले नसबन्दी फिर सांस बन्दी। (ाोर)

चौधरी भजन लालः यह गलत बात है। यह बात बिल्कुल निराधार है।

डा0 मंगल सैनः गलत नहीं है ठीक है। 5 सितम्बर 1979 को स्टेज पर गुडगांव में जो स्पीच आपने दी थी उसको पढकर देखो। बाद में कहने लगे कि माता जी हम तो रूठ गये थे। आपके बालक है अब लौट कर अपने घर आ गये है। हमें भारण दीजिये। पर स्पीकर साहब, न जाने बालक कब रूठ जाए लेकिन हमें इससे क्या लेना है आप का मां बेटे का झगडा है लेकिन यह जो ड्रामा रचा रखा है यह अच्छी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह था कि यह जो जनता के उपर फजूल का बोझा डाला जा रहा है यह उचित नहीं है। गरीब लोग इससे पिस रहे है। गरीब किसानों को अनुसूचित जातियों के लोगों को छोटे वर्गो के लोगों को सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहते है कि साहब हमको पैसा चाहिये। किस बात के लिये चाहिये। बोर्डो के चेयरमैनों को तनख्वाह देने के लिए बोर्डो

के कारपोरे ानज के चेयरमैन बढवाने के लिए पैसा चाहिये। उनको भत्ता देने के लिए पैसा चाहियें। (ोर)

चौधरी भजन लालः डा0 साहब आप अपने वक्त को याद करो।

डा0 मंगल सैनः हमारा वक्त तो टेम्पोरेरी था, भजन लाल जी, हम उसको क्या याद रखें। चौधरी देवीलाल जी को जल्दी से जाना पडा। (ोर) अगर आप हमारी वजारत में भाामिल न होते तो हमारी वजारत बडे आराम से चलती।

चौधरी भजन लालः जब आपको डिसमिस किया गया, तो आपकी हमदर्दी में मुझे आना पडा।

डा0 मंगल सैनः भजन लाल जी हमें इस कुर्सी का कोई अरमान नहीं है मगर आप जैसे दोस्तों से भी दगा कर गये हम नहीं करते। तो मैं स्पीकर साहब कहने जा रहा था कि सरकार को नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट के लिये वर्ल्ड बैंक से लोन लिये बिना काम चलाना कठिन होगा लेकिन जो आपने यह मंत्रियों की फौज इक्टठी कर रखी है उसको कम कीजिये और तभी खर्चा कम होगा और स्टेट का भी भला होगा। अब आपके पास दल बदलू बहुत पंहुच गये है। आपको किसी का डर तो रहा नहीं, उनको आप यह कहो कि यह चेयरमैन लगने वाले चक्कर छोडो आपको हम इधर ले आये है। आप सेफ हो, इसलिये आप हमारी मदद के लिये तैयार रहो। आप उन्हें समझाओं कि इस तरह करने से स्टेट का

पैसा यूं ही बरबाद होगा। इधर तो इनका ध्यान जाता नहीं है और दूसरी तरफ गरीब हरियाणा की जनता को बोझ के नीचे दबाने जा रहे है। इन अलफाज के साथ यह कहता हुआ कि हमारे गवर्नर महोदय ने जो यह आर्डिनेंस बेवाजिब मौके पर गलत समय पर और गल्त प्रैसिडेंट कायम करते हुए इ ा किया है मैं उसका अपने भाब्दों पर इम्फेसिज डालते हुए विरोध करता हूं और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः साहेबान, अभी हाउस के सामने विजनैंस काफी है और अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घण्टा बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी, बढा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय एक घंटे के लिये बढाया जाता है।

पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्ससे ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982 (पुनरराम्भ)

डा0 भीम सिंह दहिया (रोहट): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन जी ने बिल के विरोध में जो प्रस्ताव यहां सदन के सम्मुख रखा है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं।

इसलिये नहीं कि चूंकि हम लोग विरोधी दल से संबंधित है इसलिये हमें इसका विरोध करना ही है। बल्कि इस बिल के विरोध करने के बडे अच्छे कारण है जिनकी वजह से हमें इस प्रस्ताव का समर्थन करना पड रहा है। गवर्नर साहब को इस समय जबकि असेम्बली का सै ान चल रहा है। इस आर्डिनेंस को जारी नहीं करना चाहिये था। ऐसा करके उन्होंने इस हाउस का अपमान किया है। डैमोक्रेसी का अपमान किया है। अगर सरकार को किसी काम के लिए पैसा चाहिये होता है तो सरकार उसके लिये कोई न कोई कारण बताती है। कि इस काम के लिये हमें पैसा चाहिये। लोगों की भलाई के लिये पैसा चाहिये। किसी डिवैल्पमैंट के काम के लिये पैसा चाहिये लेकिन इस बिल के अन्दर ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि सरकार को इस कारण से पैसे की आव यकता है। बिना वजह लोगों पर टैक्स लगाना यह कहां तक उचित समझा जा सकता है ? दूसरी बात यह है कि जो कैबिनेट फैसला करती है, उनके पास तो सरकार द्वारा दी हुई कारें होती हैं उन्हें तो किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं हेाती क्योंकि कारों में पैट्रोल खर्च होता है वह सरकार की तरफ से दिया जाता है और फिर ये ऐक्युअल खर्चा भी कलमे करते हैं। दूसरी तरफ हम अपोजी ान के एम.एल.एज. हैं। अगर हम अपनी कारों में भी आएं तो फिर भी हमें रेलवे का किराया दिया जाता है। अगर इन बातों को भी टच न किया जाए, मैं आपको बताता हूं कि जो हरियसाणा सरकार के बड़े बड़े अफसर हैं, वे भी गाड़ियों में जाते हैं, उनको कार के हिसाब से भाड़ा मिलता है। जहां तक किसानों

का सम्बन्ध है वे बेचारे सारा खर्चा अपने पास से ही करते हैं। अगर ट्रैक्टर चलाएंगे तो उसमें डीजल पड़ेगा और अगर ट्यूबवेलज चलाते हैं तो उन्हें बिजली की दर देनी पड़ती है जिससे बेचारा किसान पहले ही हर तरफ से सरकारी बोझ` दब ताजात है ओर अब दूसरी तरफ इस आर्डिनैस के जरिये इस बिल के जरिये ही बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसलिए किसानों के ऊपर और ज्यादा बोझा न डाला जाए। सरकार के पास पैसा इकट्ठे करने के और बहुत से साधन है। जो 46वीं अमैन्डमैंट की गयी है, उस बारे में भी यह कहा गया है कि इस से सरकार को सालाना 100 करोड़ रूपये की आमदनी होगी फिर हमें समझ नहीं आता कि यह टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है ? इन कारणों की वजह से मै। अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से डाक्टर मंगल सैन जी ने जो प्रस्ताव पे ज्ञ किया है, उसका समर्थन करता हुआ तथा आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

13.00 बजे

श्री भले राम (बड़ौदा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आज सारा दे ा जानता है कि हरियाणा कि गति से प्रगति कर रहा है। हमारे साथी हर रोज मांग करते हैं कि सड़कें, बिजली और पानी वगैरह की सहूलियत दी जाए। इसलिए ऐसी सुविधाएं देने के लिए अगर हमारी सरकार थोडा बहुत टैक्स बढ़ाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज डा. साहब कह रहे थे कि हरियाणा में किस ढंग से लूट खसूट हो रही है। उनके समय में भी

इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बने थे जो बाद में चौधरी देवी लाल ने तोड़ दिये थे। डा. साहब को याद होना चाहिए कि उस समय किस तरीके से चेयरमैन लगाये गये थे। (ाोर) आखिर मुख्य मंत्री जी ने सारी स्टेट की तरक्की के बारे में देखना है, यह कोई दुकान थोड़े ही है। विकास कार्य करने के लिए टैक्स का लगाना भी बहुत जरूरी है। आज लोग ट्यूबवैलन कनैक ान के लिए और घरेलू कनैक ान के लिए बिजली की मांग करते हैं, बसों में एम.एल.एज. की चलते हैं इसलिए अगर थोडा बहुत टैक्स बढ़ा दिया है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। यह कोई ज्यादा टैक्स नहीं है। आप दूसरी स्टेटस कमा मुकाबिला करके देखें। आप दिल्ली और पंजाब का ही मुकाबिला कर लें इनसे फिर भी हरियाणा में टैक्स कम ही हैं। जब आप यह मांग करते हैं कि हमें फलां चीज चाहिए तो उसके लिए टैक्स तो लगाना ही पडेग। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मनफूल सिंह (असन्ध अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये जो यह टैक्स बढ़ाने जा रहे है, यह गल्त है। किसान और मजदूरों पर टैक्स लगाने की बजाए आप मिनिस्टरों, एम.एल.एज. और चेयरमैंनों की तनखाहें कम करें। गरीब आदमियों को तो वैसे ही मारा जा रहा है। जैसे स्वीपर कम चौकीदार व माली कम चौकीदार इतनी मेहनत का काम करते हैं लेकिन तनखाहें उन्हें एक पोस्ट की ही देते हैं और वह भी 10–15 दिन लेट देते है। मैं इस हक मे हूं

कि जो टूरिजम कम्पलैक्स हैं उनमें रेट बढ़ा कर जो कमी है वह पूरी की जाए ताकि गरीब लोगों पर बोझ न पड़े।

श्री भागी राम (एलनाबाद अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, डा. मंगल सैन जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सै न भ्रारू होने से पहले जिस प्रकार से इन्होंने डीजल, पैट्रोल, मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ाए हैं और बसेां का किराया बढ़ाया है, यह हमारे प्रदे ा के किसान, मजदूर, हरिजन और कमजोर वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाला गया है। किसान लोग आज भी डीजल खरीदने की हैसियत में नहीं है। और अब से पहले जो बसों का किराया था वह भी देने के काबिल नहीं। लोग जब इतनी मजबूरी में हैं तो यह टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए थे। भले राम जी दस दिन पहले इधर बैठ कर खूब गूंजा करते थे लेकिन आज कहते हैं कि ये टैक्स लगने चाहिए। भले राम जी यहां रैस्ट हाउस में बैठ कर आपको कुछ पता नहीं चलेगा आप बड़ौदा में जाकर लोगों से पूछें कि उनकी क्यार हालत है ?

श्री अध्यक्ष: भागी राम जी आप चेयर को ऐड्रैस करें।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर अच्छे कामों के लिए पैसा चाहिए तो उसको इकट्ठा करने के बहुत तरीके हैं। आप यह ही देखें कि आज कितने मिनिस्टर हैं। हमारे सिरसा जिला के तीन मिनिस्टर है। कोई भी दिन ऐसा

नहीं जाता जिस दिन सिरसा रैस्ट हाउस में सारे अफसरों की लाइन न बनी रहती हो। वे बेचारे परे ाान रहते हैं और इन मिनिस्टरों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये रोजाना वहां बैठे रहते हैं। इनके अलावा कभी चीफ मिनिस्टर साहब चले जाते हैं और कभी भाम ोर सिंह जी चले जाते है। ये कभी किसी की भाादी में जाते हैं, कभी किसी के लड़का हो गया तो भी जाते हैं, किसी ने दुकान का मुहूर्त करना है तो भी जाते है। इन प्राइवेट कामों के लिए भी ये सरकार से टी.ए.डी.ए. लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बड़े समझदार हैं, आप भजन लाल जी से कहें कि वे एक तो ये मिनिस्टरों की फौज छोटी कर लें और दूसरे अन्य खर्चों में कमी करें। इन्होंने जो चेयरमैन बना रखे है उनकी गाड़ियां बाजार से आलू, टमाटर और प्याज लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी को दो पैस की एक माचिस भी चाहिए तो भी गाड़ी पर ही लाई जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार जो नाजायज खर्चे खुद करवा रही है, उनको कम करे। ये अपनी तनखाह में कमी कर लें और टी.ए.डी.ए. न लें। अगर भजन लाल जी की मिनिस्टरी यह अनाउंस कर दे कि हम भी अपनी तनखाह नहीं लेंगे तो बे ाक ये टैक्स लगा लें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तनखाह तो क्या छोडनी है ये तो उस दिन का भी टी.ए.डी.ए. लेते हैं जब ये किसी के लड़के के नामकरण पर जाते है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा. मंगल सैन जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और भजन लाल जी से भी एक अपील करता हूं कि इस फौज को छोटा करो और यह जो टैक्स लगाया है, इसको

वापिस लो ताकि लोगों का भला हो सके। चीफ मिनिस्टरी हमे ाा नहीं रहती और इन मिनिस्टरों ने भी हमे ाा नहीं रहना। यहां पर नेहरा साहब बैठे हैं, ये सिरसा के हैं। ये मुझे कहा करते थे कि हम तो मजबूर हैं हम कुछ नहीं कह सकते, आप ही कुछ बात कहो (ाोर)। ये कहा करते थे कि सिारसा के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, हम तो मजबूर है, कुछ कह नहीं सकते इसलिए आप ही कहा करो। (ाोर)

ि ाक्षा राजय मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भागी राम जी ने ऐसी बात कही है जिसका अंडर कंसिड्रे ान मामले से कोई संबंध नहीं है। हाउस में यह चर्चा चल रही है कि सेल्ज टैकस लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, लगाया जाए तो किनता लगाया जाए अगर नहीं लगाया जाए तो क्यों नहीं लगाया जाए ? मेरे माननीय साथी ने इस तरह की बात कही है जो सदन में भाोभा नहीं देती। (ाोर)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, यह मेरे से गलती हो गई कि मुझे प्राइवेट बात नहीं कहनी चाहिए थी वह मैंने कह दी। वह बात मैं आयंदा नही बताऊंगा।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दि पांजब मोटर स्पिरिट (टैक्से ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982 के कालम नम्बर 2 की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भाक नहीं कि

मौजूदा सरकार, श्रीमति इंदिरा गांधी जी की सरकार, किसानों के हित के लिए बहुत कुछ कर रही ह। आज किसानो की हाल पिछली सरकार के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। किसानों को तरह तरह के प्रोग्रामों के द्वारा पूरी इमदाद देने की कोि ा ा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले आई.पी.एम. साहब ने बताया था कि एस.वाई.एल. का कार्य दो साल में कम्पलीट कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर हरियाणा के किसानों की जान है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है किसानों के गुण गाने वाले चौधरी देवी लाल जी ने आज यह कहा कि एस. वाई.एल. नहर खोदने की कोई जरूरत नहीं है। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हाउस में मिस कोट किया जा रहा है। चौधरी देवी लाल जी ने ऐसा नहीं कहा। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर आपके पास इतनी कैंपेसिटी अवेलेबल है कि जो पानी हरियाणा के हिस्से में आया है उसको लाया जा सकता है फिर चैनल खोदने का क्या मतलब है। उनका यह मतलब नहीं था कि चैनल न बानई जाए ओर चैनल की कोई जरूरत नहीं है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी आप भी एडवोकेट हैं और मैं भी एडवोकेट हूं। आपने भी सुना होगा। बे ाक उनका मतलब यह नहीं था लेकिन उन्होंने यह कहा था कि एस.वाई.एल. बनाने की क्या जरूरत है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर लें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः रिकार्ड तो मैं चैक कर लूंगा। (ाोर)

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, चोधरी देवल लाल जी श्री प्रका ा सिंह बादल के साथ यह तालमेल किए हुए हैं कि एस. वाई.एल. नहर को खोदने दिया जाए। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप माननीय सदस्य को समझााएं कि ये हाउस में गलत बयानी न करें। (ाोर)

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, चौधीर देवी लाल जी ने यह कहा कि एस.वाई.एल नहर खोदने के लिए एक करोड़ रूपया मैंने दिया था। अगर उन्होंने एस.वाई.एल नहर खोदने के लिए एक करोड रूपया मंजूर किया था तो यह आज कैसे कह दिया कि उस नहर को बगैर खोदे पानी लाया जा सकता है। एक तरफ तो चौधरी देवी लाल जी कहते है कि उस नहर को खोदने के लिए मैंने एक करोड़ रूपय दिया था और दूसरी तरफ से वे नहर को न खोदनै के लिए श्री प्रका ा सिंह बाद के साथ तालमेल किए हुए हैं। (ाोर एवं विघ्न)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी ने तो यह कहा था कि जो 3.5 एम.ए.एफ. पानी हरियाणा को मिल रहा है उसके लिए नहर की जरूरत नहीं है। (ाोर)

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अगर पर्सनल एक्सप्लेने ान देनी है तो चौधरी देवी लाल जी दें। उनकी पार्टी के मैम्बरों को बोलने की क्या जरूरत है ? (ाोर)

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, दरअसल बात यह है कि चौधरी देवी लाल जी के सबसे नजदीक मैं हूं। मैंने उनकी सारी बात सुनी थी। ये लोग उनकी बात को क्लीयर करके उनकी लीडरि ाप को खतरा पैदा करना चाहते हैं। (ाोर)

श्री निर्मल सिंह: इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो चौधरी देवी लाल जी कहते हैं कि एस.वाई.एल. नहर के खोदने के लिए मैंने एक करोड़ रूपया दिया था और दूसरी तरफ वेउस नहर को न खोदने के लिए श्री प्रका ा सिंह बादल के साथ तालमेल किए हुए हैं और नहर रोका मोर्चे को स्पोर्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के न खुदने के कारण 1977 से 1980 तक किसानों को जो सैटबैक लगा है वह लोकदल के लोगों ने लगाया हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार अगले पांच सालों में किसानो के हित के लिए एक हजार करोड रूपया दे रही है। एक डिवैल्पमैंटल स्टेट के लिए यह भी जरूरी है कि टैकस लगाए जाएं या बढाए जाएं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बिल की क्लाज 2 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके जरिए टैक्स बढाया जा रहा है। इस टैक्स के बढने से

इसका किसानों पर असर पडेगा। हरियाणा के किसान कहत और ओला वृश्टि के कारण पहले ही बहुत दुखी है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार किसानों की तरफ पूरा ध्यान दें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता डा. मंगल सैन जी ने जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के आर्डिनैस के विरोध में पे ा किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, यह सदन हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए और उनकी वफादारी के लिए समझा जाता है। अध्यक्ष महोदय, सनकार की अपनी रिपोर्ट होती है जो रेवेन्यू डिपार्टमैंट से इकट्ठी करवाते है। उसमें 85, 75 और 60 परसैंट खर्चा दिखाया है। यह सरकार के रिकार्ड के मुताबिक साबित होता है कि रेवेन्यू का 60 परसैंट किसानों पर खर्च किया जाता है। ऐसे मौके पर जबकि विधान सभा के सै ान की तारीख मुकरर्र हो चुकी थी उसक बावजूद भी इन्हौंने राज्यपाल महोदय से आर्डिनैंस जारी करवा दिया। जब सै न की तारीख मुकरर्र हो जाए तो उसके बाद आर्डिनैंस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है तथा सरकार सीधे तौर पर बिल सदन में ला सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे डा. मंगल सैन जी ने कहा है कई बार सरकार भूल जाती हैं। जैसे गवर्नर साहब ने हमें 22 तारीख को 24 तारीख को आने के लिए कहा परन्तु उससे पहले ही

उन्होंने चौधरी भजन लाल जी को मुख्य मंत्री बना दिया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सिानों के साथ, मजदूरों और गरीब लोगों के साथ उनको बिजली न दे करके बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। किसानों को समय पर बिजली न मिलने के कारण उनकी मौजूदा फसल तो खराब हो चुकी है और अगली फसल की भी बिजली की सप्लाई के बिना बिजाई नहीं हो सकती। हरियाणा की बिजली एि ायाई खेलों में चली जाएगी और जो बाकी रहेगी वह 35 चेयरमैनों और मंत्रियों के कमरे ठण्डे करने में चली जाएगी लेकिन इस सरकार को किसानों की फसल की कोई चिन्ता नहीं है। जो लोग चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं वे अपने मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन उनको किसानों की कोई चिन्ता नहीं है। इनके 35 चेयरमैनों और मंत्रियों के पास सरकारी गाडियां है। उनके बारे में अभी मेरे से थोड़ी देर पहले बोलने वाले मेरे साथी चौधरी भागी राम जी ने कहा था कि इन लोगों की गाडियां मार्किट से माचिस और प ाुओं के लिए चारा लेने के लिए जाती हैं। मेरे पास दो गाडियों के नम्बर हैं एच.वाई.ए. 28 और 39 जोकि चारा लेने के लिए जाती है। उनको देख कर लोग कहते हैं कि यह हरियाणा सरकार जा रही है। स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदे ा की सारी पूंजी को बर्बाद किया जा रहा है। स्पीकर साहब, यदि टैकसों की चोरी को रोक लिया जाये तो टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आज हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में पैट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े जबकि हरियाणा के अन्दर आज की सरकार ने इनके भाव

बढ़ा दिए है। स्पीकर साहब, हमें अपने प्रदे ा के लोगों की समस्याओं की भी चिन्ता करनी चाहिए। उन पर नाजायत वजन नहीं डालना चाहिए।

श्रीमति भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, 39 नं. गाड़ी मेरी है। अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि 39 नं. गाड़ी के अन्दर चारा वगकैरा लाया जाता हैं जबकि मेरे पास कोई भी प ाु नहीं है। इनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा: बहन जी मेरी मन्ा ाा आपके प्रति कुछ कहने की नहीं है। यदि ऐसी बात हैं तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं।

चौधरी वेदपाल: स्पीकर साहब, 28 नं. गाड़ी का भी जिक्र किया गया है। यह मेरी गाड़ी का नं. है। मेरे पास भी न कोई भैंस न कोई गाय है। इसलिए उसमें चारा आदि लाने का कोई प्र न पैदा नहीं होता।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं स्पे ाली इन गाड़ियों क बारे में नहीं कह रहा था। मैं तो एक जनरल बात कह रहा था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के मुख्यमंत्री किस तरह बने हैं यह तो सभी को मालूम है। मुख्य मंत्री बनने के लिए इनके पास टैक्नीकल प्वायंटस हैं। लेकन आप मुख्य मंत्री हमे ाा नहीं रह सकते। आपको मुख्य मंत्री होने के साथ साथ जनता का सेवक हो

कर जनता की सेवा करनी चाहिए। आज हरियाणाके किसी भी कारखाने के अन्दर उत्पादन नहीं बढ़ रहा। डेयरी डिल्वैपमैंट में 39 लाख रूपये का घाटा है। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी संस्थाएं हैं वे सभी की सभी घाटे में जा रही है। किसी भी संस्था में मुनाफा नहीं है। सरकार को इन संस्थाओं के बारे में गम्भीर रूप से सोच विचार करना चाहिए। सरकार को इन संस्थाओं को घाटे से निकालने के लिए कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। जब भी इनकों पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोगों पर टैक्स बढ़ा देत है ो ठीक बात नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के नाजयज टैक्स गरीब लोगों पर न डाले जाएं। स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार टैक्स के जरिए पैसा बढ़ा रही है लेकिन दूसरी तरफ उसका रख रखाव ठीक नहीं रखा जा रहा। मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि वह अपने सभी डिपार्टमैंटस पर चैक रखें ताकि पैसे की फिजूलखर्ची न हो सके। मेरी मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि वह आनी मंत्री परिशद को छोटा करें। अन्त में मैं जो प्रस्ताव डा. मंगल सैन जी की ओर से हाउस में रखा गया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए तथा जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से उसाक पुरजोर विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हाउस में लाया गया है। यह सारे प्रदे ा की तरक्की के लिए लाया गया है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लाया गया है।

इस बात को सभी जानते है कि जिस प्रदे ा के अन्दर नए नए प्रोजैक्ट लगाये जा रहे हों उसे पेसे की आव यकता होती है। यदि उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए मामूली मात्रा मं टैक्स जनता पर डाल दिया जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो पैसा हम टैक्स के लिए जरिए इकट्ठा कर रहे हैं या करेंगे, उससे किसानों के हित के लिए तथा हरियााणा प्रदे ा की जनता के हित के लिए ही काम करना है। डा. मंगल सैन ने एक बात और कही कि जब सै ान आ रहा था तो आडिनैंस करने की क्या आव यकता थी ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जब ऐक्ट बनता है तो उसे सर्कुलेट भी करना होता है। इस बात को भी सभी साथी जानते हैं कि जब किसी ऐक्ट को बनाया जाताहै तो उसको न जाने कितने हाथों में से निकलना होता है। यदि वह लीकेज हो जाये तो उससे कई उद्योगपति या दुकानदार काफी फायदा उठा सकते है। इसलिए लीकेज न हो, इस बात की तरफ भी ध्यान देना होता है। हमने जो डीजल और पैट्रोल के भाव बढत्राए हैं वे दूसरी स्टेटों से कम ही भाव पर बढ़ायें है। मैं आपको साथ लगते प्रान्तों के भाव बता देता हूं। दिल्ली के अन्दर पैट्रोल का भाव 6 रूपये 60 पैसे प्रति लीटर है। हम 7 प्रति ात रेट बढ़ाने की कह रहे हैं जबकित वास्तविक रूप से 6 प्रति ात ही बढ़ाया है। इस 6 प्रति ात सेल्ज टैकस से हरियाणा में पैट्रोल 6 रूपये 60 पैसे प्रति लीटर होगा। यू.पी. के अन्दर 6 यपये 18 पैसे है और राजस्थान के अन्दर 6रूपये 58 पैसे है। इसलिए इस टैक्स के लगाये जाने के बावजूद भी हमारे यहां पर पैट्रोल के भाव

दूसरी स्टेटों से कम है। इसी प्रकार से डीजल का भाव पहले 2रूपये 96 पैसे प्रति लीटर था, अब टैक्स लगाने से डीजल का भाव 3 रूपये 2 पैसे हो जायेगा। दिल्ली में डीजल 3 रूपये 12 पैसे है, यू.पी. में 3 रूपये 17 पैसे है और राजस्थान में 3 रूपये 26 पैसे है।

डा. मंगल सैनः पंजाब में क्या रेट हैं ?

चौधरी भजन लालः पंजाब मं 2–3 पैसे कम है लेकिन वे भी बढ़ाने जा रहे है।

डा. मंगल सैनः हिमाचल में क्या भाव है ?

चौधरी भजन लालः हिमाचल मे और भी ज्यादा है ? वहां की बात अलग है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहां पर एस.वाई.एल. का मामला है। इस पर 200 करोड़ रूपये की लागत आनी है। इसी प्रकार से नाथपा झाकड़ी प्रौजेक्ट पर 800 करोड़ रूपये खर्च होने है। 1 हजार करोड़ रूपये के करीब इन दोनों प्रोजैक्टस पर खर्च होना है। जो पैसा खर्च होगा वह इस प्रदे ा की जनता के लिए खर्च होगा और किसानों के लिए खर्च होगा। पानी ज्यादा आयेगा ओर बिजली ज्यादा आयेगी तो किसान भाई अपना उत्पादन अधिक बढ़ा सकते है। बिजली ज्यादा होगी तो उद्योग ज्यादा लगेंगे और उत्पादन अधिक बढ़ेगा। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोडे बहुत टैक्स बढ़ा भी दिये जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी टैक्स लगाने पड़ते हैं वे

प्रदे ा की जनता के हित के लिए ही लगाने पड़ते है। इन पर माननीय सदस्यों को कोई आपति नहीं होनी चाहिए। यह कहना कि इन टैक्सों से किसान पर ज्यादा वजन बढ़ जायेगा, गलत बात हैं घर के लिए जो बिजली दी जा रही है वह 60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से घर पड़ती है जबकि किसानों को बिजली 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है। अब जो बिजली की दर बढाइ गइ है उससे जो अन्तर होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं। जहां पहले 10 रूपये खर्चे के आते थे अब 14 रूपये आ जायेंगे। जहां पर 14 रूपये आते थे वहां पर 16 रूपये खर्चे के आएंगे और जहां पर 16 रूपये आते थे अब वहां पर 20 रूपये आ जायेंगे। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो टैक्स हमने बढ़ाये हैं वे सोच समझकर बढाये हैं। सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाये। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड ने यह भी सुविधा दी हुई है कि फलैट रेट्स के साथ साथ कोई भी व्यक्ति चाहे तो मोटर लगा सकता है और चाहे तो मीटर लगा सकता है। उसको सारी सुविधा उपलब्ध है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। फलैट रेट्स की सभी को सुविधा दी गई है। बिजलजी बोर्ड 20 करोड़ रूपये का घाटा प्रति वर्श उठा रहा है। बहन चन्द्रावती, आर्य साहब, वीरेन्द्र सिंह जी तथा दूसरे साथी सरकारों में रहे हैं। उन्हें पता है कि सरकार को किस तरह काम करना पड़ता है।

आवाजें: चोरी बहुत बढ़ रही है।

चौधरी भजन लालः आप सभी सरकारों में रहे है। आप अपना हिसाब निकाल लें और हमारा हिसाब देख लें। उस समय के मुकाबले में अब बिजली की कम चोरी हो रही है। मैं यह बात मानता हूं कि चोरी हो रही है। यह नहीं कह रहा कि चोरी बिल्कुल हो ही नहीं रही। हमने इस चोरी कीा रोकने के लिए कदम उठाये हैं। किसी तरह बिजली की चोरी न हो उसके एिल सैल भी स्थापित किए गए है। उनमें ईमानदार आफिसर लगाये गए हैं। फरीदाबाद के अन्दर जहां पर चोरी अधिक होती थी उसको रोकने के लिए भी हमने वि ोश दस्ते नियुक्त किए हैं और ईमानदार आफिसर्ज की वहां पर ड्यूटी लगाई है। चोरी को या कुरप्ान को बिल्कुल तो परमात्मा भी आ जाये, वह भी बंद नहीं कर सकता। (विघ्न) कितनी भी कोि ा ा करो तो भी यह बंद नहीं होगी। (विघ्न) लेकिन हमारी कोि ा ा यह है कि कम से कम चोरी हो ओर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। यह बहुत नौमिनल टैक्स है और इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि फैक्टरी ओनर्ज और दूसरे वर्गों के लोगों पर भी पड़ेगा। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is:-

That this House disapproves the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 3 of 1982)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is:-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों में बसों का भाड़ा 60 प्रति ात बढ़ चुका है और इस भाड़े के बढ़ने से मुद्रा, स्फीति को बढ़ावा मिलता है। किसानों का डीजल महंगा हेाता है। उन्हें दूसरी चीजें भी महंगी मिलती है। परिणामस्वरूप उनकी पैदावार भी महंगी हो जाती है। पिछली बार मार्च के सै ान में सरकार ने बिना टैकस का बजट पे ा किया था। हमनेउस समय संदेह व्यक्त किया था कि यह सरकार पीछे के पर्दे से लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है। वह बात आज सामनेआ गई हैं। इसके अलावा इन्होंने इस टैकस को आर्डिनैंस के जरिए लगाया है। जब असैम्बली का सै ान होन जा रहा था तो इन्हें इस टैक्स को आर्डिनैंस के द्वारा नहीं लगाना चाहिए था।

यह एक अप्रजातांत्रिक कदम है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन को बताएं कि पिछले चार सालों में मोटर का भाड़ा बार बार बढ़ाने के बावजूद इन्होंने मोटरों में क्या इम्प्रूवमैंट की है ? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में इन्होंने क्या सुधार किया है और लोगों को क्या नई सुविधाएं दी हैं ? अगर कोई सुविधा नहीं दी है तो इन्हें इस टैकस को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसे ये अब भी वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, इस 100 करोड़ रूपये के टैक्स का गरीब जनता के उपर बहुत बोझ पडेगा। (विघ्न)

आवकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृज मोहन): अध्यक्ष महोदय, इससे 100 करोड़ की नहीं बल्कि 20 करोड़ रूपये की इन्कम होगी। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अखबारों में सिनेमाज में सेल्ज टैक्स चोरी की वजह से लगभग 10 लाख रूपये के घपले की बात आई थी। हाउस को इस बारें में बताया जाना चाहिए कि यह बात कहां तक सच है ? (विघ्न) अखबारों में तो यह भी लिखा था कि मुख्य मंत्री जी सम्बन्धित मंत्री का जल्दी ही पता काटने वाले हैं (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिनेमाज में सेल्ज टैक्स की चोरी का सम्बन्ध है, इसके एिल तो इन्हें बजाये क्रिटिसाइज करने के लिए मंत्री जी की फराखदिली की दाद देनी चाहिए। इन्होंने खुद मीटिंग करके यह फैसला किया

कि सिनेमाज के टिकटों की बिक्री में जो गड़बड़ होती है उसकी सब जगह चैंकिग करवाई जाए और सबसे पहले इन्होंने अपना सिनेमा चैक करवाया। इसके लिए मैं इनको दाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बसों का ताललुक है, आप दूसरे प्रान्तों में जाकर देखें और फिर हरियाणा प्रान्त की बसों से मुकाबला करें। हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया बस सर्विस अगर कोई है तो वह हरियाणा प्रान्त की है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगरकोई बस पुरानी हो जाती हे तो उसमें नुक्स भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी ब्रेक डाउन सबसे कम हरियाणा प्रान्त की बसों का होता है। माननीय सदस्यों की बात किसी आधार पर कहनी चाहिए। ये यों हो क्रिटिसिजम न करें। ये अगर ठीक बात कहें तो उसका उत्तर भी दिया जा सकता है लेकिन यदि ये यों ही बात कह दें और केवल क्रिटिसिज के लिए। क्रिटिसिजम करें तो वह वाजिब बात नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज से चार साल पहले जिस चैंसी की कीमत डेढ़ लाख रूपये थी उसकी कीमत आज अढाई लाख रूपये है। आप जानते हैं कि जब इन चीजों की कीमतें बढ़ती है तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा भी हमें बर्दास्त करना पड़ेगा। सरकार इसे घर से नहीं देगी, क्योंकि सरकार भी तो लोगों की है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्स का ताल्लुक हैं, मैं यह दावे से कहता हूं कियह अब भी हिमालच और दूसरे प्रदे ाों से कम है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीरक साहब, मैं एक निवदेन करना चाहता हूँ

श्री अध्यक्ष: अब तो मुख्य मंत्री जी जवाब दे चुके हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): मैंने केवल एक सुझाव देना है। अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारि ा यह है कि आज तो टैक्सों की चोरी होती है अगर उसे बंद कर दिया जाए तो नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहां सिनेमाज में सेल्ज टैक्स चोरी का जिक्र आया। इसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके सिनेमा में यह जो सेल्ज टैक्स का पैसा बचाया जाता था यह मंत्री जी के घर जातात था या वर्कर्ज लोग अपने घर ले जाते थे ? (विघ्न) सरकार दे। चार वर्करों को हटा कर उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। चोरी रोकन के लिए मालिकों को सजा दी जानी चाहिए। ऐसे सिनेमाज के लाईसैन्स कैन्सल कर दिये जावें।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृज मोहन): अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी कथित सिनेमा में कोई दखलअन्दाजी नहीं है। न तो मैं वहां रहता हूं ओर न ही वहां जाता हूं। जहां तक टैक्स की चोरी का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि मैंने

स्वयं आफिसर्ज की मीटिंग बुलाई थी और यह फैसला किया था कि सिनेमाज में जो सेल्ज टैकस की चोरी होती है उसक पकड़ा जाना चाहिए। एक दिन में कम से कम 50 सिनेमा घरों पर रेड हुआ होगा और कई सिनेमाज में टैक्स की चोरी पाई गई। अगर मेरे सिनेमा में भी किसी ने कोई गड़बड़ की होगी तो उसको भी सजा मिलेगी।

दि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्से ान आफ सेल्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1982 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is:-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Brij Mohan): Sir, I beg to move:-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

The Bill be passed.

श्रीमति चन्द्रावती (बाढ़ड़ा): स्पीकर साहब, आज हमारे सामने पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्रय कराधान) हरियाणा सं ाोधन विधेयक, 1982 है। यह जो टैक्स बढ़ाने के बारे में बिल है, इसका विरोध करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। आज के दिन हम हर चीज पर टैकस बढाने और कीमत बढाने की बात करते हैं। मैं यह मानती हूं कि मोटर सर्विसीज, साउथ का तो मुझे पता नहीं लेकिन नौर्दर्न स्टेट्स में हरियाणा की मोटर सर्विस अच्छी है। लेकिन जब आप बरसात के दिनों में बस में सफर करें तो आपने देखा हेागा कि सभी बसों की छतें चूती है, छाता ले कर बैठना पड़ता है। किसी भी बस में ऐक्सट्रा टायर नहीं होता। अगर कहीं पर बस खराब हो जाती है यानी टायर फट जाता है तो दो तीन घन्टे तक यात्रियों को रूकना पडता है। मैं यह भी कहूंगी कि बसों के ऐक्सिडैंटस इन्ऐफिसिऐन्सी के कारण ही होते है। जो पुर्जे बसों के

लिए खरीदे जाते हैं वे खराब किस्म के लेते हैं लेकिन उनकी कीमतें ज्यादा देते हैं। खराब पुर्जे होने से वे स्ट्रैस को बरदा त नहीं करते। जब भी कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है, मोड़ता है तो वे पुर्जे स्ट्रैस को बरदा त नहीं करते जिसकी वजह से सैंकड़ों जाने गई है। कितने ही खतरनाक ऐक्सिडैंटस हुए है, उनमें ड्राइवर की भी गलती होती है लेकिन ज्यादातर पुर्जे खराब होने की वजह से ऐक्सिडैंटस होते हैं क्योंकि वे स्ट्रैस बरदा त नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से अच्छे पुर्जे नहीं खरीदे जाते हैं और कीमतें ज्यादा दी जाती है। कहा जाता है कि बसों में चोरी होती है लेकिन आपको पता है कि आयर और पार्टस खरीदते वक्त भी चोरी होती है। अगर चोरी बन्द हो जाये तो काफी लाभ हो सकता है। बसों में काफी भीड़ चलती है इसलिए हमें अधिक बसें चलानी चाहिए। आपको यह भी पता है कि चोरी और ऐक्सिडैंटस के मामले मे सबसे पहले कन्डक्टर और ड्राईवर के खिलाफ ऐक ान लिया जाता है। ड्राईवर और कन्डक्टर को सस्पैन्ड और टर्मिनेट किया जाता है लेकिन किसी बड़े अफसर को आज तक किसी मामले में सस्पैन्ड और टर्मिनेट नहीं किया गया।

जहां पर अन काउन्टिड मनी होता है वहां पर हेरफेर बेईमानी अव य होती है। बड़े बड़े अफसर भी बेईमानी करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई एक ान नहीं होता। जब बड़ा अफसर

बेईमानी करता है तो आप कन्डक्टर से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह बेईमानी न करे।

जहां तक भीड़ का सम्बन्ध है, वह बहुत ही अधिक मात्रा में बसों में होती है। सवारियां छतों पर बैठ कर जाती है। जब दूसरी बस नहीं होगी तो छतों पर ही बैइ कर जायेंगी। भीड़ को खत्म करने के लिए सरकार को अधिक बसों का प्रबन्ध करना चाहिए या बसों का टाईम ओर ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सवारियां छतों पर इसलिए बैठती हैं कि उन्हें दूर दूर जाना होता है। अगर उनकी वह बस निकल जाये तो रात को उन्हें वहीं पड़ा रहना पड़ेगा। भााम के समय भीड़ अधिक मात्रा में होती है। आखिरी बस में 25 परसैन्ट अधिक सवारियां बैठाने की इजाजत होनी चाहिए। दूसरे आप जानते हैं कि हमारा दे ा गर्म है। गर्म दे ा होने के कारण आडीनरी बसों में परदे लगने चाहिए ताकि धूप न लगे। बसों में औरतें और बच्चे भी सफर करते है। धूप में वे पड़े परे ाान होते है। इसलिए आम बसों में भी परदे लगने चाहिए। जहां आप ओर फिजूलखर्ची करते हैं अगर बसों में परदे लगा दिये जाये तो आम व्यक्ति को भी सुविधा हो सकती है। हरियाणा भवन मं दीवारों पर कारपैट लगवाना चाहते हैं लेकिन बसों में परदे नहीं लगवाते। आपको कारपैट लगवाने से पहले भारत के मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए था। यहां की कलाइमेंट कैसी है ? यें कारपैट सूट करेंगै या नहीं। अगर आप किसी को ओबलाइज करना चाहते थे और उसके कारपैट खरीदना चाहते थे तो उसे कोई ऐक्सपोर्ट

का लाइसैंस दे देते लेकिन ऐसे दीवारों पर कारपैट लगवाने का क्या लाभ है। आप किसी मिनिस्टर के घर पर कारपेट रखवा देते लेकिन हरियाणा भवन में लगवा कर लोगों को गर्मी से क्यों मार रहे हो। अगर आप किफायत करें तो यह मोटर स्पिरिट ऐक्ट लाने की कोई आव यकता नहीं है। आप खामख्वाह ही लोगों पर टैक्स लगाने जा रहे है। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट और बिजली का ऐसा महकमा है जिनमें ईमानदारी से काम हो तो बहुत अधिक बचत हो सकती है। आपको इन दो महकमों से इतनी बचत हो सकती है कि आपको बजट का लगभग 1/2 भाग प्राप्त हो सकता है ब ार्ते कि इनमें चोरी न हो और ईमानदारी से काम हो। इन भाब्दां के साथ मैं इस बिल का विरोध करती हूं।

परिवहन मंत्री (कर्नल रावराम सिंह): स्पीकर साहब, वैसे तो हाउस के सामने बिल दूसरे विभाग का है परन्तु बहिन जी ने ट्रांसपोर्ट विभाग के विशय में कई बातें कहीं हैं इसलिए उनका उततर देना जरूरी है। (श्रीमति चन्द्रावती जी की ओर से विघ्न) बहिन जी जब आप बोल रही थी उस समय मैंने कोई दखलअन्दाजी नहीं की। मैं चुपचाप भाान्ति से आपकी बात सुनता रहा। इसलिए आप बीच में न टोके। आप मरी बात को सुने। आपको बोलने का पहले मौका मिल चुका है, उस समय मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। स्पीकर साहब, बहिन जी काफी पुरान और तजुर्बेकार मैम्बर है। इन्होंने कुछ बातें प्वायंट आउट की हैं

और कुछ अच्छी सुजैस ांज भी दी है लेकिन काफी बातें इररैलेवैंट कही हैं जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इन्होंने ऐक्सिडैंटस की बात कहीं कि पुर्जे पुराने और कमजोर किस्म के लगे हुए होते हैं इसलिए ऐक्सिडैंटस होते है। इन्होंने यह भी कहा कि वे स्ट्रैस को बरदा त नहीं कर सकते। बहिन जी ने कौन सी इन्कवायरी की है कि अच्छे पुर्जे लगे होते। मैंने दो चार इन्कवायरी की हैंकि ऐक्सिडैंटस क्यों होते है। मै। बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदे ा में लौयस्ट ऐक्सिडैंटस हुए है। सब प्रदे ाों से कम हुए है। मैं यह बात फैक्ट्स और फिगर्ज के आधार पर बता रहा हूं। जहां तक प्रौफिटेबिलिटी का सवाल है, पिछले दो सालों से हरियाणा रोडवेज लौस में जा रहा है वरना हरियाणा रोडवेज इज दी ओनली पब्लिक अन्डरटेकिंग, जो अब तक प्रौफिट में चलती रही है। सारे दे ा की ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिग्ज लौस में चल रही है। (विघ्न) चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह तो पुराने टाईम की बात बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जब ये आई.पी.एम. होते थे, तब इन बसिज की कन्डी ान अच्छी होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः जब से नै ानेलाईज हुई हैं तब से ही ट्रान्सपोर्ट की कन्डी ान अच्छी रही है।

कर्नल राव राम सिंहः अच्छा, अच्दी तो तब से ही चली आ रही है लेकिन ऐक्सिडैंटस हमसे ज्यादा होने लगे है। यह तो

बड़े ही ताज्जुब की बात है। ऐक्सिडैंटस का रेट पिछले 5 सालों में हमारा दूसरों के मुकाबला में लोएस्ट है। ओवर काउडिंग की जो बात यहां पर कही गयी हे, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि इस वक्त ओवर क्राउडिंग है। उसके बारे में मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि हमारा फलीट इन्क्रीज हो रहा है। तकरीबन 200 नई बसिज हम इस सल ऐक्सट्रा ऐड कर रहे है। आने वाले दिनों में एि ायाड के खेल भी होने वाले है। हमे उसमें भी कुछ बसिज देनी पड़ सकती हैं। उस वजह से भाायद प्रौब्लम कुछ ऐक्सैन्चुएट हो जायेगी। मैं यह आ ाा करता हूं कि आनरेबल मैम्बर्ज मेरे से बेयर करेंगे कि हरियाणा के लिए यह एक बहुत फख्र की बात है कि हमें 300 बसें इनकमे लिए देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ओवरक्राउडिंग की प्रौब्लम ऐक्सैन्चुएट होगी। अन्त में मैं बहिन जी को वि वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये है ट्रान्सपोर्ट महकमा उन पर पूरा विचार करेगा।

प्रो. सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यदि कोई ठोस बात कही जायेगी तो वे उसाक जवाब देंगे। मैं एक दो बातें जो मैं समझता हूं कि काफी ठोस है, कहना चाहता हूं। मेरा और इनका जिला एक ही है। मैं भी इनके ही जिला में रहता हूं। फतेहाबाद से नोहर भाहर जो राजस्थान में पड़ता है वहां पर जाने के लिए एक रैगुलर टाईम जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था वह 8 बजे का था, वह एक प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट ओनर को देकर 20 लाख रूपये

साल की जो वहां से कमाई हो रही थी, उसको खारे दिया गया है। उस ट्रान्पोर्ट ओनर का सीधा सरकार से सम्बन्ध है। उसको यह रूट और टाईम देकर सरकार को लगभग 20,00,000 रूपये का नुक्सान हुआ है।

कर्नल राव राम सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अर इन्होंने कोइ इल्जाम लगाना है तो नोटिस दे ताकि हम उसके बारे में बता भी सकें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आप इनको बोलने दो, मेरा अपना जिला है, मैं इसका जवाब अच्छी तरह से दे दूंगा। मुझे इसकी जानकारी है।

प्रो. सम्पत सिंहः आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा साथ साथ लगते हैं और आपस में एक दूसरे के यहां से बसें चलाते है। वहां पर एक बजकर 30 मिनट पर दो ट्रैनज आकर क्रौस करती हैं। हरियाणा और राजस्थान की आपस में रि तेदारियां हैं, इसलिए लोग बहुत इधर उधर जाते आते रहते हैं। उस ट्रेन के कारण से हमारी बस में 100 सवारियां अगर अन्दर होती थी, तो 100 सवारियां ऊपर चढ़ी होती थी। इससे भी सरकार को हर साल 15–20 लाख रूपये की कमाई होती होगी। इन्होंने क्या किया है ? 1.30 टाईम की बजाये अपना टाईम 1.20 का कर दिया और प्राइवेट बस को 1.40 का टाईम दे दिया। इससे भी लगभग 15–20 लाख रूपये की कमाई खो दी हैं

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं एक मिनट के लिए इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने पिछली 15 तारीख की मन्थली मीटिंग में भी यह सवाल उठाया था। मैंने इस बात का पता करवाया है। आपको पता है हरियाणा में तो तमाम ट्रान्सपोर्ट नै ानेलाइज्ड है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई परमिट नहीं दिया गया है। हो सकता है राजस्थान सरकार की तरफ से कोई परमिट दिया गया है। (व्यवधान व भाोर)

एक आवाजः यह मनी राम मांगरू का परमिट है जो आपका भाई है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः मैं यह बता रहा हूं कि कौन सा रूट किसने आपरेट करना है और कौन सा टाईम कौन आपरेट करेगा, इस बात का फैसला राजस्थान और हरियाणा सरकार के अधिकारीगण बैठकर करते है। साल के बाद, दो साल के बाद और कई बार तीन साल के बाद यह टाईम बदलते रहते है। कहने का मतलब यह है कि कौन से रूट पर कौन से टाईम पर कौन बस चलायेगा, इस बारे में बाकायदा ऐग्रीमैंट होता है। अगर एक बस इस साल हम 8 बजे चलाते हैं तो अगले साल राजस्थान वाले चलायेंगे। (व्यवधान व भाोर) मैंनं इंक्वायरी की है। मैंने बाकायदा इस बात का पता किया है। अगर यह इस बात को साबित कर दें कि हमने किसी एक इंडीविजुअल को फायदा देने के लिए कोई गलत काम किया है तो मैं दोशी को सजा देने के लिए तैयार हूं।

एक आवाजः आप इंक्वायरी करवाइये।

चौधरी भजन लालः मैंने इंक्वायरी करवा ली है। यह मामला इन्होंने 15 तारीख को मन्थली मीटिंग में भी उठाया था, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः जब लीडर आफ दी हाउस बोल रहे हों, मैं सबसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि कोई इन्ट्रप्ट न करें। मैंने सब को टाईम दिया है। इस बारे में सब को पता है कि दोनों स्टेट्स के अफसरान बैठ कर तय करते हैं कि कौन सा रूट और कौन सा टाईम किस स्टेट ने रन करना है। इसलिए ऐसा इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, उस आदमी के खिलाफ जिसने इनकी चुनाव में मुखालिफत की हो, इस किस्म की बात कहना बड़ी गलत बात है जबकि सरकार ने कानून के मुताबिक काम किया हुआ है।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस को आधा घंटे के लिये और बढा दिया जाये।

आवाजें: हां जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय आधा घंटा बढाया जाता है।

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट) सैंकिड अमैंडमैंट बिल 1982

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhri): Sir, I beg to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है:—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न है:—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र न है:—

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है:—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.00 बजे

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ए.सी. चौधरी): मैं प्रस्ताव करता हूंः—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है:—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

14.02 बजे

(तत्प चात सदन बुधवार, 22 सितम्बर, 1982 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)